



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122024-259755
CG-DL-E-31122024-259755

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 26, 2024/पौष 5, 1946

No. 346]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 26, 2024/PAUSHA 5, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2024

मामला सं.-एडी (ओआई)-6/2023

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 06/06/2023-डीजीटीआर .

1. मैसर्स स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे इसके बाद यहां “आवेदक” अथवा “याचिकाकर्ता” कहा गया है) ने समय समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” भी कहा गया है) और सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, मूल्यांकन और उन पर पाटनरोधी शुल्क का संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे “नियमावली” भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे “प्राधिकारी” भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन.गण. और जापान के मूल के अथवा

वहां से निर्यातित “एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसिस” (जिसे यहां आगे “संबद्ध सामान” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पीयूसी” भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने की मांग करते हुए एक आवेदन/याचिका दायर की।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त *प्रथमदृष्ट्या* साक्ष्यों के आधार पर चीन जन.गण. (जिसे यहां आगे “संबद्ध देश” कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क (एडीडी), जो यदि लगाया जाए और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9(क) के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 29 दिसंबर, 2023 की अधिसूचना फाइल सं. 6/6/2023-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की। यद्यपि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आवेदक ने चीन जन.गण. और जापान को संबद्ध देशों के रूप में प्रस्तावित करते हुए याचिका दायर की है। तथापि, प्राधिकारी ने केवल “चीन जन.गण.” को संबद्ध देश माना है क्योंकि जापान के मामले में पाटन मार्जिन जांच की शुरुआत के समय नकारात्मक नोट किया गया है।

ख. प्रक्रिया

3. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

क. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने की कार्यवाही से पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 29 दिसंबर, 2023 को सार्वजनिक सूचना जारी की।

ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों, आयातक/प्रयोक्ता एसोसिएशनों, घरेलू उद्योग, अन्य ज्ञात भारतीय उत्पादकों और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों/ईमेल के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 29 दिसंबर, 2023 की जांच की शुरुआत की सूचना की प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी गई थी कि वे निर्धारित स्वरूप और तरीके में संगत सूचना दें और नियमावली के नियम 6(2) और 6(4) के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात अनुरोध दें।

घ. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा संबद्ध देश की सरकार को भारत में उसके दूतावास के माध्यम से आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।

ड. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति भी उन्हें संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों के साथ भेजी गई थी।

च. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों और संबंधित मंत्रालय को आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। घरेलू उद्योग और उत्तरदाता निर्यातकों ने ईआईक्यू का उत्तर प्रस्तुत किया था। किसी भी प्रयोक्ता अथवा आयातक ने कोई ईआईक्यू दायर नहीं किया।

छ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी:

- i. जुमेई एक्रिलिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
- ii. अनहुई जिंताओ फोटोइलैक्ट्रिक टेक्नोलॉजी कंपनी
- iii. फोशन ओपाली कम्पोजिट मटेरिया
- iv. सॉलिडटॉप कंपनी लिमिटेड

ज. उत्तर में संबद्ध देश के निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर तथा आर्थिक हित प्रश्नावली भी दायर की:

- i. शांगडोंग केलेसी न्यू मैटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक)
शंघाई सैलिसी इंडस्ट्री डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड शानडोंग ब्रांच (व्यापारी)

झ. उपर्युक्त निर्यातकों के अलावा गुआंगडोंग हंताई डेकोरेशन मैटेरियल कंपनी लिमिटेड द्वारा यह सूचित किया गया है कि दिनांक 22.01.2024 के उनके ईमेल द्वारा कंपनी एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसिस के उत्पादन अथवा निर्यात में नहीं लगी हुई है। दूसरे पक्षकार अर्थात् जिंताओ इंटरनेशनल ग्रुप ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में स्पष्टीकरण मांगे।

ञ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए, भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी:

- i. जैन टिमप्लाई एलएलपी
- ii. प्राइमा मार्केटिंग लिमिटेड
- iii. मेरिनो इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- iv. जाकन इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड
- v. परफार्मेंस स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- vi. गोचे इंटीरियर सॉल्यूशंस
- vii. बंसल सेल्स कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
- viii. सिल्वर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
- ix. संतोष टिम्बर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
- x. ग्लोबंटिस इंटरनेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड
- xi. पटेल वुड सिंडिकेट

- xii. रेहाउ पोलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
- xiii. नेशनल प्लाईवुड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- xiv. अंबिका कारपोरेशन लिमिटेड
- xv. परफार्मेंस स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- xvi. डुपोंट स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

ट. किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने निर्धारित समय सीमा के भीतर उत्तर नहीं दिया और प्रयोक्ता/आयातक प्रश्नावली के कोई उत्तर दायर नहीं किए। तथापि, निम्नलिखित पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में टिप्पणियां दायर की:

ठ. दूसरे पक्षकार अर्थात् रेहायु पोलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड ने जांच में अपनी रुचि व्यक्त की। तथापि, इस पक्षकार द्वारा कोई अनुरोध दायर नहीं किए गए थे।

ड. ऊपर नोट किए गए विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों और आयातकों/प्रयोक्ताओं के अलावा संबद्ध जांच में रुचि मार्बोनेक्स और डुरलैक्स टॉप सर्फेस लिमिटेड द्वारा व्यक्त की गई थी जिन्होंने खुद को भारत में संबद्ध सामानों का उत्पादक होने का दावा किया है। इन पक्षकारों द्वारा प्रश्नावली के कोई उत्तर दायर नहीं किए गए हैं।

ढ. प्राधिकारी ने दिनांक 29 दिसंबर, 2023 की जांच की शुरुआत की अधिसूचना के पैरा 8 द्वारा जांच की शुरुआत के 30 दिन भीतर विचाराधीन उत्पाद (अथवा पीयूसी) के क्षेत्र के संबंध में टिप्पणियां मांगी। तथापि, आवेदक सहित किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा पीसीएन के संबंध में कोई प्रस्ताव/टिप्पणियां दायर नहीं की गई हैं। फिर भी, कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में आवेदक सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों पर पूरी तरह से विचार किए जाने के बाद, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में स्पष्टीकरण 13 फरवरी, 2024 को डीजीटीआर की वेबसाइट पर प्रकाशित सूचना द्वारा सूचित किया गया था। उपर्युक्त नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि क्योंकि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने किसी पीसीएन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं किया है, अतः इस जांच में कोई पीसीएन पद्धति न अपनाए जाने का निर्णय लिया गया है। उसके बाद, सभी हितबद्ध पक्षकारों को ऊपर उल्लिखित सूचना जारी किए जाने की तारीख अर्थात् 13 फरवरी, 2024 से उत्तर दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया था।

ण. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत/दिए गए साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर पक्षकारों को यह निर्देश देकर अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराया कि वे हितबद्ध पक्षकारों की सूची के आधार पर ईमेल द्वारा उन अनुरोधों का आदान-प्रदान करें, संबद्ध जांच के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट पर सभी संगत पक्षकारों को उपलब्ध कराएं।

त. प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा के परिकलन और लेनदेनों की उचित जांच के बाद उसके विश्लेषण के लिए आयात आंकड़ों के डीजीसीआईएंडएस के लेनदेनवार ब्यौरे पर विश्वास किया है।

थ. क्षति रहित कीमत (एनआईपी) सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन के सिद्धांतों और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और निर्माण तथा बिक्री लागत के आधार पर निर्धारित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

वर्तमान जांच के लिए जांच प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2022 से 30 जून, 2023 है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल, 2019 – 31 मार्च, 2020, 1 अप्रैल 2020 – 31 मार्च, 2021, 1 अप्रैल 2021 – 31 मार्च, 2022 और जांच की अवधि शामिल है। वर्तमान जांच में जांच की अवधि में 15 माह शामिल हैं और यह अवधि वर्तमान जांच के तथ्यों में उपयुक्त मानी गई है।

द. आवेदक, संबद्ध देश के उत्तरदाता उत्पादक और निर्यातक और आवश्यक समझी गई सीमा तक अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन प्राधिकारी द्वारा किया गया था। आवश्यक संशोधन/शुद्धि के साथ केवल उस सत्यापित सूचना, जहां कहीं लागू है, पर वर्तमान जांच के लिए विश्वास किया गया है।

ध. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 14 जून, 2024 को हाइब्रिड मोड में आयोजित पहली मौखिक सुनवाई में उनके विचार मौखिक रूप में प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया। मौखिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी पक्षकारों को 21 जून, 2024 तक लिखित अनुरोध दायर करने और उसके बाद प्रति उत्तर यदि कोई है, 28 जून, 2024 तक दायर करने का अवसर प्रदान किया था। प्राधिकारी ने नए निर्दिष्ट प्राधिकारी की नियुक्ति के कारण दूसरी मौखिक सुनवाई आयोजित की और 07-01-2011 को 2006 की सिविल अपील सं. 949 में दिए गए, 'आटोमोटिव टायर मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन (एटीएमए) बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में सभी हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने और उसके बाद लिखित में अनुरोध करने का अवसर दिया गया था। जिन हितबद्ध पक्षकारों ने दूसरी मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उन्हें 24 अक्टूबर, 2024 तक मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने के और उसके बाद 29 अक्टूबर, 2024 तक प्रति उत्तर अनुरोध, यदि कोई है, दायर करने के निदेश दिए गए थे। हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया गया था कि वे उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित अनुरोध का अगोपनीय रूपांतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा करें।

न. प्राधिकारी ने 18 दिसंबर, 2024 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन विवरण परिचालित किया जिसमें केन्द्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी अनिवार्य तथ्य थे। प्राधिकारी ने संगत मानी गई सीमा तक इन अंतिम जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सभी प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की जांच की है। कोई भी अनुरोध जो पूर्व अनुरोध की मात्र पुनरावृत्ति था और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की गई थी, उसे संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।

प. इस जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर वर्तमान जांच में संगत माने गए और साक्ष्य से समर्थित सीमा तक उपयुक्त रूप से विचार किया गया है और अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा उन्हें हल किया गया है।

फ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और वह सूचना गोपनीय मानी गई है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर दें।

ब. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने पहुंच से इंकार किया है अथवा अन्यथा वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना नहीं दी है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार/टिप्पणियां रिकॉर्ड की हैं।

भ. अंतिम जांच परिणाम में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना तथा नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

म. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अम.डा. =81.47 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच की शुरुआत के स्तर पर, विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु निम्नलिखित रूप में परिभाषित किए गए थे:

क. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

3. विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. के मूल का अथवा वहां से निर्यातित "एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसिस" है। एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसिस नॉन-पोरस, कम रखरखाव, मिथाईल मेटाक्रिलेट रेसिन (एमएमए), एल्युमिनियम हाइड्रोऑक्साइड और कच्ची सामग्री के रूप में पिगमेंट्स से उत्पादित मानव निर्मित सामग्री है तथा इसका प्रयोग काउंटर टॉप जैसी सतहों के लिए किया जाता है और पीयरलेस हाइजीन तथा एस्थेटिक गुण-धर्मों के साथ ट्रेन्डी बिल्डिंग मैटेरियल के रूप में लगाया जा सकता है। यह ग्रेनाइट, मार्बल, पत्थर और अन्य प्राकृतिक रूप से होने वाले सामग्री को लामबंद कर सकता है और एक प्रशिक्षित क्राफ्ट्समेन द्वारा जोड़ा जा सकता है जो नजदीक से दिखाई न दे। विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग सीवनहीन काउंटरटाप संस्थापनाओं और आवासीय तथा वाणिज्यिक प्रयोजनों, यथा किचन काउंटरटॉप, सिंक, बाथरूम, फर्नीचर फिटिंग, वाल क्रेडिंग आदि में व्यापक रेंज के अनुप्रयोगों के लिए भी किया जाता है। एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसिस का प्रयोग वाणिज्यिक स्थानों में भी किया जाता है, यथा- कार्यालय, रिटेल आउटलेट, मॉल, होटल और बार, अस्पताल और क्लिनिक आदि।

4. एक्राइलिक सॉलिड सर्फेसिस 6 एमएम, 12 एमएम जैसी मोटाई में सामान्य रूप से, परिष्कृत काउंटरटॉप में निर्माण के लिए 760 एमएमX3660 एमएम आदि जैसे आकारों में शीट फार्म में विशिष्ट रूप से विनिर्मित किए जाते हैं, वे सिंक, शावर पेन और बाथ टब सहित कई आकारों में ढाले भी जा सकते हैं। शीट फार्म में संबद्ध सामान गर्म किए जा सकते हैं और थर्मो फार्मिंग नाम प्रक्रिया का प्रयोग करके त्रि-आयामीय आकारों में मोड़े भी जा सकते हैं जो इस उत्पाद की विश्व उत्पाद की व्यापकता में वृद्धि करता है। प्राकृतिक पत्थरों की तुलना

में संबद्ध सामानों में उपलब्ध अधिक रंग और डिजाइन विकल्प हैं जिसने इस अवधि में संबद्ध सामानों के लिए मांग में योगदान किया है।

5. आयात सूचना के अनुसार उत्पाद विवरण यह दर्शाता है कि आयातकों ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात करते समय 100% एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसेस, प्योर एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसेस, कोरियन शीट्स, हाई मैक्स एक्रिलिक शीट्स, पीएमएमए से बनी मोटेली शीट्स, पीएमएमए में शीट्स, स्टैरोन सॉलिड सर्फेस, क्रियोन मिथाइल मेथाक्रिलिक रेजिन सॉलिड सर्फेस शीट, मिथाइल मेथाक्रिलिक रेजिन शीट्स आदि जैसे विवरणों का प्रयोग किया है।

6. आवेदन पत्र में माने गए अनुसार विचाराधीन उत्पाद में एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसेस शामिल हैं जिनमें उनकी मोटाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है जिनमें मानी गई माप की यूनिट किलोग्राम (केजी) में सूचित उत्पाद का भार है।

7. विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 और कोड 3920 के अन्तर्गत वर्गीकृत है। इस उत्पाद का आयात उप शीर्ष 39205111, 39205119, 39205199, 39206390, 39219039, 39269069 और 35069999 के अन्तर्गत किया गया है। तथापि, यह संभव है कि संबद्ध सामान अन्य शीर्षों के तहत भी आयात किए गए हों और इसीलिए सीमा प्रशुल्क शीट्स केवल संकेतात्मक है और उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं हैं।

ख. समान वस्तु

9. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध सामान, जिनका भारत में पाटन का आरोप लगाया गया है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों के समान है। दोनों उत्पादों की तकनीकी विशिष्टियों, गुणवत्ता, प्रकार्य और अंतिम प्रयोग में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों प्रथमदृष्टया तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थानीय हैं। अतः वर्तमान जांच के लिए भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान संबद्ध देश से आयात किए जा रहे संबद्ध सामानों की 'समान वस्तु' माने जा रहे हैं।

5. जांच की शुरुआत के बाद, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए थे। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों पर गहराई से विचार करने के बाद दिनांक 13 फरवरी, 2024 की सूचना द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि निम्नलिखित उत्पाद वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल नहीं हैं।

- क) प्योर एक्रिलिक शीट्स।
- ख) फर्नीचर की सजावट और वाहनों की रैपिंग के लिए एक्रिलिक लेमिनेट्स तथा पीईटी/पीवीसी फिल्म।
- ग) पोलिएस्टर सॉलिड सर्फेस शीट्स।
- घ) संशोधित एक्रिलिक सॉलिड सर्फेस।

6. डीजीटीआर की वेबसाइट पर प्रकाशित दिनांक 13 फरवरी, 2024 की सूचना में यह भी उल्लेख किया गया था कि किसी को हटाने की विशिष्टता पूरी जांच प्रक्रिया में निर्धारण के अध्यक्षीन हैं और प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त माने जाने पर अंतिम जांच परिणाम में सूचित की जाएगी। अतः, अंतिम जांच परिणाम में विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में जांच के दौरान एकत्रित सभी संगत तथ्य शामिल हैं जो प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्धारणों का आधार बनेंगे।

ग.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

7. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में स्पष्टीकरण कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा मांगे गए हैं। पक्षकारों ने इस पर स्पष्टीकरण मांगा कि क्या निम्नलिखित उत्पाद विचाराधीन उत्पाद क्षेत्र में शामिल हैं अथवा नहीं।

क) प्योर एक्रिलिक शीट, वर्णित एक्रिलिक सॉलिड सर्फेस (पीयूसी) से भिन्न होने का दावा किया गया जो विभिन्न पदार्थों से निर्मित मिश्रण सामग्री है।

ख) फर्नीचर की सजावट और वाहन रैपिंग के लिए एक्रिलिक लेमिनेट और पीईटी/पीवीसी फिल्म जिसे भौतिक गुण-धर्मों और अनुप्रयोग परिदृश्यों के कारण भिन्न होने का दावा किया गया है।

ग) पोलिएस्टर सॉलिड सर्फेस शीट्स, जिसे उनके रेजिन सम्मिश्रण और बाजार अनुप्रयोगों के कारण भिन्न होने का दावा किया गया है।

घ) संशोधित एक्रिलिक सॉलिड सर्फेस जिसे कच्ची सामग्री मिश्रण, भौतिक गुण-धर्मों और निष्पादन विशेषताओं में अंतर के कारण भिन्न होने का दावा किया गया है।

ii. मार्बोनेक्स ने अनसिचुरेटेड पोलिएस्टर और एक्रिलिक सॉलिड सर्फेस शीट्स का भारतीय उत्पादक होने का दावा करते हुए अनुरोध किया कि चीन से अनसिचुरेटेड पोलिएस्टर और एक्रिलिक सॉलिड सर्फेस शीट्स के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

iii. मार्बोनेक्स ने यह भी अनुरोध किया कि 'पोलिएस्टर सॉलिड सर्फेस शीट्स' और 'मोडिफाइड एक्रिलिक सॉलिड सर्फेस' की वही विशेषताएं हैं जो वर्तमान में विचाराधीन उत्पाद अर्थात् "एक्रिलिक सॉलिड सर्फेस शीट्स" की हैं। दोनों उत्पाद इंटीरियर तथा वास्तु संबंधी प्रयोजन से संबंधित समान अंतिम प्रयोग के अंतिम प्रयोक्ता के अनुप्रयोगों में कार्य करते हैं। चीन से पोलिएस्टर सॉलिड सर्फेस शीट्स और मोडिफाइड एक्रिलिक सॉलिड सर्फेस का पर्याप्त आयात घरेलू उत्पादकों को काफी चुनौती देता है जिससे हमारे लिए अपनी उत्पादन लागतें शामिल करना अत्यधिक कठिन हो रहा है। अतः, 'पोलिएस्टर सॉलिड सर्फेस शीट्स और मोडिफाइड एक्रिलिक सॉलिड सर्फेस' भी जांच का भाग बनाया जाना चाहिए।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

8. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. के मूल का अथवा वहां से निर्यातित “एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसेस” है।
- ii. एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसेस नॉन-पोरस, कम रखरखाव, मिथाइल मेटाक्रिलेट रेसिन (एमएमए), एल्युमिनियम हाइड्रोऑक्साइड और कच्ची सामग्री के रूप में पिगमेंट्स से उत्पादित मानव निर्मित सामग्री है तथा इसका प्रयोग काउंटर टॉप जैसी सतहों के लिए किया जाता है और पीयरलेस हाइजीन तथा एसथेटिक गुण-धर्मों के साथ ट्रेन्डी बिल्डिंग मैटेरियल के रूप में लगाया जा सकता है। यह ग्रेनाइट, मार्बल, पत्थर और अन्य प्राकृतिक रूप से होने वाले सामग्री को लामबंद कर सकता है और एक प्रशिक्षित क्राफ्ट्समेन द्वारा जोड़ा जा सकता है जो नजदीक से दिखाई न दे।
- iii. विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग सीवनहीन काउंटरटाप संस्थापनाओं और आवासीय तथा वाणिज्यिक प्रयोजनों, यथा किचन काउंटरटाप, सिंक, बाथरूम, फर्नीचर फिटिंग, वाल क्रेडिंग आदि में व्यापक रेंज के अनुप्रयोगों के लिए भी किया जाता है। एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसेस का प्रयोग वाणिज्यिक स्थानों में भी किया जाता है, यथा- कार्यालय, रिटेल आउटलेट, मॉल, होटल और बार, अस्पताल और क्लिनिक आदि।
- iv. एक्राइलिक सॉलिड सर्फेसेस 6 एमएम, 12 एमएम जैसी मोटाई में सामान्य रूप से, परिष्कृत काउंटरटाप में निर्माण के लिए 760 एमएमX3660 एमएम आदि जैसे आकारों में शीट फार्म में विशिष्ट रूप से विनिर्मित किए जाते हैं, वे सिंक, शावर पेन और बाथ टब सहित कई आकारों में ढाले भी जा सकते हैं।
- v. शीट फार्म में संबद्ध सामान गर्म किए जा सकते हैं और थर्मो फार्मिंग नामक प्रक्रिया का प्रयोग करके त्रि-आयामीय आकारों में मोडे भी जा सकते हैं जो इस उत्पाद की विश्व उत्पाद की व्यापकता में वृद्धि करता है। प्राकृतिक पत्थरों की तुलना में संबद्ध सामानों में उपलब्ध अधिक रंग और डिजाइन विकल्प हैं जिसने इस अवधि में संबद्ध सामानों के लिए मांग में योगदान किया है।
- vi. आयात सूचना के अनुसार उत्पाद विवरण यह दर्शाता है कि आयातकों ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात करते समय 100% एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसेस, प्योर एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसेस, कोरियन शीट्स, हाई मैक्स एक्रिलिक शीट्स, पीएमएमए से बनी मॉटेली शीट्स, पीएमएमए में शीट्स, स्टैरोन सॉलिड सर्फेस, क्रियोन मिथाइल मेटाक्रिलिक रेजिन सॉलिड सर्फेस शीट, मिथाइल मेटाक्रिलिक रेजिन शीट्स आदि जैसे विवरणों का प्रयोग किया है। प्राधिकारी इन सभी विवरणों और नामों पर विचाराधीन उत्पाद के भाग के रूप में विचार कर सकते हैं।

vii. आवेदन पत्र में माने गए अनुसार विचाराधीन उत्पाद में एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसेस शामिल हैं जिनमें उनकी मोटाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है जिनमें मानी गई माप की यूनिट किलोग्राम (केजी) में सूचित उत्पाद का भार है।

viii. विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 और कोड 3920 के अन्तर्गत वर्गीकृत है। इस उत्पाद का आयात उप शीर्ष 39205111, 39205119, 39205199, 39206390, 39219039, 39269069 और 35069999 के अन्तर्गत किया गया है। तथापि, यह संभव है कि संबद्ध सामान अन्य शीर्षों के तहत भी आयात किए गए हों और इसीलिए सीमा प्रशुल्क शीट्स केवल संकेतात्मक है और उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं हैं।

ix. क) प्योर एक्रिलिक शीट्स, ख) एक्रिलिक लेमिनेट्स और फर्नीचर सजावट तथा वाहन रेपिंग के लिए पीईटी/पीवीसी फिल्म, ग) पोलिएस्टर सॉलिड सर्फेस शीट्स, घ) मोडिफाइड एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसेस से संबंधित कुछ पक्षकारों द्वारा मांगे गए विचाराधीन उत्पाद के संबंध में स्पष्टीकरण के बारे में आवेदक का अनुरोध है कि आवेदन पत्र में दिए गए विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में ये उत्पाद शामिल नहीं हैं। अतः, यह नोट किया जा सकता है कि ये उत्पाद, विचाराधीन उत्पाद के भाग नहीं हैं। विचाराधीन उत्पाद में एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसेस है जिसमें एमएमए/पीएमएमए रेसिन उसके प्रमुख इनपुट के रूप में है और जिस उत्पाद के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है उसमें प्रमुख इनपुट के रूप में अन्य रेसिन हैं।

x. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में पोलिएस्टर सॉलिड सर्फेस शीट्स/अनसिचुरेटेड पोलिएस्टर शीट्स और मोडिफाइड एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसेस शामिल करने के लिए कुछ अन्य घरेलू उत्पादकों के अनुरोध के संबंध में, हमारा अनुरोध है कि 'समान वस्तु' को नियंत्रित करने वाली नियमावली के अनुसार ये उत्पाद संबद्ध सामान की 'समान वस्तु' नहीं है और मूल कच्ची सामग्री, अंतर निहित उत्पाद गुण-धर्मों और लागत तथा कीमत के संदर्भ में उत्पाद में अंतर है, यद्यपि कुछ मामलों में उत्पाद की तुलनीय भौतिक दृश्यता के साथ किसी सीमा तक अंतिम प्रयोग अतिव्यापन कर सकते हैं। मोडिफाइड एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसेस संबद्ध सामानों से काफी सस्ता होने का अनुमान है (40-50% सस्ता) और वे तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से स्पष्ट रूप से भिन्न वस्तु हैं। संबद्ध सामानों में उनकी प्रमुख कच्ची सामग्री के रूप में एमएमए/पीएमएमए रेसिन हैं जबकि मोडिफाइड एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसेस अन्य सस्ती रेसिन का प्रयोग करता है जो समग्र उत्पाद मिश्रण और गुण-धर्मों को प्रभावित करता है। यहां तक कि यदि एमएमए/पीएमएमए मोडिफाइड एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसेस में प्रयुक्त किए जाने का दावा किया जाए तो उसका संकेन्द्रण 1-10% से अधिक नहीं हो सकता जबकि सामान्यतः 40-45% की रेंज में होता है। विचाराधीन उत्पाद में मोडिफाइड एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसेस को शामिल करने से उत्पाद तुलनाएं समाप्त हो जाएंगी और साथ ही पाटन और क्षति मार्जिन का निर्धारण भी विकृत हो जाएगा क्योंकि मोडिफाइड एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसेस संबद्ध सामानों की तुलना में उसकी प्रकृति से काफी सस्ता उत्पाद है।

xi. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में मोडिफाइड एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसेस को शामिल करने के लिए कुछ भारतीय उत्पादकों के दावे के संबंध में, संबद्ध सामानों की समान वस्तु के रूप में मोडिफाइड एक्रिलिक सॉलिड

सर्फेसेस का दावा करने वाले किसी भी पक्षकार को निःसंदेह यह दर्शाना चाहिए कि मोडिफाइड एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसेस संबद्ध सामानों की समान वस्तु है। ऐसा न दर्शाए जाने की स्थिति में इस दावे का कोई अर्थ नहीं है। यद्यपि आवेदक को उसे शामिल किए जाने अथवा हटाए जाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह, संबद्ध सामानों और पोलिएस्टर अथवा अनसिचुरेटेड पोलिएस्टर के बीच कोई तुलनीयता नहीं है, जिसे कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किया जा सके।

xii. यह भी अनुरोध है कि यहां तक कि यद्यपि मोडिफाइड एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसेस आवेदक की समझ के अनुसार वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु नहीं है, तथापि एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसेस पर किसी शुल्क से बचने के लिए मोडिफाइड एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसेस के रूप में संबद्ध सामानों की गलत घोषणा करने वाले किसी आयातक के उदाहरण नकारे नहीं जा सकते और उस मामले में आवेदक को शुल्कों की प्रवंचना, यदि कोई है, के ऐसे किसी प्रयास के विरुद्ध आवेदक को उपयुक्त कार्यवाही की मांग करने के लिए प्राधिकारियों के पास जाने का अधिकार है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

9. विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. के मूल का अथवा वहां से निर्यातित “एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसिस” है। एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसिस नॉन-पोरस, कम रखरखाव, मिथाईल मेटाक्रिलेट रेसिन (एमएमए), एल्युमिनियम हाइड्रोऑक्साइड और कच्ची सामग्री के रूप में पिगमेंट्स से उत्पादित मानव निर्मित सामग्री है तथा इसका प्रयोग काउंटर टॉप जैसी सतहों के लिए किया जाता है और पीयरलेस हाइजीन तथा एसथेटिक गुण-धर्मों के साथ ट्रेंडी बिल्डिंग मैटेरियल के रूप में लगाया जा सकता है। यह ग्रेनाइट, मार्बल, पत्थर और अन्य प्राकृतिक रूप से होने वाले सामग्री को लामबंद कर सकता है और एक प्रशिक्षित क्राफ्ट्समेन द्वारा जोड़ा जा सकता है जो नजदीक से दिखाई न दे। विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग सीवनहीन काउंटरटाप संस्थापनाओं और आवासीय तथा वाणिज्यिक प्रयोजनों, यथा किचन काउंटरटॉप, सिंक, बाथरूम, फर्नीचर फिटिंग, वाल क्रेडिंग आदि में व्यापक रेंज के अनुप्रयोगों के लिए भी किया जाता है। एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसिस का प्रयोग वाणिज्यिक स्थानों में भी किया जाता है, यथा- कार्यालय, रिटेल आउटलेट, मॉल, होटल और बार, अस्पताल और क्लिनिक आदि।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि निम्नलिखित उत्पाद वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल नहीं हैं:

क) प्योर एक्रिलिक शीट्स।

ख) फर्नीचर की सजावट और वाहनों की रैपिंग के लिए एक्रिलिक लेमिनेट्स तथा पीईटी/पीवीसी फिल्म।

ग) पोलिएस्टर सॉलिड सर्फेस शीट्स।

घ) संशोधित एक्रिलिक सॉलिड सर्फेस।

11. एक्राइलिक सॉलिड सर्फेसिस 6 एमएम, 12 एमएम जैसी मोटाई में सामान्य रूप से, परिष्कृत काउंटरटॉप में निर्माण के लिए 760 एमएमX3660 एमएम आदि जैसे आकारों में शीट फार्म में विशिष्ट रूप से विनिर्मित किए जाते हैं, वे सिंक, शावर पेन और बाथ टब सहित कई आकारों में ढाले भी जा सकते हैं। शीट फार्म में संबद्ध सामान गर्म किए जा सकते हैं और थर्मो फार्मिंग नाम प्रक्रिया का प्रयोग करके त्रि-आयामीय आकारों में मोडे भी जा सकते हैं जो इस उत्पाद की विश्व उत्पाद की व्यापकता में वृद्धि करता है। प्राकृतिक पत्थरों की तुलना में संबद्ध सामानों में उपलब्ध अधिक रंग और डिजाइन विकल्प हैं जिसने इस अवधि में संबद्ध सामानों के लिए मांग में योगदान किया है।
12. आयात सूचना के अनुसार उत्पाद विवरण यह दर्शाता है कि आयातकों ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात करते समय 100% एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसेस, प्योर एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसेस, कोरियन शीट्स, हाई मैक्स एक्रिलिक शीट्स, पीएमएमए से बनी मोटेली शीट्स, पीएमएमए में शीट्स, स्टैरोन सॉलिड सर्फेस, क्रियोन मिथाइल मेथाक्रिलिक रेजिन सॉलिड सर्फेस शीट, मिथाइल मेथाक्रिलिक रेजिन शीट्स आदि जैसे विवरणों का प्रयोग किया है। ये प्रयुक्त वैकल्पिक नाम संबद्ध सामानों के विवरण का भाग है।
13. आवेदन पत्र में माने गए अनुसार विचाराधीन उत्पाद में एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसेस शामिल हैं जिनमें उनकी मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, रंग और डिजाइन पर ध्यान नहीं दिया जाता है और मानी गई माप की यूनिट किलोग्राम/टन (किलोग्राम/मी.ट.) में सूचित उत्पाद का भार है।
14. विचाराधीन उत्पाद उसके प्लास्टिक और वस्तुओं से संबंधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 और उप शीर्ष 392051 के अन्तर्गत वर्गीकृत है जो पोली (मिथाइल मेथाक्रिलेट) शीट से संबंधित है जो संबद्ध सामानों के लिए समर्थित वर्गीकरण नहीं है। संबद्ध सामानों के आयात आवेदन पत्र में दावा किए गए अनुसार उप शीर्ष 39205111, 39205119, 39205199, 39206390, 39219039, 39269069 और 35069999 के अन्तर्गत सूचित किए गए हैं। सीमा प्रशुल्क शीट्स केवल संकेतात्मक है और उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं हैं।
15. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों पर भी विचार किया है और रिकॉर्ड में उपलब्ध संगत सूचना के आधार पर तथा आवश्यक पाए गए अनुसार हितबद्ध पक्षकारों से और सूचना मंगाकर उसकी जांच की है।
16. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में स्पष्टीकरण के बारे में, जैसाकि प्योर एक्रिलिक शीट्स, एक्रिलिक लेमिनेट्स और फर्नीचर सजावट तथा वाहन रेपिंग के लिए पीईटी/पीवीसी फिल्म, पोलिएस्टर सॉलिड सर्फेस शीट्स और मोडिफाइड एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसेस से संबंधित कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा मांग की गई है, इसकी पुष्टि की जाती है कि ये उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के भाग नहीं हैं। जैसा कि आवेदक द्वारा स्पष्ट किया गया है, यद्यपि संबद्ध सामानों में मिथाइल मेथाक्रिलेट (एमएमए)/पोली-मिथाइल मेथाक्रिलेट (पीएमएमए) रेजिन, जिसे प्रमुख कच्ची सामग्री के रूप में एक्रिलिक रेसिन भी कहा जाता है, तथापि उपलब्ध तथ्य यह नहीं दर्शाते कि प्योर एक्रिलिक शीट्स, एक्रिलिक लेमिनेट्स और फर्नीचर सजावट तथा वाहन रेपिंग के लिए पीईटी/पीवीसी फिल्म

और पोलिएस्टर सॉलिड सर्फेस शीट्स ने भी उसकी कच्ची सामग्री के रूप में एमएमए/पीएमएमए है। इस प्रकार, ये उत्पाद संबद्ध सामानों के क्षेत्र में नहीं आते।

17. साथ ही उपलब्ध तथ्य यह बताते हैं कि मोडिफाइड एक्रिलिक सॉलिड सर्फेस में मूल कच्ची सामग्री, अंतरनिहित उत्पाद गुण-धर्मों और लागत तथा कीमत की दृष्टि से अंतर है। यद्यपि अंतिम प्रयोग कुछ सीमा तक संबद्ध सामानों में अतिव्यापन कर सकते हैं। मोडिफाइड एक्रिलिक सॉलिड सर्फेस संबद्ध सामानों से काफी सस्ता होने का अनुमान है (40-50% सस्ता) यह प्राथमिक कारणों से है संबद्ध सामानों में उनकी प्रमुख कच्ची सामग्री के रूप में एमएमए/पीएमएमए रेसिन हैं जबकि मोडिफाइड एक्रिलिक सॉलिड सर्फेस अन्य सस्ती रेसिन का प्रयोग करता है जो समग्र उत्पाद मिश्रण और गुण-धर्मों को प्रभावित करता है और साथ उत्पाद की लागत और कीमत को भी प्रभावित करता है। जैसा कि आवेदक द्वारा सुनिश्चित किया गया है यहां तक कि यदि एमएमए/पीएमएमए मोडिफाइड एक्रिलिक सॉलिड सर्फेस में प्रयुक्त किए जाने का दावा किया जाए तो उसका संकेन्द्रण 1-10% से अधिक नहीं हो सकता जबकि एक्रिलिक सॉलिड सर्फेस में एमएमए/पीएमएमए संकेन्द्रण सामान्यतः 40-45% की रेंज में होता है। संबद्ध सामान उनकी मोडे जाने की योग्यता में विशिष्ट है और कई आकारों में ढाले जा सकते हैं। मोडिफाइड एक्रिलिक शीट्स में शून्य से बहुत कम मोडे जाने तक की क्षमता है। इस प्रकार मोडिफाइड एक्रिलिक सॉलिड सर्फेस विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में नहीं है।

18. कुछ पक्षकारों द्वारा मोडिफाइड एक्रिलिक सॉलिड सर्फेस को भी विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किए जाने के अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह दावा सिद्ध नहीं है। इसके विपरीत, उपलब्ध तथ्य संबद्ध सामानों और मोडिफाइड एक्रिलिक सॉलिड सर्फेस के बीच मूल अंतर बताते हैं, जैसा कि यहां ऊपर नोट किया गया है। अतः, मोडिफाइड एक्रिलिक सॉलिड सर्फेस को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल करना स्वीकार नहीं किया जाता है।

19. अनसिचुरेटेड पोलिएस्टर और पोलिएस्टर सॉलिड सर्फेस शीट को भी विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल करने के अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि दावेदार भारतीय उत्पादक ने इन दावों को सिद्ध नहीं किया है और अनुरोध में औचित्य नहीं है। किसी भी दशा में यह नोट किया जाता है कि अनसिचुरेटेड पोलिएस्टर और पोलिएस्टर सॉलिड सर्फेस शीट स्पष्ट रूप से पोलिएस्टर आधारित उत्पाद हैं जबकि संबद्ध सामान एमएमए/पीएमएमए रेसिन आधारित उत्पाद हैं।

20. समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार प्रवधान है:-

“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

21. रिकॉर्ड में सूचना पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित सामान नियमावली के अनुसार समान वस्तु हैं। दोनों

तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के क्षेत्र और अभिप्राय में संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु हैं।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

22. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर किए गए अनुरोध घरेलू उद्योग और आधार के पहलू पर अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- i. जांच की शुरुआत की अधिसूचना यह बताती है कि याचिकाकर्ता का संबद्ध सामानों का भारतीय उत्पादन 80% है। यह विवरण सही नहीं है।
- ii. याचिकाकर्ता का उत्पादन भारत में एक्रिलिक सॉलिड सर्फेस के कुल उत्पादन के 75-80% के निकट नहीं है। इसके बताए, डुरेक्स टॉप सर्फेस लिमिटेड (मुंबई) सॉलिड सर्फेस व्यापार में सबसे बड़ा व्यापारी है। डुरेक्स की 200000 शीट्स की क्षमता है जो याचिकाकर्ता की क्षमता का लगभग दुगुना है।
- iii. याचिकाकर्ता ने प्राधिकारी को याचिकाकर्ता को पात्र घरेलू उद्योग मानने के लिए भ्रामक सूचना दी है। प्राधिकारी को डुरेक्स टॉप सर्फेस लिमिटेड से आवश्यक सूचना मंगाना और तदनुसार घरेलू उद्योग के आधार की जांच करना अपेक्षित है।
- iv. प्राधिकारी को घरेलू उद्योग से भारत में संबद्ध सामानों का कुल उत्पादन अन्य पक्षकारों को देने के लिए कहना चाहिए।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

23. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. आवेदक अर्थात् स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत में संबद्ध सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक है और संबद्ध सामानों के कुल भारतीय उत्पादन में उसका प्रमुख अनुपात है। आवेदक ने क्षति की अवधि में संबद्ध देश से संबद्ध उत्पाद का आयात नहीं किया और न ही वह संबद्ध उत्पाद के किसी निर्यातक/आयातक से संबद्ध है। अतः प्राधिकारी वर्तमान जांच के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत आवेदक को पात्र घरेलू उद्योग माने।
- ii. भारत में संबद्ध सामानों के पांच अन्य उत्पादक हैं अर्थात् 1) डुरेक्स टॉप सर्फेस लिमिटेड, 2) मार्बोनेक्स, 3) बरोदा मोनोसोल सर्फेस इंडिया एलएलपी, 4) रिकोरियन शगुन पोलिमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और 5) डेनोलेक्स पोलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड। मार्बोनेक्स ने जांच की शुरुआत के बाद प्राधिकारी को एक पत्र में खुद को भारत में संबद्ध सामानों का उत्पादक घोषित किया है, यद्यपि आवेदन-पत्र के समय यह उत्पादक आवेदक की जानकारी में नहीं था।

- iii. 5 अन्य भारतीय उत्पादकों में से, डुरेक्स टॉप सर्फेस लिमिटेड और मार्बोनेक्स ने आवेदन पत्र और संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का समर्थन किया है।
- iv. आवेदक ने अपनी बाजार सूचना के अनुसार कुल भारतीय उत्पादन का अनुमान लगाया है क्योंकि अन्य ज्ञात भारतीय उत्पादकों द्वारा संबद्ध सामानों के उत्पादन संबंधी सूचना किसी अन्य सरकारी अथवा प्रकाशित स्रोतों से उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार निर्धारित कुल भारतीय उत्पादन में आवेदक का हिस्सा 70-80% की रेंज में है और नियम 5(3) के साथ पठित नियम 2(ख) की अपेक्षाएं पूरा करता है।
- v. किसी भी अन्य पक्षकार द्वारा दिए गए कुल भारतीय उत्पादन संबंधी कोई वैकल्पिक सूचना नहीं है। ऐसी सूचना के अभाव में, आवेदक द्वारा दावा किए गए अनुसार कुल भारतीय उत्पादन विश्वसनीय साक्ष्य बनता है।
- vi. उत्तरदाता निर्यातक ने आवेदक द्वारा दावा किए गए आधार पर विवाद किया है, परंतु टन/कि.ग्रा. के संदर्भ में “एक्रिलिक सॉलिड सर्फेस” के कुल भारतीय उत्पादन के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है। निर्यातक ने आरंभ में दावा किया कि दूसरे उत्पादक अर्थात् डुरेक्स टॉप सर्फेस लिमिटेड में 2 लाख की क्षमता है और बाद में यह उल्लेख किया गया है कि उसी उत्पादक के पास “सॉलिड सर्फेस” का उत्पादन करने के लिए 120000 पीसों की क्षमता है। यह नोट किया जाना चाहिए कि डुरेक्स टॉप सर्फेस प्राइवेट लिमिटेड ने वर्तमान जांच का समर्थन किया है। साथ ही, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत आधार क्षमता का प्रकार्य नहीं है और आधार जांच की अवधि में भारतीय उत्पादकों द्वारा उत्पादन के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। डुरेक्स टॉप सर्फेस प्राइवेट लिमिटेड की क्षमता के संबंध में भी उनकी वेबसाइट से यह नोट किया जा सकता है कि उनकी वेबसाइट पर सूचित क्षमता एक्रिलिक सॉलिड सर्फेस तथा मोडिफाइड एक्रिलिक सॉलिड सर्फेस के लिए है जो कि गैर-विचाराधीन मद है परंतु निर्यातक ने यह बताने का प्रयास किया है कि यह पूरी क्षमता एक्रिलिक सॉलिड सर्फेस की है।
- vii. दूसरी सुनवाई के बाद और प्राधिकारी के साथ इस संबंध में चर्चा के मुद्दों के आधार पर आवेदक ने हिसाब लगाया है कि क्या संबद्ध सामानों का भारतीय उत्पादन कुछ सरकारी अथवा अन्य स्रोतों से उपलब्ध है। आवेदक ने अनुमानों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए अपने अनुमानों को पुनः भी देखा। इन सभी प्रयासों के बाद यह अनुरोध है कि ऐसी कोई प्रकाशित अथवा संकलित सूचना उपलब्ध नहीं है और आवेदक कुल भारतीय उत्पादन का माप करने के लिए अपने अनुमानों पर विश्वास करने के लिए विवश है।
- viii. यह माना जाना चाहिए कि वर्तमान जांच की शुरुआत से लगभग 10 माह हो गए हैं और आवेदक द्वारा दावे अन्य सभी पक्षकारों को व्यापक रूप से परिचालित किए गए हैं परंतु आज की तारीख तक कोई भी अन्य पक्षकार कुल भारतीय उत्पादन के संबंध में आवेदक के दावों का खंडन करने के लिए कोई विश्वसनीय सूचना नहीं दे पाया। यहां तक कि इस संबंध में विरोधी उत्पादक से आए विरोध असंगत हैं और निर्यातक संबद्ध सामानों के उत्पादन ब्यौरे नहीं दे पाया।
- ix. साथ ही, समर्थक उत्पादों तथा अन्य भारतीय उत्पादकों ने, आवेदक द्वारा किए गए भारतीय उत्पादन के अनुमानों पर विवाद नहीं किया है जो यह दर्शाता है कि आवेदक द्वारा किए गए अनुमान विश्वसनीय हैं।

- x. इस प्रकार, याचिकाकर्ता संबद्ध सामानों के संबंध में घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने के लिए नियम 2(ख) के तहत मानदंड पूरे करता है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

24. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

“(ख) घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

25. यह नोट किया जाता है कि आवेदन पत्र मैसर्स स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि आवेदक ने जांच/क्षति की अवधि में संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया और संबद्ध उत्पाद के किसी निर्यातक/आयातक से भी संबद्ध नहीं हैं।

- 26 आवेदक ने दावा किया है कि उनके द्वारा संबद्ध सामानों का उत्पादन का पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के साथ पठित नियम 2(ख) में परिकल्पितानुसार भारत में संबद्ध सामानों के कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है। आवेदक ने यह भी दावा किया कि वे भारत में संबद्ध सामानों के सबसे बड़े उत्पादक हैं।

27. आवेदक द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि आवेदक को छोड़कर भारत में संबद्ध सामानों के 5 और अन्य उत्पादक हैं जिससे भारत में संबद्ध सामानों के लिए कुल भारतीय उत्पादकों की संख्या 6 हो जाती है।

28. आवेदक ने अन्य ज्ञात भारतीय उत्पादकों, अनुमानित आधार पर उनके उत्पादन, प्रोद्ध भवन आधार पर आवेदक द्वारा उत्पादन, संबद्ध सामानों के कुल घरेलू उत्पादन में प्रत्येक ज्ञात उत्पादक के हिस्से और आवेदन-पत्र/जांच के समर्थन अथवा विरोध के स्तर के ब्यौरे संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

संबद्ध सामानों का घरेलू उत्पादन – किलो ग्राम में मात्रा						
क्र.सं.	कंपनी का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि (अप्रैल 2022 से जून 2023)	उत्पादक का स्तर
1	स्टाइलम इंडस्ट्रीज लि.	***	***	***	***	आवेदक

2	डुरलैक्स टॉप सर्फेस लिमिटेड	***	***	***	***	समर्थक
3	मार्बोनेक्स	***	***	***	***	समर्थक
4	बड़ोदा मोनोसोल सर्फेस इंडिया एलएलपी	***	***	***	***	निष्क्रिय
5	रिकोरियन शगुन पोलिमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	***	***	***	***	निष्क्रिय
6	डेनोलेक्स पोलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड	***	***	***	***	निष्क्रिय
7	कुल	***	***	***	***	
8	कुल भारतीय उत्पादन में आवेदक का हिस्सा - %	***	***	***	***	अपेक्षित आरंभिक से अधिक
9	रेंज	60-70%	65-75%	70-80%	75-85%	अपेक्षित आरंभिक से अधिक
10	कुल भारतीय उत्पादन में समर्थकों सहित आवेदक का हिस्सा -%	***	***	***	***	अपेक्षित आरंभिक से अधिक
11	रेंज	75-85%	80-90%	85-95%	85-95%	अपेक्षित आरंभिक से अधिक

29. ऊपर नोट किए गए अनुसार, 5 अन्य उत्पादकों में डुरेक्स टॉप सर्फेस लिमिटेड और मार्बोनेक्स ने प्राधिकारी को आवेदन-पत्र/वर्तमान जांच के लिए अपना समर्थन सूचित किया है और चीन जन.गण. से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है तथा उल्लेख किया कि इन आयातों से उनका निष्पादन प्रभावित हुआ है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि समर्थन की अभिव्यक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित स्वरूप और तरीके में नहीं है और नहीं उनको हुई क्षति मापने के लिए कोई सूचना प्रस्तुत की गई है। अन्य 3 उत्पादकों अर्थात् बड़ोदा मोनोसोल सर्फेस इंडिया एलएलपी, रिकोरियन शगुन पोलिमर्स इंडिया प्राइवेट

लिमिटेड और डेनोलेक्स पोलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड ने वर्तमान जांच का न तो समर्थन किया है और न विरोध किया है।

30. प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों के सभी ज्ञात भारतीय उत्पादकों को निर्धारित स्वरूप और तरीके में वर्तमान जांच के लिए संबद्ध सूचनाएं प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखा। परंतु उन उत्पादकों से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। यद्यपि उत्तरदाता निर्यातकों ने आवेदक द्वारा किए गए आधार के दावों पर विवाद किया है, तथापि कुल घरेलू उत्पादन के संबंध में उन पक्षकारों द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई। निर्यातकों ने तर्क दिया है कि भारतीय उत्पादक अर्थात् डुरलैक्स टॉप सर्फेस लिमिटेड के पास संबद्ध सामानों के पास 2 लाख पीसों का उत्पादन करने की क्षमता है। तथापि, जांच की अवधि के दौरान उपर्युक्त पक्षकार द्वारा संबद्ध सामानों के उत्पादन संबंधी कोई सूचना निर्यातकों द्वारा नहीं दी गई है। डुरलैक्स टॉप सर्फेस लिमिटेड की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्यातकों द्वारा किया गया अनुरोध निम्नलिखित है:

“डुरलैक्स टॉप सर्फेस लिमिटेड 10 से अधिक वर्षों से सॉलिड सर्फेस व्यापार में लगा हुआ है। हमारे अंतिम ग्राहक और चैनल भागीदारों के साथ उत्कृष्ट संतुष्टि दर के साथ दो लोकप्रिय ब्रांड लक्सर (एक्रिलिक यूवी सॉलिड सर्फेस) और एसपिरन(मोडिफाइड सॉलिड सर्फेस) सिद्ध होने पर..... हमारे पास 200000 शीटें उत्पादित करने की वार्षिक क्षमता है”।

31. उपर्युक्त सूचना दर्शाती है कि डुरलैक्स टॉप सर्फेस लिमिटेड एक बहु-उत्पाद कंपनी है और दावेदार निर्यातकों ने यह नहीं दर्शाया है कि कंपनी की वेबसाइट पर उल्लिखित क्षमता संबद्ध सामानों से संबंधित ही है। जैसा कि नोट किया गया है, डुरलैक्स टॉप सर्फेस लिमिटेड ने जांच का समर्थन किया है, यद्यपि नोट किए गए अनुसार निर्धारित स्वरूप और तरीके में नहीं किया। संबद्ध सामानों के कुल घरेलू उत्पादन संबंधी किसी अन्य सूचना के अभाव में प्राधिकारी संबद्ध सामान के घरेलू उत्पादन को मापने और इस जांच में आधार के निर्धारण के लिए भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विश्वास करते हैं। उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि संबद्ध सामानों के घरेलू उत्पादन में आवेदक का प्रमुख अनुपात है और हिस्सा ***% है जो नियमावली के नियम 5(3) के साथ पठित नियम 2(ख) के तहत अपेक्षित आरंभिक स्तर से अधिक है। यह भी नोट किया जाता है कि आवेदक संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबद्ध नहीं है।

32. अतः रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर ध्यान देते हुए, प्राधिकारी नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से आवेदक/याचिकाकर्ता को पात्र घरेलू उद्योग मानते हैं और यह कि आवेदन पत्र नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंड पूरा करता है।

ड. गोपनीयता संबंधी मुद्दे

ड.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

33. गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. याचिका का अगोपनीय रूपांतर याचिका में निहित आरोपण की उपयुक्त समझ नहीं देता।

- ii. याचिका का अगोपनीय रूपांतर नियमावली के नियम 7 और महानिदेशक द्वारा जारी दिनांक 09 दिसंबर, 2013 की व्यापार सूचना सं. 1/2023 में निर्धारित मानकों को पूरा करने में विफल रहता है।
- iii. याचिकाकर्ता ने वर्तमान जांच की शुरुआत के लिए आधार के रूप में प्रयुक्त आयात सूचना के स्रोत का नाम भी प्रकट न कर अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। याचिकाकर्ता ने न तो आयात आंकड़ों का स्रोत उल्लिखित किया है न ही उसे गोपनीय होने का कोई कारण दिया है।
- iv. परियोजना रिपोर्ट पर भारी विश्वास करने के बावजूद घरेलू उद्योग ने पूरी परियोजना रिपोर्ट गोपनीय होने का दावा किया है। उन्होंने परियोजना रिपोर्ट का कोई सार्थक अगोपनीय सार भी नहीं दिया है ताकि हितबद्ध पक्षकार उसका कोई प्रभावी खंडन कर सकें अथवा टिप्पणियां दे सकें।
- v. याचिकाकर्ता ने भारत में कुल उत्पादन प्रकट न कर अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है जो कि दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना 10/2018 के अनुसार प्रकट किया जाना अपेक्षित है।
- vi. याचिकाकर्ता ने क्षति के आरोपों से संबंधित सूचना को गलत ढंग से रोका और उसमें छेड़छाड़ की।
- vii. घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और अपूर्ण याचिका दायर की।

ड.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

34. गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - i. विरोधी पक्षकारों ने इस मामले में अत्यधिक गोपनीयता का सहारा लिया जिसमें उनके दावों पर पर्याप्त खंडन देने के लिए आवेदक की क्षमता को सीमित किया है। गोपनीयता के दावे पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के उल्लंघन में है। पक्षकार गोपनीय होने के दावे की सूचना के मान्य कारण अथवा सार्थक सार देने में विफल रहे जो अक्षरशः गोपनीयता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। प्राधिकारी विरोधी पक्षकारों को नियम 7 की अपेक्षाओं का पालन करने के निर्देश दे सकते हैं।
 - ii. शानडोंग केलेसी न्यू मैटिरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने संबद्ध कंपनियों के नाम भी गोपनीय रखे हैं और कंपनी द्वारा दायर उत्तर पर उसकी पूर्णता के संबंध में टिप्पणी करने में हमारी क्षमता प्रभावित हुई है।
 - iii. शंघाई सैलिसि इंडस्ट्री डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने अपने शेयरधारकों के कोई ब्यौरे नहीं दिए हैं और साथ ही कंपनी की संबद्धता के ब्यौरे भी गोपनीय रखे गए हैं। इससे भी उत्तर की पूर्णता के संबंध में हमारी टिप्पणियां प्रभावित हुई हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या संबद्ध सामानों से संबंधित सभी पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष आए हैं अथवा नहीं।
 - iv. परियोजना रिपोर्ट के संबंध में गोपनीयता के दावों से संबंधित तर्कों में कोई औचित्य नहीं है। दस्तावेज पर पूर्ण गोपनीयता का दावा किया गया है क्योंकि अनिवार्य ब्यौरे प्रकट किए बिना उसके किसी अगोपनीय सार की तैयारी गैर-अर्थक्षम पाई गई थी और सूचना गोपनीय है तथा प्रकृति में व्यापार संवेदी है।

v. यह तर्क कि आवेदक ने अत्यधिक गोपनीयता का सहारा लिया और अपूर्ण याचिका दायर की, किसी औचित्य से परे है। आवेदन पत्र स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग को पाटन तथा परिणामी क्षति दर्शाता है और सूचना नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार तथा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। साथ ही, परियोजना रिपोर्ट सहित कुछ सूचना नियम में अनुमति योग्य पूरे कारण देकर गोपनीय होने का दावा किया गया है और यथा-संभव सार भी दिए गए हैं।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

35. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

“गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”

36. नियम 6(7) की अपेक्षा अनुसार प्राधिकारी ने एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा उन्हें प्रस्तुत साक्ष्य जांच में प्रतिभागी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया। यह सूचना जांच में प्रतिभागी अन्य हितबद्ध पक्षकारों में उस साक्ष्य का आदान प्रदान करने के निर्देशों के साथ प्रतिभागी हितबद्ध पक्षकारों में परिचालित की गई थी।

37. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच उन दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी, संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक था गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और वह सूचना गोपनीय मानी गई है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां कहीं संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर दें। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यापार संबंधी संबंधी संवेदी सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है।

38. आवेदन पत्र के प्रयोजन से आवेदक द्वारा प्रयुक्त आयात आंकड़ों के स्रोत के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने बाजार सूचना के रूप में आंकड़ों का स्रोत उल्लिखित किया है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के लिए डीजी सिस्टम के लेनदेन-वार आंकड़ों को माना है।

39. इस तर्क के संबंध में कि परियोजना रिपोर्ट पर भारी रूप से विश्वास करने के बावजूद घरेलू उद्योग ने पूरी परियोजना रिपोर्ट को गोपनीय होने का दावा किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने व्यापार संवेदनशीलता के आधार पर परियोजना रिपोर्ट के संबंध में गोपनीयता का दावा किया।

इस अनुरोध के संबंध में कुल घरेलू उत्पादन संबंधी वास्तविक सूचना आधार के निर्धारण के संबंध में प्रकट की जानी चाहिए, यह नोट किया जाता है कि आवेदक द्वारा धारित भारतीय कुल उत्पादन में हिस्से की रेंज दी गई है जो आधार के निर्धारण के लिए संगत सूचना के सार्थक सार के रूप में नोट की गई है।

च. विविध अनुरोध

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

41. विभिन्न विविध मुद्दों के संबंध में निर्यातक/उत्पादक/अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. जांच की शुरुआत के बाद आवेदक ने कोई अद्यतन याचिका प्रस्तुत नहीं की है।
- ii. याचिका द्वारा माने गए आयात आंकड़े अविश्वसनीय स्रोतों से हैं।
- iii. डीजीटीआर को याचिका में निहित सूचना के आधार पर वर्तमान जांच शुरू नहीं करनी चाहिए थी।
- iv. पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू उत्पादक का एकाधिकार स्थापित होगा और वह जनहित में नहीं होगा।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

42. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित विविध अनुरोध/खंडन किए हैं:

- i. निर्यातकों का यह तर्क कि जांच की शुरुआत के बाद आवेदक द्वारा कोई अद्यतन याचिका प्रस्तुत नहीं की गई है, का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि जांच की शुरुआत के समय संबद्ध देश में परिवर्तन के बाद याचिका में संगत अद्यतन संबंधी अनुरोध घरेलू उद्योग द्वारा 27 फरवरी, 2024 को प्रस्तुत किए गए हैं। और वे 12 मार्च, 2024 को हितबद्ध पक्षकारों में परिचालित भी किए गए हैं। वह सूचना पहली मौखिक सुनवाई के बाद लिखित अनुरोध के साथ एक बार फिर दी गई है।
- ii. यह तर्क कि याचिकाकर्ता द्वारा माने गए आयात आंकड़े अविश्वसनीय स्रोतों से हैं, का कोई आधार नहीं है। यह ज्ञात तथ्य है कि डीजीसीआईएंडएस के अनुसार लेनदेन-वार आयात सूचना आम जनता द्वारा अथवा कंपनी द्वारा नहीं ली जा सकती और आवेदक संबंधित प्राधिकारियों द्वारा लागू विनियमों के मद्देनजर उन आंकड़ों को नहीं ले पाया तथा ये कठिनाइयां आवेदन पत्र में भी दस्तावेजयुक्त की गई हैं। अतः, आवेदक को अन्य स्रोतों पर विश्वास करना था।

iii. इस तर्क के संबंध में कि डीजीटीआर को याचिका में निहित सूचना के आधार पर वर्तमान जांच शुरु नहीं करनी चाहिए थी, यह नोट किया जाए कि आवेदन-पत्र स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग को पाटन और परिणामी क्षति दर्शाता है और सूचना नियमों के अपेक्षानुसार तथा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार भी प्रस्तुत की गई हैं।

iv. इस तर्क के संबंध में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से घरेलू उत्पादक का एकाधिकार स्थापित होगा और जनहित में नहीं होगा, प्राधिकारी नोट करें कि भारत में संबद्ध सामानों के लगभग 6 ज्ञात उत्पादक हैं। यह एक एक निर्धारित सिद्धांत है कि पाटनरोधी शुल्क से एकाधिकार नहीं होगा। इसकी अपेक्षा इससे पाटित आयात बंद होंगे जिससे घरेलू उद्योग उचित व्यापारिक और उचित बाजार स्थितियों में प्रचालन कर पाएंगे। भारत में अपने बल पर भारतीय मांग को पूरा करने की क्षमता है और देश इस उत्पाद के संबंध में आत्मनिर्भर हो सकता है।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

43. प्राधिकारी ने निम्नलिखित रूप में हितबद्ध पक्षकारों के विचारों पर विचार किया है:

i. इस तर्क के संबंध में कि जांच की शुरुआत के बाद, आवेदक द्वारा कोई अद्यतन याचिका प्रस्तुत नहीं की गई है, यह नोट किया जाता है कि यह सूचना आवेदक द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों में परिचालित की गई है।

ii. इस तर्क के संबंध में कि आवेदक द्वारा माने गए आयात आंकड़े अविश्वसनीय स्रोतों से हैं, यह नोट किया जाता है कि आवेदक ने आयात आंकड़ों के लिए गौण स्रोत पर विश्वास किया क्योंकि वह डीजीसीआईएंडएस से उपर्युक्त आंकड़े नहीं ले पाया। तथापि, प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत के समय ही डीजीएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है और उन आंकड़ों का प्रयोग इस विवरण के लिए भी किया गया है।

iii. इस तर्क के संबंध में कि डीजीटीआर को याचिका में निहित सूचना के आधार पर वर्तमान जांच शुरु नहीं करनी चाहिए थी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह मामला ऐसी जांच की शुरुआत के लिए सभी संगत मापदंडों की प्रथमदृष्टया संतुष्टि के आधार पर शुरु किया गया था। आवेदन पत्र में दावे सत्यापन और विस्तृत जांच के अध्यधीन रखे गए हैं तथा उस सत्यापित सूचना पर ही अंतिम जांच परिणामों के लिए विचार किया गया है।

iv. इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क से याचिकाकर्ता का एकाधिकार बनेगा और ऐसा कोई भी उपाय जनहित के विरुद्ध होगा, यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से निचले स्तर के प्रयोक्ताओं के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपाय से कम नहीं होगी और विशेष रूप से क्योंकि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना घरेलू उद्योग को क्षति का हल करने के लिए आवश्यक राशि तक प्रतिबंधित है। पाटनरोधी उपाय लगाए जाने से पाटन की परिपाटियों से प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे और किसी भी तरह उचित आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे। पाटनरोधी शुल्कों से घरेलू उद्योग को हो रही क्षति भी रुकेगी और संबद्ध सामानों के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद भी मिलेगी।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

44. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. चीन जनवादी गणराज्य को बाजार अर्थव्यवस्था का स्तर दिया जाना चाहिए।
- ii. विश्व व्यापार संगठन में चीन जनवादी गणराज्य के अभिगम संबंधी नयाचार की धारा 15 (क) (II) के अनुसार 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गया। उस तारीख के बाद भारत का गैर बाजार अर्थव्यवस्था पद्धति का प्रयोग करके चीनी उत्पादों की पाटनरोधी जांच में सामान्य मूल्य का परिकलन करने हेतु विश्व व्यापार संगठन के करारों के तहत कोई कानूनी आधार नहीं है। भारत द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और अन्य शामिल करारों की अपेक्षाओं के असंगत होगी।
- iii. प्राधिकारी पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2 के अनुसार किसी सामान्य मूल्य का परिकलन कर सकते हैं।
- iv. कम से कम, इस जांच में असमान देश के आंकड़े लागू करने के बजाए सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उत्तर में निर्यातक कंपनियों द्वारा दी गई लागतों और कीमतों संबंधी आंकड़े लागू करें।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

45. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. याचिका में सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और आवेदक के दावों के अनुसार, पाटन मार्जिन का कार्यकरण से संबंधित सभी संगत सूचना है। ये आंकड़े चीन जन.गण. से संबद्ध सामानों के आयातों के मामले में काफी पाटन मार्जिन दर्शाते हैं। पाटन मार्जिन आरंभिक न्यूनतम से अधिक ही नहीं हैं बल्कि विचाराधीन उत्पाद के लिए अत्यधिक सकारात्मक भी हैं।
- ii. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण अब भी संगत है क्योंकि वह यह सिद्ध करने के लिए चीन जन.गण. से उत्पादकों पर है कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में विद्यमान है।
- iii. चीन जन.गण. को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और उसके बाद सामान्य मूल्य का आधार आवेदन-पत्र में दिया जाता है। साथ ही, प्राधिकारी नोट करें कि उत्तरदाता निर्यातकों ने लागू प्रश्नावली के उत्तर दायर कर एमईटी का दावा नहीं किया है और इस संदर्भ में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण इस मामले में बहुत अनिवार्य है।

iv. वर्तमान मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि चीन जन.गण. से संबद्ध सामानों के निर्यातक भारतीय उत्पादकों को हानि पहुंचाकर भारत में अधिक बाजार हिस्सा लेने की नीति के रूप में, भारत में संबद्ध सामानों के पाटन का प्रयोग कर रहे हैं और निर्यातकों का यह डिजाइन इससे सिद्ध है कि वे अपने निजी बाजार में संबद्ध सामानों की बिक्री भारत को और अन्य देशों को करते हैं। शानडोंग केलेसी न्यू मैटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के उत्तर में उपलब्ध सूचना निम्नलिखित प्रवृत्ति दर्शाती है:

विवरण	इकाई	तीसरा पूर्व वर्ष - 2020	दूसरा पूर्व वर्ष (2021)	पहला पूर्व वर्ष (2022)	जांच की अवधि
संस्थापित क्षमता	सूचीबद्ध	100	200	200	250
क्षमता उपयोग प्रतिशतता	सूचीबद्ध	100	164	182	211
बिक्री मात्रा (पीयूसी):					
घरेलू बिक्री	सूचीबद्ध	100	151	222	293
भारत को निर्यात	सूचीबद्ध	100	588	1590	2349
अन्य देश	सूचीबद्ध	100	277	373	458
बिक्री वसूली प्रति यूनिट (पीयूसी):					
घरेलू बिक्री	सूचीबद्ध	100	85	84	83
भारत को निर्यात	सूचीबद्ध	100	78	89	88
अन्य देश	सूचीबद्ध	100	89	103	105

v. उपर्युक्त तालिका से निम्नलिखित सिद्ध है:

क. निर्यातक ने बहुत ही आक्रामक रूप से अपनी क्षमता बढ़ाई है और जांच की अवधि तक क्षमता उपयोग भी दुगुना हुआ। यह स्पष्ट है कि भारत को निर्यातों में कई गुना वृद्धि से क्षमता और क्षमता उपयोग में यह आक्रामक वृद्धि बड़ी है।

ख. भारत को निर्यातों में उच्चतम मात्रात्मक वृद्धि सिद्ध है जिसमें यह वृद्धि घरेलू और अन्य बाजारों में भी निर्यातक द्वारा सामानों की बिक्री से है। मात्रा में यह वृद्धि 100 सूचकांक से 2349 सूचकांक तक आधार वर्ष में

जांच की अवधि तक लगभग 12% तक और तत्काल पूर्व वर्ष में 1% तक कीमत में कमी से प्राप्त हुई है। इस प्रकार, कीमत में कमी भारत को निर्यातों की मात्रा बढ़ाने की रणनीति के रूप में प्रयुक्त की गई थी।

ग. आवेदन पत्र में विश्वास किए गए आयात आंकड़े जांच की अवधि तक चीन जन.गण. से आयातों में भारी वृद्धि दर्शाते हैं और उपर्युक्त आंकड़े इस तथ्य को कम करते हैं कि चीन जन.गण. से निर्यातक भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात आक्रामक रूप से करते आ रहे हैं और मात्रा, पाटित कीमतों को बढ़ाने के लिए पेश की गई है तथा भारत को कीमतें कम की गई थी, जबकि अन्य देशों को निर्यातों ने वृद्धि दर्ज की।

घ. यह स्पष्ट है कि निर्यातक ने भेदभावपूर्ण कीमत अपनाई है और परिणामस्वरूप, यद्यपि भारत को कीमत में जांच की अवधि तक लगभग 12% तक गिरावट आई, तथापि अन्य देशों को कीमत 5% तक बढ़ी। यह स्पष्ट है कि निर्यातक की भारत के लिए कम कीमत की रणनीति है जिससे पाटन हो रहा है।

ड. उपर्युक्त तथ्य सामूहिक रूप से यह दर्शाते हैं कि निर्यातक ने भारत में संबद्ध सामानों के लिए अधिक बाजार हिस्सा लेने हेतु रणनीति के रूप में पाटन अपनाया है और ये स्थिति उपयुक्त पाटनरोधी शुल्क लगाकर ही ठीक की जा सकती है।

vi प्राधिकारी आवेदन पत्र में दावों के आधार पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित कर सकते हैं।

vii. संबद्ध सामानों का पाटन सिद्ध है और यह घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचाने के लिए काफी पर्याप्त है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

सामान्य मूल्य

46. धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

चीन जन.गण. के उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था का स्तर

47. डब्ल्यूटीओ में चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है: “जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 (“पाटनरोधी करार”) के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार एक डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों की संलिप्तता की कार्यवाहियों में लागू होंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

“(क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद -VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ क (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

48. यह नोट किया जाता है कि अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि एक्सेसन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में भारत की नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के ज़रिए पूरा करना अपेक्षित है।

49. जांच की शुरुआत के स्तर पर, प्राधिकारी ने एसजीए और लाभ जोड़कर भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार सामान्य मूल्य निर्मित कार्यवाही की। जांच शुरू करने पर प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दी कि वे जांच की शुरुआत की सूचना का उत्तर दें और अपनी बाजार अर्थव्यवस्था के स्तर के निर्धारण के लिए संगत सूचना दें। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) में निर्धारित मानदंडों के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा का खंडन करने और संगत विस्तृत सूचना देने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजी। प्राधिकारी ने चीन जन.गण. की सरकार से यह भी अनुरोध किया कि वे चीन में उत्पादकों/निर्यातकों को संगत सूचना देने की सलाह दें।

50. किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने चीन के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था स्तर का विरोध नहीं किया। इस प्रकार, उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर और किसी भी चीनी निर्यातक कंपनी द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा का खंडन किए जाने के अभाव में, प्राधिकारी चीन जन.गण. को वर्तमान जांच में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानना उपयुक्त समझते हैं और चीन जन.गण. के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही करते हैं।

51. तदनुसार, चीन जन.गण. से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य निम्नलिखितानुसार निर्धारित किया गया है:

चीन जन.गण. में सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य

52. नियमावली का अनुबंध I निम्नलिखित रूप में पठित है:

गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य, अथवा भारत या जहां यह संभव नहीं है, वहां सहित तीसरे देश से अन्य देशों से कीमत अथवा अन्य किसी उपयुक्त आधार, जिसमें आवश्यक होने पर विधिवत समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त अथवा देय कीमत शामिल है, उपयुक्त लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए, के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश संबंधित देश के विकास और प्रश्रुत उत्पाद के मद्देनजर उपयुक्त तरीके में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा चुना जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर उचित ध्यान दिया जाएगा। किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में किसी समान मामले में की गई जांच की समय सीमाओं, जहां लागू हो, के भीतर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त चयन से किसी अपर्याप्त विलंब के बिना सूचित किया जाएगा और उनकी टिप्पणियां देने के लिए उपयुक्त समयावधि दी जाएगी।

53. पैरा 7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए एक अनुक्रम निर्धारित है और यह प्रावधान है कि सामान्य मूल्य किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य, अथवा तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों में कीमत के आधार पर अथवा जहां यह संभव नहीं है, वहां उपयुक्त लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए आवश्यक होने पर विधिवत समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त अथवा देय कीमत सहित किसी अन्य उपयुक्त आधार पर निर्धारित किया जाएगा। चूंकि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत तथा निर्मित मूल्य, अथवा ऐसे तीसरे देश से अन्य देशों को कीमत आवेदक सहित किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए भारत को रिकॉर्ड में कोई दावा नहीं है, अतः सामान्य मूल्य इस आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता। अतः, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 में निर्धारित किए गए अनुसार भारत में वास्तव में देय कीमत के रूप में चीन जन.गण. से संबद्ध सामानों के लिए सामान्य मूल्य निर्मित किया है। इसका परिकलन बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और लाभ के लिए उपयुक्त अभिवृद्धि कर घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्मित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

i. निर्यात कीमत

क) शांगडोंग केलेसी न्यू मैटिरियल टेक्नोलॉजी कं. लि. (उत्पादक)

54. शांगडोंग केलेसी न्यू मैटिरियल टेक्नोलॉजी कं. लि., जो संबद्ध सामानों का उत्पादक एवं निर्यातक है, के निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर से यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि में कंपनी ने भारत को ***मी.ट. संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। उत्पादक/निर्यातक ने अंतरदेशीय परिवहन, समुद्री भाड़ा, बीमा, बैंक प्रभार और

पत्तन एवं अन्य संबद्ध खर्चों के निमित्त समायोजनों का दावा किया है और उनकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

55. शंघाई सैलिसी इंडस्ट्री डेपलेपमेंट कं. लि. (व्यापारी) - शंघाई सैलिसी इंडस्ट्री डेपलेपमेंट कं. लि., जो संबद्ध सामानों का निर्यातक/व्यापारी है, के निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर से यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि में कंपनी ने शांगडोंग केलेसी न्यू मैटरियल टेक्नोलॉजी कं. लि. द्वारा उत्पादित ***मी.ट. संबद्ध सामानों का भारत को निर्यात किया। उत्पादक/निर्यातक ने अंतरदेशीय परिवहन, समुद्री भाड़ा, बीमा, बैंक प्रभार और पत्तन एवं अन्य संबद्ध खर्चों के निमित्त समायोजनों का दावा किया है और उनकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

चीन में सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

56. चीन जन.गण. के अन्य असहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत सहयोगी निर्यातकों के लिए जांच किए गए आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध कीमतों के अनुसार है और वह पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

पाटन मार्जिन

57. संबद्ध सामानों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को देखते हुए, संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के लिए पाटन मार्जिन निम्नलिखित है। यह देखा जाता है कि प्रतिभागी उत्पादक के लिए पाटन मार्जिन न्यूनतम है।

पाटन मार्जिन तालिका

क्र.सं.	देश	उत्पादक	सामान्य मूल्य अम.डा./कि.ग्रा.	निवल निर्यात कीमत अम.डा./कि.ग्रा.	पाटन मार्जिन अम.डा./कि.ग्रा.	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन (रेंज %)
1	चीन जन.गण.	शांगडोंग केलेसे न्यू मैटरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड और शंघाई सैलिसी इंडस्ट्री डेपलेपमेंट कं. लिमिटेड, शांगडोंग ब्रांच	***	***	***	***	0-10
2	चीन जन.गण.	अन्य कोई उत्पादक	***	***	***	***	5-15

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध का मूल्यांकन**ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

58. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित उत्पादन और लाभ भारत में उत्पन्न अप्रत्याशित और अभूतपूर्व संकट के कारण तथा कोविड-19 फ्लू महामारी के रूप में समस्त विश्व जिसके कारण लोगों का सामाजिक आर्थिक जीवन वैश्विक रूप से पटरी से उतर गया और आगामी कई महीनों और वर्षों तक व्यापार और वाणिज्य बिगड़ गया, के कारण ध्यान में नहीं रखा जा सकता।
- ii. परियोजना रिपोर्ट, जो पूरी तरह भिन्न बाजार स्थिति पर आधारित थी, पर महामारी के प्रभाव के कारण उचित समायोजन किए बिना वास्तविक मंदी के विश्लेषण के लिए वर्तमान जांच में विश्वास नहीं किया जाना चाहिए।
- iii. संबद्ध देश से आयात भारत में केवल मांग और आपूर्ति अंतराल को भरने के लिए आ रहे हैं क्योंकि याचिकाकर्ता भारतीय मांग पूरा नहीं कर सकता। तदनुसार, संबद्ध देश के आयात मांग में वृद्धि के साथ बढ़ते रहे हैं।
- iv. याचिकाकर्ता और अन्य घरेलू उत्पादकों के पास उपलब्ध वर्तमान क्षमता से वह भारतीय मांग को पूरा नहीं कर सकता। अतः आयात भारत में मांग और आपूर्ति अंतराल को भरने के लिए ही है न कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति पहुंचाने के लिए।
- v. प्रति यूनिट बिक्री लागत आधार वर्ष 2019-20 में 100 की तुलना में जांच की अवधि में 49 प्रतिशत तक कम हुई। जबकि, निवल बिक्री वसूली 49% तक बढ़ी, आधार वर्ष 2019-20 में 100 से जांच की अवधि में 149 हुई। इससे घरेलू उद्योग को लाभप्रदता हुई क्योंकि उनकी बिक्री कीमत बिक्री लागत से कहीं अधिक है। इस प्रकार, जांच की अवधि में कोई कीमत प्रभाव नहीं है।
- vi. याचिकाकर्ता की क्षमता पूरी क्षति अवधि में और जांच की अवधि में अपरिवर्तित रही। याचिकाकर्ता का उत्पादन और क्षमता उपयोग क्रमशः यह दर्शाते हुए तेजी से बढ़ा कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं है।
- vii. याचिकाकर्ता के उत्पादन में वृद्धि से उनकी घरेलू बिक्री जांच की अवधि में 6 गुना से भी अधिक बढ़ी। याचिकाकर्ता की निर्यात बिक्री काफी बढ़ी है।
- viii. उत्पाद दिवसों की संख्या के रूप में औसत मालसूची और बिक्री गिरावट दर्शा रहे हैं, यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता उन्होंने जो भी उत्पादन किया उसकी बिक्री करने में सक्षम था।
- ix. याचिकाकर्ता को पूरी क्षति अवधि और जांच की अवधि में हानियां हो रही थी। तथापि, ये हानियां जांच की अवधि में काफी कम हो गईं जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में यह दर्शाते हुए काफी सुधार हुआ है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं है।

- x. याचिकाकर्ता की वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट आवेदक की लाभप्रदता दर्शाती है। यह नोट किया जाए कि याचिकाकर्ता की पीबीटी जांच की अवधि में अधिकतम थी, जो यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है।
- xi. कर्मचारियों की संख्या और मजदूरी बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शा रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं है।
- xii. याचिकाकर्ता की उत्पादकता में आधार वर्ष 2019-20 की तुलना में जांच की अवधि में सुधार हुआ, जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं है।
- xiii. घरेलू उद्योग का समग्र निष्पादन सुधरा है। याचिकाकर्ता के सभी आर्थिक मापदंड यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं है और यदि कोई है तो वह चीन जन.गण. से संबद्ध सामानों के आयातों के कारण हो सकती है। जांच की शुरुआत में प्राधिकारी द्वारा की गई टिप्पणियों में तथ्यात्मक और कानूनी आधार का अभाव है।
- xiv. घरेलू उद्योग को हुई तथाकथित रूप से कोई क्षति संबंधित देश से आयातों को छोड़कर अन्य कारकों से है। याचिका कई महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने में विफल है जिनका संबंधित देश के मूल के आयातों से स्वतंत्र रूप से घरेलू उद्योग पर प्रभाव था।
- xv. चीनी उत्पाद गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर हैं। आयातित उत्पादों की गुणवत्ता भारतीय एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसेस से बेहतर है। चीनी और कोरियाई उत्पादक उच्च गुणवत्ता के उत्पाद देते हैं जो टिकाऊपन बढ़ाते हैं तथा अनुप्रयोग का क्षेत्र व्यापक करते हैं।
- xvi. कच्ची सामग्री की कीमतों में उतार-चढ़ाव का वैश्विक एक्रिलिक सॉलिड सर्फेस बाजार पर काफी प्रभाव है। कच्ची सामग्री, यथा- एल्युमिना ग्राइंड्रेट और एक्रिलिक रेसिन की कीमतें विभिन्न कारकों, यथा – आपूर्ति एवं मांग, भौगोलिक तनाव और प्राकृतिक आपदाओं के कारण घटती बढ़ती रहती हैं।
- xvii. कोविड-19 महामारी का विश्व भर में व्यापारों पर गंभीर प्रभाव रहा है। आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और उपभोक्ता का व्यवहार सुदूर कार्य-व्यवस्थाओं में परिवर्तित होने और वित्तीय चुनौतियों से महामारी में व्यापार को तेजी से अभूतपूर्व परिस्थितियां अपनाने के लिए मजबूर किया। कई उद्यमों को याचिकाकर्ता सहित काफी धक्का लगा।
- xviii. अन्य कारणों में आंतरिक समस्याएं वैश्विक रूप से हतोत्साहित बाजार स्थितियां रूस यूक्रेन युद्ध आदि शामिल हो सकते हैं जिसने घरेलू उद्योग के निष्पादन के हास में भूमिका निभाई हो सकती है, जो संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन के कारण है।

xix. याचिकाकर्ता ने सकल अचल परिसंपत्तियों पर 22% आय मानते हुए परिकलन किए हैं जो अत्यधिक बड़ा हुआ है और कानून के अनुसार नहीं है। अनुरोध है कि माननीय व्यापार उपचार महानिदेशक क्षति रहित कीमत का परिकलन करने के लिए नियोजित पूंजी पर 22% आय के रूप में उपयुक्त लाभ न अपनाएं।

xx. माननीय व्यापार उपचार महानिदेशक को उस अवधि को घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ अपनाना चाहिए जब उपयुक्त आय का परिकलन करने के लिए आधार के रूप में पाटन का आरोप नहीं था।

xxi. वास्तविक निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए परियोजना रिपोर्ट मापदंड नहीं हो सकती। याचिकाकर्ता ने उत्पादन मात्रा और परियोजना रिपोर्ट में लाभ की दिखावटी तस्वीर प्रस्तावित की जिसे आवेदक के वास्तविक निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए मापदंड नहीं माना जा सकता।

ज.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

59. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा प्रस्तुत पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध संबंधी सकारात्मक साक्ष्य ये दर्शाते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के परिकल्पित पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई। सूचना में पाटित आयातों की मात्रा के ब्योरे और समान वस्तु के लिए घरेलू उद्योग ने कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव तथा नियम 11 के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में परिकल्पित घरेलू उद्योग पर इन पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव शामिल हैं।

ii. आवेदन पत्र में सूचना ये भी दर्शाती है कि निष्पादन उससे बहुत कम है जो उद्योग ने प्राप्त करना प्रस्तावित किया था और उस अर्थ में उद्योग की स्थापना की भी वास्तविक रूप से मंदी हुई थी। इस प्रकार, वास्तविक क्षति का सह-अस्तित्व और उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी भी वर्तमान मामले में बड़ा साक्ष्य है। पूर्वाग्रह के बिना वास्तविक क्षति इस मामले में बड़ा साक्ष्य है, यहां तक कि यदि प्राधिकारी वास्तविक मंदी के दावों की जांच न करने का निर्णय लें।

iii. अनुबंध II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली का नियम 11 दर्शाता है कि वास्तविक क्षति अथवा घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा अथवा ऐसे उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी हो सकती है। वर्तमान मामले की क्षति के तथ्य वास्तविक क्षति और वास्तविक मंदी के रूप में क्षति दर्शा सकते हैं और प्राधिकारी द्वारा उसकी जांच की जाए। जहां तक आवेदक का संबंध है, उसे पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है और उसकी प्रकृति नियम में परिकल्पित अनुसार प्राधिकारी द्वारा निर्धारण का मामला है।

iv. निष्पादन के प्रस्तावित स्तर का समर्थन करने के लिए आवेदक की परियोजना रिपोर्ट दी गई है जो कई मापदंडों के मामलों में संगत है। आवेदक ने वित्त वर्ष 2018-19 में (अक्तूबर, 2018) वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया, जो दर्शाता है कि आवेदक ने हाल की अवधि में उत्पादन शुरू किया। तथापि, यदि पाटित आयात न होते तो आवेदक ने अब तक अपने को पूरी तरह स्थापित कर लिया होता और जांच की अवधि तक क्षमता उपयोग, उत्पादन, लाभ आदि के प्रस्तावित स्तर प्राप्त कर लिए होते।

v. भारत में इस समय तक स्पष्ट रूप से एक निर्धारित न्याय-निर्णय है कि वास्तविक क्षति और वास्तविक मंदी किसी जांच में साथ साथ रह सकती हैं और विगत में कई जांचों में प्राधिकारी द्वारा लिया गया स्पष्ट दृष्टिकोण इस मामले में भी लागू किया जा सकता है। क) अंतिम जांच परिणाम- चीन जन.गण., मलोशिया, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ के मूल के विनीर्ड इंजीनियर्ड वुडन फ्लोरिंग के आयातों संबंधी पाटनरोधी जांच दिनांक 13.2.2018, चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ओ-एसिड के आयातों संबंधी पाटनरोधी जांच दिनांक 19 दिसंबर, 2017 में लिया गया दृष्टिकोण इस मामले में भी लागू किया जा सकता है। विनीर्ड इंजीनियर्ड वुडन फ्लोरिंग मामले में यह स्पष्ट रूप से नोट किया गया है कि “जहां तक इस तर्क का संबंध है कि वास्तविक मंदी और वास्तविक क्षति साथ-साथ नहीं हो सकते, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति के एक रूप से अधिक की जांच के लिए कानून के तहत कोई प्रतिबंध नहीं है”

vi संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयात जांच की अवधि तक पूर्ण दृष्टि से तथा भारत में खपत के संबंध में बड़े हैं। वस्तुतः, पाटित आयात जांच की अवधि में उच्चतम स्तर पर थे।

vii. पाटित आयातों का बाजार हिस्सा जांच की अवधि तक बढ़ा और जांच की अवधि में भारतीय मांग में काफी बड़ा हिस्सा लेता रहा। यद्यपि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा भी जांच की अवधि तक बढ़ा, तथापि पूर्ण दृष्टि से बाजार हिस्सा बहुत असामान्य रहा और घरेलू उद्योग की क्षमता इस असामान्य बाजार हिस्से के परिणामस्वरूप जांच की अवधि में व्यापक रूप से कम उपयोग में रही।

viii. वास्तविक क्षति इस तथ्य में है कि यद्यपि पाटित आयात अपना बाजार हिस्सा आधार वर्ष में 5-10% से बढ़ाकर जांच की अवधि में 25-35% बढ़ा पाए, तथापि घरेलू उद्योग का हिस्सा आधार वर्ष में 0-2% से बढ़कर जांच की अवधि में 3-6% तक बढ़ पाया। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग अपना क्षमता उपयोग आधार वर्ष में 2-10% से बढ़ाकर जांच की अवधि में 25-35% ही कर पाया। वस्तुतः घरेलू उद्योग ने प्रचालन के चौथे अथवा पाचवें वर्ष तक 70-80% का क्षमता उपयोग स्तर तक पहुंचने की उम्मीद की थी परंतु वह पाटित आयातों के कारण रुक गया।

ix. यह वह मामला है जहां चीन जन.गण. से पाटित आयातों ने बाजार हिस्सा ले लिया और घरेलू उद्योग को क्षमता उपयोग के प्रत्याशित स्तरों से कम पर प्रचालन करने के लिए धकेल दिया जिससे फिर समग्र निष्पादन प्रभावित हुआ।

x. सूचना दर्शाती है कि घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग, उत्पादन और बिक्री जांच की अवधि तक बहुत कम थी और इन मापदंडों पर वास्तविक निष्पादन इन मापदंडों संबंधी प्रस्तावित अथवा प्रत्याशित संख्याओं से कहीं कम था। क्षति की अवधि में जांच की अवधि तक इन मानदंडों में वृद्धि कहीं अधिक हुई होती, यदि पाटन न होता और इन मापदंडों पर प्राप्त वृद्धि बहुत खराब और नाम मात्र की थी।

- xi. क्षमता उपयोग से कम, प्रस्तावित स्तरों से काफी कम, यहां तक कि जब देश सुदृढ़ मांग दर्शा रहा था, भारत में पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण सीधी गिरावट है और इस मापदंड पर क्षति और वास्तविक मंदी का साक्ष्य घरेलू उद्योग को क्षति के वास्तविक प्रभाव के रूप में पाटित आयातों को दर्शाता है।
- xii. घरेलू उद्योग काफी उपयोग न की गई क्षमताओं पर रह गया था क्योंकि प्रमुख बाजार हिस्सा पाटित आयातों ने ले लिया था। यह स्थिति तब है जब देश में उत्पाद के लिए मांग में वृद्धि रही है।
- xiii. पाटित आयातों की पहुंच कीमत से सकारात्मक कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री और कीमत न्यूनीकरण प्रभाव सृजित हुए क्योंकि घरेलू उद्योग को कीमत बढ़ाने से रोका गया था जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती ताकि पूरी लागत वसूली जा सके तथा उपयुक्त लाभ कमाया जा सके।
- xiv. घरेलू उद्योग को नकारात्मक पीबीटी, नकारात्मक पीबीआईटी, नकारात्मक पीबीडीआईटी और नकारात्मक आरओआई में दर्शाए गए अनुसार वित्तीय हानियां हुई और ये प्रमुख मापदंड जांच की अवधि में और क्षति अवधि में नकारात्मक थे। इन नकारात्मक आंकड़ों के अलावा, नकद लाभ और पीबीडीआईटी के संदर्भ में वास्तविक निष्पादन बहुत कम थे, यद्यपि जांच की अवधि में थोड़ा सा सकारात्मक हुए।
- xv. यद्यपि लाभप्रदता मानदंडों ने पूर्व वर्षों की तुलना में जांच की अवधि तक कुछ वृद्धि दर्शाई, तथापि इन मापदंडों पर वास्तविक निष्पादन प्रस्तावित अथवा अनुमानित संख्याओं से कहीं कम थे और किसी भी तरह घरेलू उद्योग की अच्छी स्थिति नहीं दर्शाते। क्षति अवधि में जांच की अवधि तक इन मापदंडों में वृद्धि कहीं अधिक हुई होती, यदि पाटन न होता।
- xvi. घरेलू उद्योग में मालसूची बढ़ी और यह वृद्धि बाजार में पाटित सामग्री की भारी मौजूदगी के कारण है। मालसूची में वृद्धि मात्रात्मक क्षति दर्शाती है क्योंकि मालसूची में वृद्धि दर्शाती है कि घरेलू उद्योग के उत्पाद का उठना बहुत कम था, यद्यपि उत्पादन बहुत कम दरों पर बढ़ा।
- xvii. मालसूची के स्तर में वृद्धि नकारात्मक थी, जांच की अवधि तक सभी प्रमुख मापदंडों के संदर्भ में वास्तविक वृद्धि बहुत खराब रही है और उन मापदंडों संबंधी अनुमानों से कम रही है। इस प्रकार, पाटित आयातों में घरेलू उद्योग को सुदृढ़ वृद्धि प्राप्त करने से रोका जो क्षति के संकेत दर्शाता है और इन पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को स्थापित होने से रोका, जैसा कि सभी प्रमुख क्षति मानदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दर्ज प्रत्याशित वृद्धि से कम का साक्ष्य है।
- xviii. घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता काफी प्रभावित हुई है और क्षमता में प्रस्तावित वृद्धि पूरी नहीं की जा सकी।
- xix. आयात पाटित स्तरों पर होते रहे हैं और पाटन मार्जिन संबद्ध देश के मामले में काफी सकारात्मक है। आयातों की प्रवृत्ति यह नहीं दर्शाती कि पाटन की वर्तमान दर से स्थिति में कोई परिवर्तन आएगा और यदि पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाता है तो पाटन बढ़ते ही जाएंगे।

- xx. घरेलू उद्योग ने जिस गति से क्षति अवधि और जांच की अवधि में प्रचालन किया, यह दर्शाता है कि पाटन घरेलू उद्योग को अच्छा निष्पादन करने से और उसे प्रत्याशितानुसार स्थापित होने से रोकते रहेंगे।
- xxi. इस प्रकार, घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और इस बात के साक्ष्य हैं कि प्रत्याशितानुसार उद्योग की स्थापना प्राप्त नहीं की जा सकी।
- xxii. यद्यपि जांच की शुरुआत के बाद के अनुबंध के साथ पठित याचिका में क्षति के मानदंड दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को नियमावली में परिकल्पनानुसार क्षति हुई, तथापि याचिका यह भी दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है।
- xxiii. जिस कीमत पर विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देश से भारत में आयात किया गया है वह उसके सामान्य मूल्य से कम रही है जिससे काफी पाटन हुआ है।
- xxiv. संबद्ध देश से आयात पूर्ण दृष्टि से भारत में खपत की सापेक्ष दृष्टि से जांच की अवधि तक पर्याप्त रूप से बढ़े। परिणामस्वरूप इन पाटित आयातों का बाजार हिस्सा बढ़ा और जांच की अवधि तक काफी अधिक रहा और क्षति अवधि और जांच की अवधि में बढ़ती हुई चाल पर रहा है। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा काफी कम और नगण्य स्तरों पर रहा।
- xxv. पाटित आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि और घरेलू उद्योग के बहुत ही खराब बाजार हिस्से का घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंडों पर बुरा प्रभाव था और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री बहुत कम रही और क्षति अवधि में कुछ वृद्धि के बाद भी अनुमानित स्तरों से कहीं कम रही है। यह सिद्ध है कि पाटित आयातों से क्षति से उद्योग की स्थापना पर वास्तविक मंदी के प्रभाव पड़े।
- xxvi. घरेलू उद्योग की कीमत पर पाटित आयातों के प्रतिकूल प्रभावों से घरेलू उद्योग पूरी लागत आगे ले जाने से भी रुका और घरेलू उद्योग को अपनी लागत से भी कम पर बिक्री करनी पड़ी। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को वित्तीय हानियां और नकारात्मक निवेश पर आय की स्थिति बनी। घरेलू उद्योग ने पाटित आयातों के अभाव में लाभदायक स्तरों तक कीमतें बढ़ाई होती।
- xxvii. आयातों/प्रयोक्ताओं ने स्पष्ट रूप से इस कारण आयातित सामग्री को तरजीह दी कि निर्यातकों द्वारा पेश कीमतें पाटित स्तर पर थीं। अकेल पाटित कीमतों से पाटित आयातों द्वारा बाजार हिस्सा लिया गया। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग सभी मोर्चों पर क्षति होने के लिए रह गया था।
- xxviii. यदि पाटन नहीं होता तो घरेलू उद्योग की स्थिति काफी बाजार हिस्से और सामान्य क्षमता उपयोग के साथ बेहतर निष्पादन और लाभप्रदता की होती।
- xxix. यह भी सिद्ध है कि घरेलू उद्योग का निष्पादन अनुमानित स्तरों से कहीं कम रहा है, यह दर्शाता है कि पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को खुद स्थापित होने से रोका और ये तथ्य घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदी दर्शाते हैं।

xxx. घरेलू उद्योग की उत्पादकता निरंतर बढ़ती रही है और उद्योग अपनी लागत काफी नीचे ला पाया तथा ब्याज, मूल्यहास के संदर्भ में लागत जांच की अवधि में न्यूनतम स्तर पर रही है जो आवेदक द्वारा दक्ष प्रचालन दर्शाती है। फिर भी घरेलू उद्योग लाभप्रद स्तरों पर बिक्री नहीं कर पाया क्योंकि पाटित आयात उसकी लागत और कीमत से कम पर थे।

xxxi. अन्य देशों से आयात अधिक अथवा अपाटित अथवा क्षति रहित स्तर पर रहे हैं और अन्य देशों से ये आयात क्षति का कारण नहीं रहे हैं। साथ ही आवेदन पत्र में यह दर्शाया गया है कि निर्यातों, मांग में कोई गिरावट, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन जैसे कारक घरेलू उद्योग को क्षति का कोई कारण नहीं रहे हैं। यह नोट करने योग्य है कि चीन जन.गण. से आयात कीमत कोरिया गणराज्य, जापान आदि जैसे अन्य प्रमुख निर्यातक देशों से कहीं कम रही हैं और इस कम कीमत का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है।

xxxii. चीन जन.गण. के निर्यातक कटौती करने और घरेलू उद्योग के साथ-साथ अन्य आयातों के हिस्से को प्राप्त करने और ऐसे उद्देश्यपूर्ण डिजाइनों को प्रभाव देने का प्रयास कर रहे हैं, पाटित कीमत की पेशकश की जा रही है और परिणामस्वरूप चीन जन.गण. का बाजार हिस्सा आसमान को छूता रहा है।

xxxiii. चीन जन.गण. और अन्य देशों से आयातों की तुलना दर्शाती है कि चीन जन.गण. ने अपनी कीमत इतनी कम रखी है और परिणामस्वरूप चीन जन.गण. से आयात बढ़े, यद्यपि अन्य कम हुए अथवा स्थिर हुए:

	मात्रा मी.ट.				दर रु./कि.ग्रा.			
पंक्ति स्तर	2019- 20	2020- 21	2021- 22	जांच की अवधि (ए)	2019- 20	2020- 21	2021- 22	जांच की अवधि (ए)
चीन	691	281	1214	2650	174.18	168.25	190.67	187.10
जापान	242	189	142	439	205.93	237.71	220.05	220.07
दक्षिण कोरिया	7414	4656	6327	5984	211.91	209.65	223.12	255.07
यूएसए	513	255	540	339	240.59	237.84	197.99	316.95

xxxiv. जांच की अवधि में वास्तविक निष्पादन और प्रत्याशित निष्पादन- घरेलू उद्योग स्पष्ट रूप से जोर देता है कि जांच की अवधि में वास्तविक निष्पादन प्रत्याशित स्तर से कहीं कम रहा है और इस कारक पर भी क्षति की जांच करते समय मापदंड के रूप में विचार किया जाना चाहिए।

xxxv. आवेदक ने जांच की अवधि तक 70-80% क्षमता उपयोग के स्तर में प्रचालन की उम्मीद की जो मांग में बताई गई वृद्धि से आसानी से संभव रहा होता, यदि कोई पाटन नहीं होता। तथापि, घरेलू उद्योग को जांच की अवधि तक भी 25-35% तक के क्षमता उपयोग स्तर पर प्रचालन होने के लिए मजबूर होना पड़ा। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि तक 25-35% की रेंज में बाजार हिस्से की उम्मीद की थी परंतु जांच की अवधि तक 3-5% बाजार हिस्से से कम तक किनारे किया गया था। घरेलू उद्योग ने 15-25% के घरे में आरओसीई के साथ जांच की अवधि तक लाभ दर्ज करने की उम्मीद की थी। तथापि, घरेलू उद्योग को हानियां हुई और आरओसीई नकारात्मक था।

xxxvi. घरेलू उद्योग की जांच की अवधि से पूर्व भी अपनी क्षमता बढ़ाने की योजना थी परंतु प्रतिकूल बाजार स्थिति से जांच की अवधि के बाद क्षमता बढ़ाने में विलंब हुआ। घरेलू उद्योग ने और अधिक लोगों को रोजगार में रखा होता परंतु मात्रात्मक वृद्धि में स्थिरता से रोजगार में कोई वृद्धि करने से रुक गया और वस्तुतः मालसूची में वृद्धि थी जिससे घरेलू उद्योग अपने उत्पादन और कर्मचारी स्तर न्यूनतम रखने के लिए मजबूर हुआ। इस प्रकार, जांच की अवधि में समग्र निष्पादन अनुमानित स्तरों से कहीं कम रहा और इस पहलू पर क्षति की जांच करते समय विचार किया जाए।

xxxvii. क्षति मानदंडों में सुधार के कानूनी स्तर और तर्क – कुछ विरोधी पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि तक क्षति के सभी प्रमुख मापदंडों में सुधार हुआ और इसीलिए कोई क्षति नहीं है। इस तर्क का कानून में कोई आधार नहीं है और नियमों के तहत अपेक्षानुसार क्षति की जांच करते समय इस तर्क को रद्द किया जाना चाहिए।

xxxviii. नियम 11 के तहत नियमावली के अनुबंध-II में यह उल्लेख है कि (i) क्षति के निर्धारण में दोनों की वस्तुपरक जांच शामिल होगी (क) समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव तथा पाटित आयातों की मात्रा और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव। इस प्रकार नियमावली के तहत अपेक्षा प्रस्तुत क्षति के साक्ष्य की उद्देश्यपूर्ण जांच है न कि विरोधी पक्षकारों द्वारा सुझाए गए अनुसार अंतिम मद से अंतिम मद (आधार वर्ष से जांच की अवधि तक) तुलना। आधार वर्ष में कोई वृद्धि क्षति को नहीं नकारती और उद्देश्यपूर्ण जांच की आवश्यकता है।

xxxix. विश्व व्यापार संगठन- पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.1 में निर्धारितानुसार कानूनी की स्थिति समान है। डब्ल्यूटीओ पैनल द्वारा यूरोपीय समुदाय – ब्राजील से मालेबल कॉस्ट आयरन ट्यूब अथवा पाइप फिटिंग पर पाटनरोधी शुल्क, दिनांक 7 मार्च, 2003 में यह स्पष्ट किया गया है कि उद्योग की वर्तमान स्थिति को लेने के लिए कोई जांच अंतिम मुद्दों की तुलना की अपेक्षा अनिवार्य है, जैसा कि निर्यातकों द्वारा दावा किया। डब्ल्यूटीओ पैनल ने यह पाया “7.316 हम सर्वप्रथम उनके अलग अलग विकास और अन्य कारकों में जांच किए गए अन्य कारकों में घटनाओं की तुलना में, दोनों संदर्भ में प्रत्येक क्षतिकारक के संबंध में घटनाओं से संबंधित आंकड़े रखने के इस मूल्यांकन की प्रक्रिया में महत्व पर ध्यान देते हैं। इस प्रकार, सार्थक जांच में अंतिम मुद्दों की तुलना की अपेक्षा प्रत्येक क्षतिकारक और तत्व में वास्तविक मध्यस्ता की वृत्तियों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

जांचकर्ता प्राधिकारी के समक्ष तथ्यों से ली गई सुकर, उपयुक्त और अखंडित तस्वीर लाई जानी चाहिए। निर्धारण में उद्योग की वर्तमान स्थिति को लेने वाले आंकड़ों के पूरे और प्रभावी मूल्यांकन के आधार पर ही समीक्षाकर्ता पैनल यह मूल्यांकन करने में सक्षम होगा कि क्या जांच से लिए गए निष्कर्ष निष्पक्ष और उद्देश्यपूर्ण प्राधिकारी के हैं।”

xi. डब्ल्यूटीओ द्वारा थाइलैंड – पोलैंड से लोहे के एंगल, आकार तथा खंडों अथवा नॉन-अलॉय स्टील और एच-बीम्स पर पाटनरोधी शुल्क, दिनांक 28 सितंबर 2000 में डब्ल्यूटीओ द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि कई कारकों में सकारात्मक प्रवृत्तियां जांचकर्ता प्राधिकारी को किसी क्षति का निर्धारण करने से नहीं रोकते और यह सिर्फ इसलिए है कि इन सकारात्मक प्रवृत्तियों के लिए स्पष्टीकरणों की आवश्यकता होगी। इसकी अपेक्षा कई कारकों में सकारात्मक प्रवृत्तियों के बाद भी क्षति पाई जा सकती है और यह पुनः उद्देश्यपूर्ण जांच और स्पष्टीकरण का मामला है। इस प्रकार आवश्यकता साक्ष्यों की उद्देश्यपूर्ण जांच की है और क्षति का निर्धारण निर्यातकों द्वारा सुझाव गए अनुसार विगत वर्षों और जांच की अवधि के बीच मात्र प्रवृत्ति विश्लेषण का प्रकार्य नहीं है। डब्ल्यूटीओ रिपोर्ट में यह उल्लेख है “7.248. इसके अतिरिक्त, एग्जीबिट थाइलैंड-37 में एसवाईएस से संबंधित सूचीबद्ध रूप में अगोपनीय आंकड़े निहित हैं अथवा उल्लिखित हैं, जिसमें क्षमता, उत्पादन क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा (घरेलू और निर्यात बिक्री सहित); बाजार हिस्सा; मालसूची, निवल लाभ/हानि, निवेश पर आय और रोजगार शामिल हैं। थाई जांचकर्ता प्राधिकारियों के समक्ष तथ्यात्मक साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि 1995 से आईपी तक, एसवाईएस की क्षमता स्थिर रही जबकि उद्योग की स्थिति के संकेतक कई कारक सकारात्मक हो गए, जिनमें उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री (घरेलू और निर्यात बिक्री, दोनों), बाजार हिस्सा, मालसूची और रोजगार शामिल हैं। 7.249. यदि हम यह नहीं मानते कि आईपी के दौरान कई कारकों में ऐसे सकारात्मक प्रवृत्तियां जांचकर्ता प्राधिकारियों को क्षति का अनुकूल निर्धारण करने से आवश्यक रूप से जांचकर्ता प्राधिकारियों को नहीं रोकते, तथापि हमारा यह मत है कि कई कारकों में ऐसे सकारात्मक संचलनों के लिए ऐसी स्पष्ट सकारात्मक प्रवृत्तियों के आलोक में क्यों और कैसे के विवशकारी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी, घरेलू उद्योग करार के अभिप्राय से क्षतिग्रस्त था अथवा रहा। विशेष रूप से हम मानते हैं कि इस स्थिति की पूरे और समझाने वाले स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी कि क्या और कैसे ये सकारात्मक संचलन अन्य किसी कारक और तत्व से बढ़ गए थे जो आईपी के दौरान नकारात्मक दिशा में जाने हो सकते थे।

xli. डब्ल्यूटीओ द्वारा ऊपर निर्धारित सिद्धांत भारत द्वारा कई पाटनरोधी जांच परिणामों में भी दर्शाए गए हैं और किसी भी ऐसे मामले में जांच की अवधि तक प्रमुख मानदंडों में सुधार से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि कोई क्षति नहीं है। इसकी अपेक्षा प्राधिकारी ने उस समय भी क्षति पाई जब कई प्रमुख मानदंडों में जांच की अवधि में सुधार हुआ।

xlii. चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “बसों और लारियों/ट्रकों में प्रयुक्त 16” से अधिक सामान्य रिम डायर कोड वाले रबड़ के फ्लैप और/अथवा ट्यूबों के साथ और ट्यूबों के बिना (ट्यूबलेस टायर सहित) नई/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायरों”, सं-14/14/2015-डीजीएडी – 1 अगस्त, 1017, के आयातों

संबंधी पाटनरोधी जांच में प्रमुख मात्रा और कीमत मापदंडों, दोनों ने आधार वर्ष और जांच की अवधि के बीच वृद्धि दर्शाई है परंतु प्राधिकारी द्वारा क्षति पाई गई थी।

xlili. चीन जन.गण. और हांगकांग के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “प्रिंटेड सर्किट बोर्ड” के आयातों संबंधी पाटनरोधी जांच में – फाइल सं. 06/16/2022-डीजीटीआर दिनांक 29 दिसंबर, 2023, जांच की अवधि तक अर्थात् आधार वर्ष तक इस मामले में प्रमुख मापदंडों में सुधार हुआ परंतु क्षति पाई गई थी। यह नोट किया गया था कि घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंड आधार वर्ष से जांच की अवधि तक बढ़े। यह भी नोट किया गया था कि यद्यपि मात्रा तथा कीमत मापदंडों में सकारात्मक वृद्धि है परंतु मांग में विस्तार की तुलना में कम क्षमता उपयोग के साथ वृद्धि कम है।

xliv. चीन जन.गण., दक्षिण कोरिया, ताईवान और वियतनाम से इलैस्ट्रोमेरिक फिलामेंट यार्न के आयातों संबंधी पाटनरोधी जांच में – फा.सं. 14/29/2015-डीजीएडी दिनांक 24 मार्च, 2017, मामले के तथ्य आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में प्रमुख क्षति मापदंडों में सुधार दर्शाते हैं, यद्यपि कीमत मापदंड फिर भी जांच की अवधि में नकारात्मक रहे। यह पाया गया था “आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में बिक्री और उत्पादन के संदर्भ में घरेलू उद्योग की सकारात्मक वृद्धि थी। तथापि, मांग में काफी वृद्धि के बावजूद पूर्व वर्षों की तुलना में लाभ, नकद लाभ तथा निवेश पर आय जांच की अवधि में नकारात्मक रही। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि मांग में वृद्धि से घरेलू उद्योग ने निवेश पर आय में लाभ, आरामदायक नकद प्रवाह और वृद्धि की उम्मीद की थी। तथापि, घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण उसे प्राप्त नहीं कर पाया। घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि निष्पादन लाभ, निवेश पर आय और मालसूची स्तर के संबंध में नकारात्मक रहा।

xlv. प्राधिकारी और डब्ल्यूटीओ के निर्णयों द्वारा संगत विगत जांच परिणामों की सामूहिक रीडिंग यह दर्शाती है कि कई मापदंडों में केवल वृद्धि से यह स्वतः निष्कर्ष नहीं निकलता कि कोई क्षति नहीं है, जैसा कि विरोधी पक्षकारों ने तर्क दिया है। क्षति की जांच उद्देश्यपूर्ण ढंग से किए जाने की आवश्यकता है और घरेलू उद्योग क्षति संबंधी सकारात्मक साक्ष्य आवेदन पत्र में मौजूद हैं, वे ये दर्शाते हैं कि वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति की मौजूदगी है।

xlvi. यह भी अनुरोध है कि संबद्ध देश से भारत में संबद्ध सामानों का पाटन रोकने के लिए तत्काल उपायों के अभाव में घरेलू उद्योग को और भी अपूर्ण हानियां होंगी। इस प्रकार, शीघ्र ही पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश वर्तमान मामले के तथ्यों में बहुत अनिवार्य है।

xlvii. प्राधिकारी ने प्रपत्र IV में दावा की गई घरेलू बिक्री से संबंधित मूल्यहास की प्रवृत्ति पर प्रश्न उठाए हैं जो मौखिक सुनवाई के बाद लिखित अनुरोध में विस्तार से स्पष्ट किए गए हैं। यह पुष्टि की गई है और स्पष्ट किया गया है कि प्रपत्र I ए में मूल्यहास के दावे आवेदक के रिकॉर्ड के अनुसार हैं और उनमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

xlviii. यह भी स्पष्ट किया गया है कि तथापि पूंजीगत लागत में थोड़ा सा उछाल मूल्यहास के संदर्भ में लागत पर कोई प्रभाव नहीं डालता क्योंकि उत्पादन शुरू होने से लेकर लगाया गया वास्तविक मूल्यहास सरकार की नीति में परिवर्तन के कारण हुए मूल्यहास को लगाने की पद्धति में परिवर्तन के कारण मूल्यहास लागत के अनुमानित आंकड़ों से काफी कम रहा है।

xlix. जिस कीमत पर कोरिया गणराज्य (255रु./किग्रा.), यूएसए (316 रु./किग्रा.) आदि जैसे महत्वपूर्ण अन्य स्रोतों से भारत में उत्पाद आया है, जांच की अवधि में आवेदक की लागत दर्शाती है और कोई असामान्य संख्या नहीं है परंतु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विद्यमान कीमत की सही तस्वीर दर्शाती है।

i. निर्यातकों ने तर्क दिया है कि परियोजना रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं है और उसका प्रयोग क्षति के संदर्भ में उचित नहीं है, इस तर्क का कोई औचित्य नहीं है। जो परियोजना रिपोर्ट संयंत्र स्थापित करते समय तैयार की गई थी और वित्त पोषण तथा आवेदक के अन्य प्रबंधन निर्णयों का भाग रही हैं, किसी उपयुक्त व्यक्ति द्वारा कोई बनाया गया दस्तावेज़ नहीं कहा जा सकता और दस्तावेज़ प्रकृति में हर तरह से गोपनीय और प्राधिकृत है।

ii. आवेदन पत्र में उद्योग की स्थापना में उसके निष्पादन में वास्तविक मंदी दर्शाने के लिए आवश्यक सीमा तक परियोजना रिपोर्ट पर विश्वास रखा गया है। परियोजना रिपोर्ट संयंत्र की स्थापना के समय अर्थात् जांच की अवधि में वास्तविक निष्पादन के समय अनुमानित निष्पादन का मूल्यांकन सक्षम बनाती है और परियोजना रिपोर्ट का प्रयोग करने में कुछ भी अनुचित नहीं है, जैसा कि किसी न्यायिक अदालत द्वारा माना गया है अथवा पाटनरोधी नियमावली के किसी प्रावधान द्वारा माना गया है अथवा प्राधिकारी द्वारा माना गया है। वस्तुतः, प्राधिकारी ने विनाइल टाईल्स जैसे वास्तविक मंदी के मामलों में परियोजना रिपोर्ट का प्रयोग नोट किया है (फा.सं. 6/17/2021-डीजीटीआर दिनांक 23.1.2023)।

iii. प्राधिकारी वर्तमान मामले में क्षति का मूल्यांकन करते समय जांच की अवधि में निष्पादन और परियोजना रिपोर्ट पर आधारित अनुमानित निष्पादन, दोनों का संज्ञान ले सकते हैं। साथ ही जांच की अवधि में कोविड का प्रभाव नहीं था और जांच की अवधि में चीन जन.गण. से संबद्ध सामानों के पाटित और क्षतिकारक आयात के कारण ही पूरा नहीं हुआ था। आवेदक ने अब जांच की अवधि मानी गई अवधि के लिए बहुत उपयुक्त और प्राप्त करने योग्य संख्याओं का अनुमान लगाया और वह पाटित आयातों से कम हुई थी। इस उत्पाद की बाजार में सुदृढ़ मांग और कीमत थी, परंतु बहुत कम कीमतों पर पाटित आयातों ने आवेदक के अवसरों को समाप्त कर दिया। इस प्रकार, अनुमानित संख्याओं पर विचार करना भी संगत है।

iiii. निर्यातकों द्वारा यह भी कहा गया है कि घरेलू उद्योग के समग्र निष्पादन में सुधार हुआ है। यह घरेलू उद्योग की स्थिति की सही रीडिंग नहीं है और कानूनी मानकों तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा विगम मामलों की भी जांच किए जाने की आवश्यकता है।

liv. वृद्धि के बाद भी वास्तविक निष्पादन बहुत खराब रहा है और कहीं भी घरेलू उद्योग द्वारा अनुमानित संख्याओं के निकट नहीं रहा है। साथ ही, निर्यातकों द्वारा उल्लिखितानुसार इन वर्षों में वृद्धि बहुत कम आधार

वर्ष की संख्याओं का प्रभाव है तथा जांच की अवधि में वास्तविक निष्पादन यह दर्शाएगा कि घरेलू उद्योग को सभी मापदंडों पर कम निष्पादन के साथ किसी सार्थक तरीके में स्थापित होने से रोका गया था।

iv. यह भी नोट किया जाए कि निर्यातकों ने उल्लेख किया है कि आवेदक ने वास्तविक क्षति के खतरे का दावा किया है जो सही विवरण नहीं है। आवेदक ने आवेदन पत्र में क्षति का दावा किया है न कि क्षति के खतरे का।

Ivi. निर्यातकों ने निम्नलिखित तालिका के पहले दो कॉलमों में क्षति के संबंध में अपनी टिप्पणियां तालिकाबद्ध करने का प्रयास किया है जिनमें निम्नलिखित खंडन दिया गया है:

मापदंड	निर्यातक द्वारा वास्तविक निष्पादन और टिप्पणियां	घरेलू उद्योग द्वारा खंडन
निम्नलिखित में स्वाभाविक एवं संभावित गिरावट :		
बिक्री	सुधार	सुधार केवल नाममात्र का है, वृद्धि के बाद भी घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 5% से कम है जबकि पाटित आयातों का हिस्सा 25-35% है। इस प्रकार पाटित आयातों ने बाजार मांग का उच्चतर हिस्सा ले लिया जो घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाता है।
लाभ	सुधार	घरेलू उद्योग फिर भी हानियों में था जबकि जांच की अवधि में शामिल अवधि तक उसे अच्छे लाभ में होने के लिए अनुमानित किया गया था। जांच की अवधि में हानियां पाटित आयातों से कीमत और लागत कटौती के कारण कम वसूली की वजह से है। जांच की अवधि में हानियां घरेलू उद्योग को हुई क्षति दर्शाती हैं।
उत्पाद	सुधार	मालसूची में भी सुधार हुआ और यहां तक कि उत्पादन में कुछ वृद्धि के बाद भी पाटित आयातों के कारण क्षमता का 70% से अधिक उपयोग में न लाया गया रहा जो घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाता है।
उत्पादकता	सुधार	यह दर्शाता है कि उत्पादकता में कमी क्षति का

		कारण नहीं रहा है।
निवेश पर आय अथवा क्षमाता का उपयोग	सुधार	घरेलू उद्योग फिर भी हानियों में था जबकि जांच की अवधि के रूप में शामिल अवधि तक उसके 15-25% के अच्छे आरओसीई स्तरों में होने का अनुमान था। पाटित कीमतों ने सीधे ही आरओसीई को प्रभावित किया। घरेलू उद्योग को पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण लागत में कमी का लाभ नहीं मिला।
निम्नलिखित पर वास्तिक एवं संभावित नकारात्मक प्रभाव		
नकद प्रवाह	सुधार	घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में अब भी हानियां थीं जो वर्तमान क्षति दर्शाती हैं। आधार वर्ष में बहुत कम संख्याओं से सुधार का अर्थ क्षति का अभाव नहीं है। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि तक काफी सकारात्मक नकद प्रवाह की उम्मीद की जो पाटन के कारण प्रभावित हुई थी।
मालसूची	सुधार	मालसूची बढ़ी जो यह दर्शाता है कि प्राप्त कम उत्पादन स्तर भी पूरी तरह से बेचा नहीं जा सका और सामग्री मालसूची में समाप्त हुई। यह मापदंड मात्रात्मक क्षति दर्शाता है।
रोजगार/मजदूरी	सुधार	कम निष्पादन। घरेलू उद्योग पाटित आयातों के अभाव में अधिक रोजगार दे सकता था और बेहतर क्षमता उपयोग कर सकता था।
वृद्धि	सुधार	सभी मापदंडों पर कम निष्पादन दिखाई देता है। क्षति मापदंड यह भी दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी हुई थी क्योंकि समग्र निष्पादन उम्मीद और परियोजना रिपोर्ट में अनुमानित स्तरों से कम था। इस प्रकार, क्षति वृद्धि मापदंड पर भी दिखाई देती है।
पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता	सुधार	विस्तार योजनाओं में काफी विलंब हुआ है और यह पाटित आयातों से सृजित प्रतिकूल बाजार स्थितियों का सीधे गिरना है जो इस कारण क्षति दर्शाता है।

Ivii. क्षति के अन्य कारण के संदर्भ में निर्यातकों द्वारा उल्लिखित कारण, यथा – चीनी उत्पाद गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर हैं, कच्ची सामग्री की कीमत में उतार-चढ़ाव, कोविड आदि का प्रभाव घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं रहे हैं। पाटित और कटौती तथा कम कीमत पर बिक्री स्तरों पर आयतों में भारी वृद्धि घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण रहे हैं।

Iviii. आवेदक द्वारा उत्पाद गुणवत्ता में सर्वोत्तम हैं और किसी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं तथा एकमात्र चिंता संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा पेश की जा रही पाटित कीमतों की है। आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की लागत और कीमत से कम है और इन कीमतों ने बाजार में उचित व्यापारिक क्षेत्र कम किया है तथा अकेले ये आयात आवेदक द्वारा दावा की गई क्षति का कारण रहे हैं। आवेदक के गुणवत्ता मुद्दे के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है और न ही प्रयोक्ताओं द्वारा कोई अनुरोध किए गए हैं।

lix. नियोजित पूंजी पर बढ़ी हुई आय के तर्क का कोई औचित्य नहीं है। एनआईपी के लिए आरओसीई की दर प्राधिकारी द्वारा नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर और उनकी सतत परिपाटी के अनुसार निर्धारित की जाती है।

Ix. याचिकाकर्ता द्वारा एकाधिकार के तर्क का कोई औचित्य नहीं है। भारत में संबद्ध सामानों के लगभग कुल 6 ज्ञात उत्पादक हैं। यह एक निर्धारित परिपाटी है कि पाटनरोधी शुल्क से एकाधिकार नहीं होगा। इसकी अपेक्षा यह केवल पाटित आयातों को रोकेगा जिससे घरेलू उद्योग उचित व्यापारिक और उचित बाजार स्थितियों में प्रचालन कर पाएगा। भारत के पास अब अपनी ओर से भारतीय मांग को पूरा करने की क्षमता है और देश इस उत्पाद पर आत्मनिर्भर हो सकता है। यद्यपि जांच की अवधि में मांग-आपूर्ति अंतराल लगभग 5-10% रहा है, तथापि जांच की अवधि के बाद अंतराल शून्य है। भारत में अब कुछ अतिरिक्त क्षमता है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

60. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और विरोधी पक्षकारों के भी विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों पर विचार करते हुए उनका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण नीचे संगत पैराओं में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को हल करता है।

61. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में, "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए" घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करने में, यह जांच करना आवश्यक माना जाता है कि क्या भारत वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों का काफी मात्रा में ह्रास करना अथवा कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग

की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन आदि की मात्रा और मार्जिन पर नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

62. क्षति और कारणात्मक संबंध संबंधी विभिन्न तर्कों के संबंध में विरोधी पक्षकारों का यह तर्क है कि आवेदक के निष्पादन में जांच की अवधि में सभी मानदंडों में सुधार हुआ और आवेदक द्वारा दावा की गई कोई क्षति केवल अन्य कारणों से है। दूसरी ओर, विरोधी पक्षकारों के दावों के खंडन में आवेदक ने दावा किया है कि यद्यपि पूर्व वर्षों की तुलना में जांच की अवधि तक क्षति मानदंडों में सुधार हुआ, तथापि वास्तविक दृष्टि से वास्तविक वृद्धि बहुत खराब रही है और सभी मात्रा तथा कीमत मानदंडों में निष्पादन संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए परियोजना में निवेश करते समय आवेदक द्वारा अनुमानित स्तरों से काफी कम रहा है। आवेदक ने यह भी जोर दिया कि घरेलू उद्योग को क्षति की अवधि में कुछ सुधारों के बाद भी जांच की अवधि में वित्तीय हानियां और नकारात्मक आय हुई। आवेदक ने यह भी दावा किया कि घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तव में मंदी हुई थी जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति भी दर्शाती है। प्राधिकारी ने ऐसे सभी तर्कों और खंडनों पर विचार किया है और जांच के दौरान एकत्रित इस संबंध में तथ्य इस प्रकटन विवरण में प्रकट किए गए हैं जो यथा तथ्यतः उपर्युक्त नियमावली के अनुबंध II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में परिकल्पनानुसार तर्कों को हल करते हैं।

63. इस दावे के संबंध में कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादन कोविड-19 फ्लू महामारी के रूप में भारत में तथा पूरे विश्व में हुए अप्रत्याशित और अभूतपूर्व संकट के कारण ध्यान में नहीं लाया जा सकता, प्राधिकारी नोट करते हैं वर्तमान जांच के लिए निर्धारित जांच की अवधि महामारी से प्रभावित नहीं हुई है और जांच की अवधि के लिए दावे में कोविड-19 महामारी के लिए किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है।

64. इस तर्क के संबंध में कि संबद्ध देश से आयात भारत में केवल मांग और आपूर्ति अंतराल को भरने के लिए आ रहे हैं क्योंकि याचिकाकर्ता भारतीय मांग को पूरा नहीं कर सकता, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध सामानों के लगभग 6 उत्पादक हैं और यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि में भारत में संबद्ध सामानों के लिए उन उत्पादकों के पास उपलब्ध क्षमता भारतीय मांग का पर्याप्त भाग पूरा करने के लिए पर्याप्त थी।

65. इस तर्क के संबंध में कि याचिकाकर्ता की वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट आवेदक की लाभप्रदता दर्शाती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक एक बहु-उत्पाद कंपनी है और अकेले संबद्ध सामानों से संबंधित क्षति पर क्षति जांच के लिए विचार किया गया है।

66. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को हुई तथाकथित कोई क्षति आयातों को छोड़कर अन्य कारकों से है, यथा -चीनी उत्पाद गुणवत्ता में बेहतर हैं, कच्ची सामग्री की कीमतों में उतार-चढ़ाव, कोविड-19 महामारी, आवेदक की आंतरिक समस्याएं, वैश्विक रूप से न्यूनीकृत बाजार स्थितियां, रूस यूक्रेन युद्ध आदि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इनमें से कोई भी तर्क किसी साक्ष्य से समर्थित नहीं है। यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि आवेदक गुणवत्ता मुद्दों के कारण लाभप्रद स्तरों पर बिक्री नहीं कर पाया। महामारी जैसा मुद्दा जांच की अवधि में विद्यमान नहीं था। यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि क्षति का कारण कच्ची सामग्री की कीमत में

वैश्विक उतार-चढ़ाव है। इसी प्रकार, यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि क्षति रूस यूक्रेन युद्ध, आवेदक की आंतरिक समस्याओं आदि के कारण थी।

67. इस तर्क के संबंध में कि वास्तविक निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए परियोजना रिपोर्ट मापदंड नहीं हो सकती, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस मामले में क्षति का मूल्यांकन क्षति की अवधि के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत वास्तविक क्षति के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है और यह जांच क्षति मूल्यांकन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधिदेश के अनुसार किया जाता है।

68. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित करते समय प्राधिकारी को 22% आरओसीई की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, यह नोट किया जाता है कि 22% आरओसीई सतत परिपाटी के अनुसार एनआईपी के निर्धारण के लिए दिया जाता है और ये परिपाटी वर्तमान मामले में भी उपयुक्त मानी जाती है।

69. घरेलू उद्योग के इन दावों के संबंध में कि उद्योग की स्थापना को वास्तविक क्षति और वास्तविक मंदी का सह-अस्तित्व वर्तमान मामले में पूरा साक्ष्य है, प्राधिकारी ने क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन के आधार पर क्षति विश्लेषण किया है। इस संबंध में यह भी नोट किया जाता है कि जांच की अवधि और पिछले तीन वर्षों के लिए क्षति संबंधी सूचना वर्तमान मामले में उपलब्ध है, जो नियम में परिकल्पितानुसार क्षति की वस्तुपरक जांच की अनुमति देता है।

70. जांच की अवधि तक कानूनी मानकों और सभी क्षति मापदंडों में सुधार के तर्क से संबंधित घरेलू उद्योग के दावों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम के तहत अपेक्षा ऐसी जांच के लिए क्षति और संगत तथ्यों की उद्देश्यपूर्ण जांच करने की है जो कि जांच के दौरान एकत्रित जो तथ्य इस जांच के दौरान एकत्रित किए गए थे, इस विवरण में प्रस्तुत हैं। नियम 11 के तहत नियमावली के अनुबंध II में यह उल्लेख है कि (i) क्षति के निर्धारण में समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव और पाटित आयातों की मात्रा तथा (ख) उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव, दोनों शामिल होंगे।

i. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

71. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पूर्ण दृष्टि से अथवा भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में पाटित आयातों में काफी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के लिए प्राधिकारी ने डीजीएस से लिए गए लेन-देनवार आंकड़ों पर विश्वास किया है। संबद्ध सामानों की आयात मात्रा और क्षति जांच अवधि में उसका हिस्सा निम्नलिखित है:

क. मांग का मूल्यांकन/स्पष्ट खपत

72. मांग/स्पष्ट खपत के लिए प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों के कुल आयात और घरेलू उद्योग द्वारा की गई कुल घरेलू बिक्री तथा अन्य सभी भारतीय उत्पादकों द्वारा की गई बिक्री पर विचार किया है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	वार्षिकीकृत जांच की अवधि	पीओआई
संबद्ध आयात	मी.ट.	798	193	1971	3677	4596
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	24	247	461	576
अन्य देश	मी.ट.	5613	3176	6549	6444	8056
कुल आयात	सूचीबद्ध	6411	3368	8520	10,121	12651
घरेलू बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	78	346	607	759
अन्य उत्पादकों की बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	60	234	316	395
मांग	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	53	136	164	206

73. यह देखा जाता है कि जांच की अवधि में उत्पाद के लिए मांग काफी बढ़ी है। जांच की अवधि में भारत में संबद्ध सामानों के लिए मांग आधार वर्ष की तुलना में और तत्काल पूर्व वर्ष की तुलना में भी बढ़ी है। यह भी नोट किया जाता है कि मांग जांच की अवधि और आधार वर्ष के बीच 64% की वृद्धि के साथ जांच की अवधि में उच्चतम स्तर पर रही है और जांच की अवधि और तत्काल पूर्व वर्ष के बीच 28% की वृद्धि है।

ख. पूर्ण एवं सापेक्ष दृष्टि से संबद्ध देश के आयात

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	वार्षिकीकृत जांच की अवधि	पीओआई
संबद्ध आयात	मी.ट.	798	193	1971	3677	4596
मांग	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	53	136	164	206

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	वार्षिकीकृत जांच की अवधि	पीओआई
उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	222	648	1085	1357
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात :						
खपत	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	46	181	280	280
उत्पादन	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	11	38	42	42

74. यह नोट किया जाता है कि खपत के संबंध में पाटित आयातों का हिस्सा आधार वर्ष तथा तत्काल पूर्व वर्ष की भी तुलना में जांच की अवधि तक बढ़ा है। तथापि, भारत में उत्पादन के संबंध में पाटित उत्पाद जांच की अवधि और आधार वर्ष के बीच कम हुए हैं परंतु जांच की अवधि तथा तत्काल पूर्व वर्ष के बीच बढ़े हैं।

ii. घरेलू उद्योग पर आयातों का कीमत प्रभाव

75. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में तथाकथित पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हुई है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव कीमतों को न्यूनीकृत करना अथवा कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हुई होती। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग पर कीमतों के प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत न्यूनीकरण तथा कीमत ह्रास, यदि कोई है, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) और क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

क) कीमत कटौती

76. कीमत कटौती विश्लेषण के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयातों के पहुंच मूल्य से की गई है। घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत का परिकलन करते समय सभी कर, छूट, रियायत और कमीशन घटा दिए गए हैं और कार्यगत स्तर पर बिक्री वसूली पाटित आयातों के पहुंच मूल्य के साथ तुलना के लिए निर्धारित की गई है। तदनुसार संबद्ध देश से पाटित आयातों के कटौती प्रभाव निम्नलिखित निकलते हैं:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
निवल बिक्री वसूली	रु./कि.ग्रा.	***	***	***	***
निवल बिक्री वसूली	प्रवृत्ति	100	129	120	149
पहुंच कीमत	रु./कि.ग्रा.	181	179	197	197
कीमत कटौती	रु./कि.ग्रा.	(***)	***	***	***
कीमत कटौती	%	(***)	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज %	0 – (10)	15-25	0-10	15-25

77. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयात भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली से कम कीमत पर आते रहे हैं जिससे सकारात्मक कीमत कटौती हुई है। यह भी नोट किया जाता है कि यद्यपि आयातों की पहुंच कीमत इन वर्षों में बढ़ी थी, तथापि पाटित आयातों की पहुंच कीमत और घरेलू उद्योग की एनएसआर के बीच अंतराल बहुत अधिक रहा जिससे जांच की अवधि में 15-25% की रेंज में कीमत कटौती हुई।

ख) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

78. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का ह्रास कर रहे हैं और क्या इन आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों का न्यूनीकरण करना अथवा कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हुई होती। क्षति की अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की तुलना निम्नलिखित रूप में पाटित आयातों की पहुंच कीमत के आलोक में की गई थी:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई	वार्षिकीकृत - पीओआई
बिक्री लागत	रु./कि.ग्रा.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	54	49	49
बिक्री कीमत	रु./कि.ग्रा.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	120	149	149
पहुंच कीमत	रु./कि.ग्रा.	181	179	197	197	197
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	109	109	109

79. उपर्युक्त तालिका के अनुसार सूचना यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों की पहुंच कीमत भी आधार वर्ष और जांच की अवधि के बीच बढ़ी जबकि घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत जांच की अवधि में कम हुई।

80. आयातों की पहुंच कीमत जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से काफी कम रही है।

iii. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

81. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव की उद्देश्यपूर्ण जांच शामिल होगी। इन

उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और तत्वों जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए।

82. क्षति और कारणात्मक संपर्क संबंधी अनिवार्य तथ्यों को प्रकट करते समय प्राधिकारी ने इस जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए उद्देश्यपूर्ण रूप से क्षति मापदंडों की जांच की है ताकि उनके औचित्य के आधार पर उन सभी अनुरोधों को हल किया जा सके।

क) उत्पादन, क्षमता, बिक्री और क्षमता उपयोग

83. उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नलिखित था:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई	वार्षिकीकृत पीओआई
संस्थापित क्षमता	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	125	100
उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	222	648	1357	1085

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई	वार्षिकीकृत पीओआई
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	222	648	1085	1085
घरेलू बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	78	346	759	607

84. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि क्षति की अवधि में क्षमता स्थिर रही, तथापि उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू उद्योग की बिक्री आधार वर्ष और जांच की अवधि के बीच बढ़ी।

ग) मांग में बाजार हिस्सा

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई	वार्षिकीकृत पीओआई
संबद्ध आयात	मी.ट.	798	193	1971	4596	3677
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	24	247	576	461
अन्य देश	मी.ट.	5613	3176	6549	8056	6444
कुल आयात	मी.ट.	6411	3368	852	12651	10,121
घरेलू बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	78	346	759	607
अन्य उत्पादकों की बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	60	234	395	316
मांग	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	53	136	206	164
निम्नलिखित का भारतीय मांग में हिस्सा ;						
संबद्ध आयात	%	12	6	22	34	34

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई	वार्षिकीकृत पीओआई
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	46	181	280	280
अन्य देश	%	86	92	74	60	60
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	86	70	70
कुल आयात	%	98	97	96	94	94
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	98	96	96
घरेलू बिक्री	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	147	254	369	369
अन्य उत्पादकों की बिक्री	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	172	192	192
भारतीय उत्पादकों की बिक्री	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	136	228	313	313

85. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों का बाजार हिस्सा आधार वर्ष और जांच की अवधि के बीच बढ़ा है।

ख) लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ

86. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई	वार्षिकीकृत पीओआई
लाभ/हानि (पीबीटी)	रु./कि.ग्रा.	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(117)	(25)	(5)	(5)
पीबीआईटी	रु./कि.ग्रा.	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(118)	(25)	(5)	(5)

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई	वार्षिकीकृत पीओआई
नकद लाभ	रु./कि.ग्रा.	(***)	(***)	(***)	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(185)	(31)	1	1
औसत नियोजित पूंजी	लाख रु.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	42	65	88	88
नियोजित पूंजी पर आय	%	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	I सूचीबद्ध	(100)	(217)	(133)	(31)	(31)

87. उपयुक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के प्रमुख लाभप्रदता मापदंडों में पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में सुधार दर्शाया। तथापि, कर पूर्व लाभ प्रति यूनिट, ब्याज और कर पूर्व लाभ तथा नियोजित पूंजी पर आय जैसे सभी प्रमुख मापदंडों के संदर्भ में लाभप्रदता जांच की अवधि में नकारात्मक रही है।

रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

88. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग का रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई	वार्षिकीकृत पीओआई
रोजगार	संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	144	264	264
मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	221	248	383	306
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.ट./व्यक्ति	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	205	450	411	411
मजदूरी	रु./कि.ग्रा.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	38	28	28

89. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग में रोजगार के स्तर में वृद्धि हुई है और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में भी जांच की अवधि तक सुधार हुआ। तथापि, उत्पादन की प्रति यूनिट मजदूरी ने जांच की अवधि तक गिरावट दर्शाई है।

ग) पाटन मार्जिन की मात्रा

90. पाटन की मात्रा उस सीमा का संकेतक है जिस तक भारत में आयात पाटित किए जा रहे हैं। जांच ने यह दर्शाया है कि पाटन मार्जिन जांच की अवधि में सकारात्मक है।

घ) मालसूची

91. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई	वार्षिकीकृत पीओआई
मालसूची	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	227	356	644	644

92. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग में मालसूची जांच की अवधि तक बढ़ी।

ड.) वृद्धि

93. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रमुख मात्रा और लाभप्रदता मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि जांच की अवधि में सकारात्मक रही है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	वार्षिकीकृत- जांच की अवधि
उत्पादन	%	122	192	67
घरेलू बिक्री मात्रा	%	(22)	346	75
क्षमता उपयोग	%	122	192	67
मालसूची	%	127	57	81
रोजगार	%	8	33	83
प्रति.कि.ग्रा. बिक्री कीमत	%	28	(7)	24
प्रति कि.ग्रा. बिक्री लागत	%	21	(55)	(10)

नियोजित पूंजी पर आय	%	(117)	39	76
प्रति इकाई लाभ	%	(17)	79	81
प्रति इकाई पीबीआईटी	%	(18)	79	82

94. घरेलू उद्योग का यह दावा है कि सकारात्मक वृद्धि बहुत खराब रही है। अधिक बाजार हिस्से से घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का उपयोग बेहतर कर सकता था जिससे मात्रात्मक मापदंडों में अधिक वृद्धि भी हो सकती थी। अपाटित कीमत से घरेलू उद्योग बेहतर कीमत वसूल कर सकता था जिससे कीमत और लाभप्रदता मापदंडों में वृद्धि हो सकती थी। मापदंड के रूप में वृद्धि यहां इस संदर्भ में नोट की गई है।

च) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

95. घरेलू उद्योग ने दावा किया कि स्थापित क्षमताओं को किसी सार्थक उपयोग स्तर पर अभी पहुंचना है और उत्पादन में पांच वर्ष से अधिक के बाद भी नकारात्मक आय पाटित आयातों द्वारा बनी प्रतिकूल स्थिति दर्शाती है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग एक बहु-उत्पाद कंपनी है और इसीलिए पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता अकेले विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के आधार पर नियंत्रित नहीं हो सकती, यद्यपि संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए किए गए निवेश से आरओसीई जांच की अवधि में नकारात्मक नोट किया गया है जो आगे पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।

छ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

96. संबद्ध देश से आयात कीमतों की जांच, लागत संरचना में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारक जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, आदि यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देश से आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम है जो काफी कीमत कटौती कर रहे हैं। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध सामानों के लिए मांग क्षति की अवधि में काफी वृद्धि दर्शा रही थी और इसीलिए वह घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला कारक नहीं हो सकता। इस प्रकार, यह नोट किया जा सकता है कि घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटित आयात हैं।

ज) क्षति मार्जिन की मात्रा/कम कीमत पर बिक्री

97. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा दी गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर और जांच की अवधि के लिए प्रैक्टिसिंग लागत लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन के परिकलन के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए क्षति रहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत के निर्धारण के लिए क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यही व्यवहार यूटिलिटियों के साथ किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन लागत में कोई असाधारण

अथवा गैर-आवर्ती व्यय न लगाए जाएं। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल अचल परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर उपयुक्त आय (कर-पूर्व 22% की दर से) नियमावली के अनुबंध-III निर्धारितानुसार क्षति रहित कीमत निकालने के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी और वह अपनाई जा रही है।

98. संबद्ध देश से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत निर्धारित की है।

99. उपर्युक्त निर्धारित पहुंच कीमत और क्षति रहित कीमत के आधार पर उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है।

क्षति मार्जिन

क्र.सं.	देश	उत्पादक	एनआईपी अम.डा./किग्रा.	पहुंच मूल्य अम.डा./किग्रा.	क्षति मार्जिन अम.डा./किग्रा.	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन (रेंज %)
1	चीन जन.गण.	शांगडोंग केलेसे न्यू मैटिरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड और शंघाई सैलेसी इंडस्ट्री डवलेपमेंट कं. लिमिटेड, शांगडोंग ब्रांच	***	***	***	***	10-20
2	चीन जन.गण.	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	20-30

झ. गैर-आरोपण विश्लेषण

100. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षित है कि वे पाटित आयातों को छोड़कर किसी अन्य ज्ञात कारक की जांच करें जो साथ-साथ घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति पाटित आयातों के कारण न हो। इस संबंध में जो कारक संगत हो सकते हैं उनमें अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन तथा उत्पादकता शामिल हैं। नीचे यह जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों का घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान हो सकता है।

क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

101. आयात सूचना यह दर्शाती है कि संबद्ध देश को छोड़कर जांच की अवधि में कोरिया गणराज्य, यूएसए और जापान से संबद्ध सामानों का पर्याप्त आयात रहा है। वस्तुतः संबद्ध देश के रूप में जापान के विरुद्ध भी आवेदन पत्र दायर किया गया है। परंतु जांच की शुरुआत के समय यह नोट किया गया था कि जापान के मामले में पाटन मार्जिन नकारात्मक है। यह भी नोट किया जाता है कि कोरिया गणराज्य और यूएसए से भी आयात संबद्ध देश से उच्चतर कीमतों पर रहे हैं और आवेदक ने दावा किया कि इन कीमतों से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। इस प्रकार, ऐसे अन्य आयातों पर घरेलू उद्योग को क्षति के लिए विचार नहीं किया जा सकता।

ख) निर्यात निष्पादन

102. प्राधिकारी ने अपने विश्लेषण के लिए ही घरेलू प्रचालनों के आंकड़ों पर विचार किया है। किसी भी दशा में, जांच की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निर्यातों में वृद्धि रही है जो निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई	वार्षिकीकृत- जांच की अवधि
निर्यात बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	3388	7526	25978	20782

ग) खपत के पैटर्न में मांग परिवर्तनों में संकुचन

103. यह नोट किया जाता है कि क्षति की अवधि में संबद्ध सामानों की मांग बढ़ी है। इस प्रकार यह नोट किया जा सकता है कि घरेलू उद्योग को क्षति किसी काफी स्तर तक मांग में संकुचन के कारण नहीं थी।

घ) व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

104. संबद्ध सामानों का आयात किसी भी तरह प्रतिबंधित नहीं है और वे स्वतंत्र रूप से देश में आयात किए जा सकते हैं। किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा यह बताने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में कोई परिवर्तन हुआ है।

ड) प्रौद्योगिकी में विकास

105. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में काफी परिवर्तन दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है जिससे कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने हाल ही में अपना संयंत्र स्थापित और अक्तूबर, 2018 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया।

च) खपत के पैटर्न में परिवर्तन

106. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान और भारत में आयातित संबद्ध सामान तुलनीय हैं तथा अंतिम प्रयोक्ता इन सामानों को परस्पर परिवर्तनीय पाते हैं। खपत के पैटर्न में संभावित परिवर्तन ऐसे कारक नहीं हैं जिनसे घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति हो सकती हो।

छ) अन्य उत्पादों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन

107. प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों के निष्पादन के संबंध में ही आंकड़ों पर विचार किया है। अतः, उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

ज) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

108. निर्धारितानुसार, प्रति कर्मचारी उत्पादकता में जांच की अवधि तक वृद्धि दर्शाई है। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादकता में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का कोई कारण नहीं रहा है।

ब. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे**ब.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

109. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने जांच प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू उत्पादक का एकाधिकार स्थापित होगा और जन हित में नहीं होगा।
- ii. पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारतीय स्थानीय उत्पादन अस्थिर आपूर्ति में हो सकता है और ग्राहक अन्य उत्पादों में जा सकते हैं। सीमित और अस्थिर भारतीय स्थानीय उत्पादन एकाधिकारिक स्थिति बनाएंगे और वे 100 मिलियन अम.डा. उत्पाद बाजार, व्यापार और संबद्ध कार्यों को समाप्त कर देंगे।
- iii. भारत में एक्रिलिक सॉलिड सर्फेस की मांग विभिन्न कारकों से निरंतर बढ़ती जा रही है, यथा निर्माण एवं इंटीरियर डिजाइन उद्योग में वृद्धि, बढ़ती हुई निपटान योग्य आय और बढ़ रही उपभोक्ता प्राथमिकताएं, जबकि भारतीय उत्पादक संबद्ध सामानों के लिए भारतीय मांग पूरा नहीं कर सकते। भारत में संबद्ध सामानों के केवल 4 उत्पादक हैं जिनमें प्रत्येक के पास 1-2 उत्पादन लाइनें हैं, जो भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- iv. चीन और कोरिया के पास 10-15 उत्पादन लाइनें हैं। अतः, विशेष रूप से कोविड के बाद भारतीय आयातकों ने महसूस किया कि वे मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह भारतीय उत्पादकों पर निर्भर नहीं रह सकते और अन्य देशों से आयात आरंभ किया। आज 20 से अधिक ब्रांड चीन और कोरिया से ओईएम आधारित आयातों के साथ सक्रिय हैं। ओईएम मोड भारतीय आयातकों को भारी आत्मविश्वास देता है और भारतीय ग्राहकों के लिए अधिक विकल्प देता है।

v. जन हित का निर्धारण इस मामले में पाटनरोधी शुल्क न लगाए जाने के पक्ष में रहता है।

ब.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

110. जांच प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. संबद्ध सामान प्रीमियम विवेकपूर्ण भवन सामग्री है जिसका सबसे सामान्य रूप से प्रयोग सीबनहीन काउंटरटॉप स्थापनाओं, अंतिम प्रयोक्ता के विकल्प के आधार पर वाणिज्यिक स्थानों में और कुछ घरों में बाथरूम वेनिटी आदि के लिए किया जाता है। परिणामस्वरूप, ये उत्पाद ऐसे निर्माण/अंतिम प्रयोग के अनुप्रयोगों में प्रमुख लागत मद नहीं बनता। न ही यह भारी भवन निर्माण सामग्री है जिसका प्रयोग पारंपरिक टाइलों आदि जैसे घरों के सामान्य आवास प्रयोजनों के लिए किया जाए।
- ii. आवेदक द्वारा अनुरोध किए गए अनुसार पाटनरोधी शुल्क प्रयोक्ताओं पर कोई भारी प्रभाव नहीं डालेगा, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा दायर आर्थिक हित की प्रश्नावली में दर्शाया गया है और प्रभाव 0.50% से कम होगा जिसे पाटनरोधी शुल्क का कोई काफी प्रभाव नहीं माना जा सकता।
- iii. आवेदक के पास लागत/कीमत के आंकड़ों का समर्थन करने के लिए प्रभाव विश्लेषण प्रस्तुत करने हेतु प्रयोक्ताओं की वित्तीय सूचना तक पहुंच नहीं है। तथापि, निम्नलिखित रूप में अनुमान आवेदक की समझ के आधार पर उत्पाद की प्रकृति और प्रयोग पर विचार करते हुए किया गया है।

विवरण	मूल्य रु.
छोटे आकार की वाणिज्यिक भवन परियोजनाओं की अनुमानित लागत	10000000
संबद्ध सामानों की अनुमानित आवश्यकता (आयातों की पहुंच कीमत पर 212.89/कि.ग्रा. की दर से लगभग 500 कि.ग्रा.)	106445
इस समय की स्थिति के अनुसार कुल लागत में संबद्ध सामानों का हिस्सा	1.06%
याचिका में क्षति मार्जिन विवरण के अनुसार 67.48 प्रति कि.ग्रा. की दर से संभावित पाटनरोधी शुल्क के रूप में संबद्ध देश का भारित औसत क्षति मार्जिन (दावे के अनुसार मार्जिन से कम)	33740
अनुमानित संभावित पाटनरोधी शुल्क के बाद नई लागत	140185
किसी पाटनरोधी शुल्क के बाद कुल लागत में संबद्ध सामानों का हिस्सा	1.40%
संभावित पाटनरोधी शुल्क के कारण अंतिम प्रयोक्ता कल लागत में वृद्धि	0.34%
रेंज	0.25%-0.50%

- iv. अनुमान यह दर्शाते हैं कि आवेदक के अनुरोध के अनुसार पाटनरोधी शुल्क प्रयोक्ता पर कोई भारी प्रभाव नहीं डालेगा और यह प्रभाव लगभग 0.50% से कम होगा जिसे पाटनरोधी शुल्क का कोई भारी प्रभाव नहीं माना जा सकता। प्रयोक्ता आवेदक को अनुरोध किए गए अनुसार पाटनरोधी शुल्क के जरिए सुनिश्चित उचित

व्यापारिक क्षेत्र की सहायता से भारत में खुद को स्थापित करने की अनुमति दी जाती है तो प्रयोक्ताओं को कुल मिलाकर लाभ होगा।

v. यदि आवेदक को अनुरोध किए गए अनुसार पाटनरोधी शुल्क के जरिए सुनिश्चित उचित व्यापारिक क्षेत्र की सहायता से भारत में मौजूद रहने की अनुमति दी जाती है तो प्रयोक्ताओं को कुल मिलाकर लाभ होगा। किसी भी दशा में, प्रयोक्ता अन्य देशों से चीन जन.गण. से काफी अधिक कीमत पर आयात कर रहे हैं और चीन पर पाटनरोधी शुल्क से कोई कीमत वृद्धि नहीं होगी।

vi यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि पाटनरोधी शुल्क जैसे उपायों का अंतिम प्रयोक्ताओं पर कुछ प्रभाव हो सकता है परंतु किसी भी तरीके से वह भार स्वरूप नहीं होगा और शेष सुविधा क्षतिकारक पाटित आयातों को रोकने में होगी जो भारत में इस उत्पाद के लिए मजबूत विनिर्माण आधार की स्थापना को प्रभावित कर रहा है। भारत में एक विनिर्माण आधार अंततः भारतीय प्रयोक्ताओं के हित में होगा। आज की स्थिति के अनुसार, प्रयोक्ता उनके द्वारा पेश की गई पाटित कीमतों के कारण आयातित सामग्री को तरजीह दे रहे हैं। किसी उपाय के बाद भी प्रयोक्ता उचित एवं उपयुक्त कीमतों ही दे रहे होंगे न कि उससे कुछ अधिक क्योंकि किसी भी दशा में शुल्क पाटन और क्षति के मार्जिन से कम नहीं हो सकते।

vii. यह नोट करना भी व्यावहारिक है कि पाटनरोधी शुल्क उपायों की मांग केवल चीन जन.गण. से पाटित और क्षतिकारक आयातों की वृद्धि ही की जाती है और पर्याप्त आयात कारिया गणराज्य, जापान, यूएसए से हो रहे हैं तथा प्रयोक्ता किसी पाटनरोधी शुल्क के बिना इन स्रोतों से आयात जारी रख सकते हैं।

viii. आवेदक ने जांच की अवधि के बाद की घटना के रूप में, संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षमताएं संस्थापित की। यह अतिरिक्त क्षमता बहुत पहले बन जानी चाहिए थी क्योंकि मशीनें 2022 में ही खरीदी गई थी परंतु प्रक्रिया में पाटित आयातों से सृजित प्रतिकूल बाजार स्थिति के कारण विलंब हुआ। नई क्षमता मार्च 2024 के महीने में तकनीकी रूप से सक्रिय हुई हैं, यद्यपि यह संयंत्र विद्यमान क्षमता की तरह अब व्यापक रूप से बेकार है क्योंकि पाटित आयातों से दबाव अब भी जारी है। इस समय भारत में संबद्ध सामानों के लिए पूरी मांग को पूरा करने की क्षमता है और जांच की अवधि के बाद की अवधि में कोई मांग-आपूर्ति अंतराल नहीं है और जांच की अवधि में भी अंतराल मुश्किल से 5% था।

ix. निर्यातकों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पाटनरोधी शुल्क घरेलू उत्पाद का एकाधिकार स्थापित करेगा और जनहित में नहीं होगा। यह तर्क पूर्णतः आधारहीन है। भारत में संबद्ध सामानों के कुल लगभग 6 ज्ञात उत्पादक हैं। यह एक निर्धारित सिद्धांत है कि पाटनरोधी शुल्क से एकाधिकार नहीं बनेगा। इसकी अपेक्षा इससे केवल पाटित आयात रुकेंगे जिससे घरेलू उद्योग उचित व्यापारिक और उचित बाजार स्थितियों में प्रचालन करने में संक्षम होगा। भारत के पास अब अपने बल पर भारतीय मांग को पूरा करने की क्षमता है और देश इस उत्पाद पर आत्मनिर्भर हो सकता है। यद्यपि जांच की अवधि में मांग आपूर्ति अंतराल लगभग 5-10% रहा है तथापि जांच की अवधि के बाद अंतराल शून्य है। भारत में अब कुछ अतिरिक्त क्षमता है।

अ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

111. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन सामान्य रूप में पाटन की अनुचित व्यापारिक परिपाटियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके, जो देश के सामान्य हित में है।

112. प्राधिकारी ने यह विचार किया कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाने से जन हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह प्रभाव निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने भारतीय बाजार में सामानों की उपलब्धता पर शुल्कों लगाए जाने के प्रभाव, उत्पाद के प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग पर प्रभाव और आम जनता पर प्रभाव की जांच की। यह निर्धारण वर्तमान जांच प्रक्रिया में प्रस्तुत अनुरोधों और साक्ष्य के आधार पर है।

113. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने उपभोक्ताओं के लिए उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना देने हेतु एक प्रश्नावली भी निर्धारित की। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर परिवर्तनीयता, उपभोक्ताओं की स्रोतों में जाने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण नई स्थिति में समायोजन में विलंब अथवा उसके बढ़ने की संभावना वाले कारकों के संबंध में सूचना मांगी।

114. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क से आयात प्रतिबंधित नहीं होते बल्कि केवल यह सुनिश्चित होता है कि आयात उचित कीमतों पर बाजार में आए। इस प्रकार उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर संबद्ध सामानों के आयात के लिए व्यापक विकल्प और आजादी मिलती रहेगी जिससे बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होगी।

115. प्राधिकारी ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी जो इस जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजी गई थी। घरेलू उद्योग और 2 उत्तरदाता निर्याताओं/उत्पादकों ने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित स्वरूप और तरीके में आर्थिक हित प्रश्नावली प्रस्तुत की। यह नोट किया जाता है कि एक प्रयोक्ता/आयातक ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दिया है। वस्तुतः संबद्ध सामानों के किसी प्रयोक्ता/आयातक ने इस मामले में उत्तर नहीं दिया है। घरेलू उद्योग ने शुल्क के संभावित प्रभाव की मात्रा दी है परंतु निर्यातकों अथवा किसी अन्य पक्षकार ने ऐसी कोई मात्रा नहीं दी है। यह देखा जाता है कि शुल्क लगाए जाने से उन प्रयोक्ताओं पर काफी प्रभाव नहीं पड़ेगा जो वाणिज्यिक संपत्तियों आदि के प्राथमिक रूप से विकास विकास करता है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रभाव नगण्य होगा। इसके अतिरिक्त, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने सत्यापनीय सूचना नहीं दी है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध सामानों पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इन उपायों का कुछ प्रयोक्ताओं पर प्रभाव पड़ सकता है परंतु वह जारी अनुचित व्यापार परिपाटियों के जोखिम के विरुद्ध संतुलित होना चाहिए।

116. इस तर्क के संबंध में कि उत्पाद के लिए मांग आपूर्ति अंतराल है और किसी पाटनरोधी शुल्क से घरेलू उत्पादक का एकाधिकार बनेगा, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आयातों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य नहीं करता। भारत में संबद्ध सामानों के लगभग 6 उत्पादक हैं। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का प्रयोजन सामान्य रूप में अनुचित व्यापार परिपाटियों से हुए व्यापार के ह्रास के मुद्दे को हल करना है ताकि खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति स्थापित की जा सके। किसी भी दशा में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि देश में

मांग आपूर्ति अंतराल है तो विदेशी उत्पादक निश्चित रूप से उचित और अपाटित कीमत पर उत्पाद का निर्यात कर देश में अंतराल को भर सकते हैं। तथापि, मांग आपूर्ति अंतराल की मौजूदगी उत्पाद के पाटन का औचित्य नहीं बनाती। प्रयोक्ता उद्योग पर प्रभाव के संबंध में घरेलू उद्योग ने अंतिम प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव 1% से कम बताया है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अंतिम प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नहीं बताया है और न ही किसी वास्तविक प्रयोक्ता ने कोई उत्तर दायर किया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस अनुरोध को नोट करते हैं कि संबद्ध सामान वाणिज्यिक संपत्तियों में प्रयुक्त प्राथमिक रूप से प्रीमियम और विवेकपूर्ण भवन सामग्री है तथा समग्र निर्माण में संबद्ध सामानों का हिस्सा प्रश्रुत उत्पाद की प्रकृति के मद्देनजर बहुत ही कम है। संबद्ध सामानों के बहुत मौके के प्रयोग हैं।

117. इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारतीय स्थानीय उत्पादन अस्थिर आपूर्ति में हो सकता है और ग्राहक अन्य उत्पादों में जा सकते हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैर-संबद्ध देशों से विदेशी उत्पादकों और घरेलू उत्पादकों में आपूर्ति की पर्याप्त क्षमता है।

118. इस दावे के संबंध में कि चीन और कोरिया में लगभग 10-15 उत्पादन लाइनें हैं और आज 20 से अधिक ब्रांड चीन और कोरिया से ओईएम आधारित आयातों से भारत में सक्रिय हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क से किसी भी तरह प्रयोक्ताओं को उपलब्ध विकल्प प्रतिबंधित नहीं होंगे परंतु इसके साथ ही विदेशी उत्पादकों द्वारा अपनाई जा रही पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटी से भारतीय उत्पादकों को हो रही क्षति समाप्त होगी। साथ ही, विदेशों में किए गए भारी पैमाने का उत्पादन पाटित स्तरों पर भारत को निर्यातों के लिए कोई औचित्य नहीं है। यह भी नोट करने योग्य है कि कोरिया गणराज्य से आयात उच्चतर कीमत पर रहे हैं और आवेदक ने उन आयातों से किसी क्षति का दावा नहीं किया है।

ट. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

119. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे प्रकटन विवरण में निर्धारित आंकड़ों के आधार पर शुल्क लागू करें।
- ii. उत्पादक/निर्यातक का नाम अंतिम जांच परिणाम में “शांगडोंग केलेसी न्यू मैटिरियल टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड” और “शंघाई सेल्सी इंडस्ट्री डेवलेपमेंट कंपनी, लिमिटेड शांगडोंग ब्रांच” के रूप में उल्लिखित किया जाए।

ट.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

120. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. प्राधिकारी सकारात्मक जांच परिणाम के मामले में शुल्क तालिका में यह विनिर्दिष्ट कर सकते हैं कि वैकल्पिक विवरण जैसे “100%” एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसेस, प्योर एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसेस, कोरियन शीट्स,

हाई मैक्स एक्रिलिक शीट्स, पीएमएमए से बनी मोटेली शीट्स, पीएमएमए में शीट्स, स्टैरोन सॉलिड सर्फेस, क्रियोन मिथाइल मेथाक्रिलिक रेसिन सॉलिड सर्फेस शीट, मिथाइल मेथाक्रिलिक रेजिन शीट्स आदि जो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात करते समय संबद्ध वस्तु के वर्णन का हिस्सा हैं। यह अनुरोध याचिका का भी हिस्सा रहा है।

ii. यथा प्रकट तथ्य वर्तमान मामले में पाटन दर्शाते हैं। तथापि, चीन जन.गण. से उत्पादकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन 0-15% के स्तर पर काफी कम लगता है। ऐसा कमतर मार्जिन चीन जन.गण. के लिए निर्धारित काफी कम सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत से किए गए अपर्याप्त समायोजन के ही कारण हुआ है।

iii. घरेलू उद्योग के दावे के अनुसार कुल लागत पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया जाए क्योंकि एनआईपी के लिए समायोजन अलग उद्देश्य के लिए और नियमावली के अलग अनुबंध के अन्तर्गत किया गया है।

iv. कोरिया गणराज्य से जापान की तुलना में काफी अधिक आयात हुआ है और इसके मद्देनजर कोरिया गणराज्य से आयात कीमत पर इस मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए आधार के रूप में विचार किया जाए। नियम के अनुबंध I में एनएमई देश के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण का प्रावधान है और किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत को सामान्य मूल्य का आधार माना जा सकता है। यहां तक कि नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के अन्तर्गत क्रम के अनुसार यह विकल्प सबसे पहले आता है।

v. निर्यात कीमत को वैट की वापसी दर और प्रदत्त वैट में अंतर के लिए 4% तक समायोजित करना अपेक्षित है इससे कारखानाद्वारा स्तर पर उत्पाद की तुलनीयता पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

vi. वैट अंतर के लिए समायोजन के अलावा, निर्यात कीमत के लिए गौण पैकिंग लागत पर विचार करते हुए निवल निर्यात कीमत के प्रयोजनार्थ समायोजन करना अपेक्षित है क्योंकि घरेलू उद्योग की गौण पैकिंग लागत को अनुमत व्यय के रूप में अनुमति नहीं दी गई है।

vii. सुधारों के बाद भी घरेलू उद्योग की स्थिति लाभप्रदता मापदंडों की दृष्टि से नकारात्मक रही है और मात्रात्मक मापदंडों के अनुसार निष्पादन घरेलू उद्योग की उम्मीद और अनुमानों से काफी कम रहा है। इस प्रकार, नियम के अनुसार वास्तविक क्षति बिल्कुल स्पष्ट है।

viii. भारत में आने वाले पाटित आयात घरेलू उद्योग कीमत में कटौती कर रहे हैं और कीमत ह्रास प्रभाव भी स्पष्ट हैं। ऐसे कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और एनआईपी से भी कम रही हैं जिससे क्षति मार्जिन सकारात्मक रहा है और घरेलू उद्योग पर पाटन के प्रभाव की गंभीरता का पता चलता है।

ix. बताए गए तथ्यों से पता चलता है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति केवल पाटित आयातों के कारण हुई है।

x. भारतीय उत्पादक भारत में उत्पाद की मांग को पूरा कर सकते हैं और यथा सूचित एडीडी का प्रभाव प्रयोक्ताओं पर बिल्कुल मामूली होगा। तथापि, घरेलू उद्योग का वर्तमान बाजार हिस्सा बिल्कुल मामूली है और एडीडी नहीं लगाए जाने पर स्थिति और खराब हो जाएगी।

xi. भारत के पास पीओआई के बाद की अवधि में समूची भारतीय मांग को पूरा करने की क्षमता है और इस उत्पाद में अधिक निवेश आकर्षित करने की क्षमता है और भारत इस महत्वपूर्ण उत्पाद में और अधिक उत्पादकों को देख सकता है यदि भारत में अनुकूल बाजार स्थिति उपलब्ध हो। वर्तमान में भी संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने के लिए 5 उत्पादकों की क्षमता के साथ घरेलू विनिर्माण आधार काफी संभावनाओं वाला और विशाल है और एडीडी से भारतीय उत्पादकों को पाटित आयातों द्वारा हुई क्षति से निपटने में मदद मिलेगी। इस समय पाटित आयातों का भारत में उत्पाद के बाजार में काफी अधिक हिस्सा है और भारतीय उत्पादक भारत में उत्पाद के उत्पादन में भारी निवेश के लिए उसमें एक उचित हिस्सा पाने की योग्यता रखते हैं।

ट.2 प्राधिकारी द्वारा जांच

121. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की जांच की है। यह नोट किया जाता है कि जो टिप्पणियां पुनरावृत्ति की हैं और जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जांच की गई है तथा अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराओं में पर्याप्त रूप से हल कर दी गई हैं, संक्षिप्तता के लिए प्राधिकारी द्वारा प्रकटन पश्चात जांच में उन्हें दोहराया नहीं जा रहा है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की नीचे जांच की गई है:

i. निर्धारित पाटन मार्जिन के कम होने के दावे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन मार्जिन को नियमावली के अनुबंध I के अधिदेश और प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया का पालन करते हुए, निर्धारित किया गया है। इस संबंध में विचार किए गए सभी तथ्यों का प्रकटन किया गया है। तथापि, निर्धारण में किसी तथ्यात्मक त्रुटि पर ध्यान नहीं दिलाया गया है।

ii. इस दावे के संबंध में चीन जन.गण. के मामले में सामान्य मूल्य को कोरिया गणराज्य से आयात कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की प्रक्रिया के दौरान, ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया और ऐसे किसी अनुरोध को इस स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

iii. अप्रदत्त वैट और गौण पैकिंग की दृष्टि से, समायोजनों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपलब्ध तथ्यों के अनुसार आवश्यक समायोजन पहले ही किए गए हैं और उनके ब्यौरे पहले ही प्रकट किए गए हैं। प्रकटन पश्चात के दावे भी किसी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं और उन पर विचार नहीं किया जा सकता है।

ठ. निष्कर्ष और सिफारिशें

122. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों, दी गई सूचना, किए गए अनुरोधों और ऊपर रिकॉर्ड किए गए अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा उपर्युक्त पाटन के विश्लेषण और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के आधार पर प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:

i. विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसेस” है। नीचे दिए गए उत्पाद वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ पीयूसी के दायरे में शामिल नहीं हैं:

क) प्योर एक्रिलिक शीट्स।

ख) फर्नीचर की सजावट और वाहनों की रैपिंग के लिए एक्रिलिक लेमिनेट्स तथा पीईटी/पीवीसी फिल्म।

ग) पोलिएस्टर सॉलिड सर्फेस शीट्स।

घ) संशोधित एक्रिलिक सॉलिड सर्फेस।

ii. संबद्ध उत्पाद के आयात दर्शाते हैं कि आयातों ने 100% एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसेस, प्योर एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसेस, कोरियन शीट्स, हाई मैक्स एक्रिलिक शीट्स, पीएमएमए से बनी मोटेली शीट्स, पीएमएमए में शीट्स, स्टैरोन सॉलिड सर्फेस, क्रियोन मिथाइल मेथाक्रिलिक रेजिन सॉलिड सर्फेस शीट, मिथाइल मेथाक्रिलिक रेजिन शीट्स आदि को संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात के समय आयातकों द्वारा वर्णित किया गया है। ऐसे वैकल्पिक नामों का प्रयोग संबद्ध वस्तु के वर्णन के भाग के रूप में किया गया है।

iii. विचाराधीन उत्पाद में एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसेस शामिल हैं जिनमें उनकी मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, रंग और डिजाइन पर ध्यान नहीं दिया जाता है और मानी गई माप की यूनिट किलोग्राम/टन (किलोग्राम/मी.ट.) में सूचित उत्पाद का भार है।

iv. विचाराधीन उत्पाद को प्लास्टिक और उसकी वस्तुओं से संबंधित सीमा प्रशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 और उप शीर्ष 392051 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है जो पोली (मिथाइल मेथाक्राइलेट) शीट से संबंधित है, जो संबद्ध वस्तु के लिए एक समर्पित वर्गीकरण नहीं है। संबद्ध वस्तु के आयातों की सूचना आवेदक के दावे के अनुसार शीर्षों 39205111, 39205119, 39205199, 39206390, 39219039, 39269069 और 35069999 के अन्तर्गत किया गया है। सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष केवल संकेतात्मक है और उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं हैं।

v. प्राधिकारी ने पीसीएन पद्धति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों को प्रस्ताव, यदि कोई हो, देने का अवसर दिया था। तथापि, कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त पीयूसी के दायरे संबंधी टिप्पणियों पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ध्यान दिया गया है और उसके बाद हितबद्ध पक्षकारों को पीयूसी का दायरा अधिसूचित किया गया है।

vi घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु एडी नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु है।

- vii. चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच की शुरुआत के लिए आवेदन मैसर्स स्टाइलैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था। आवेदक ने जांच अवधि/क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया और वह संबद्ध उत्पाद के किसी निर्यातक/आयातक से भी संबद्ध नहीं है। आवेदक के अलावा, भारत में संबद्ध वस्तु के 5 अन्य उत्पादक भी हैं।
- viii. यद्यपि आवेदक ने अनुमानित आधार पर अन्य उत्पादकों के उत्पादन की मात्रा निर्धारित करके कुल भारतीय उत्पादन का अनुमान लगाया है, तथापि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने सकल भारत के उत्पादन का कोई साक्ष्य नहीं दिया है। भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन और बिक्री के संबंध में कोई प्रकाशित सूचना नहीं है। इसलिए सरकारी राजपत्र और डीजीटीआर की वेबसाइट पर जांच की शुरुआत अधिसूचित करने के अलावा, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पहचान की गई विभिन्न कंपनियों को उनके उत्पादन, आयात और किसी अन्य सूचना, जिसे वे संगत मानते हों, को मंगाने के लिए लिखा था। परंतु किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।
- ix. रिकॉर्ड में सूचना के आधार पर प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि आवेदक का उत्पादन भारतीय उत्पादन का 75-85% बनता है। अतः, प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अन्तर्गत घरेलू उद्योग है और नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।
- x. प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावे से संतुष्ट हैं और उन्होंने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना को रिकॉर्ड किया है।
- xi. संबद्ध वस्तु के एक उत्पादक अर्थात् शानडोंग केलेसी न्यू मैटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने शंघाई सेलिसि इंडस्ट्री डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (व्यापारी) के साथ वर्तमान जांच में स्वयं को पंजीकृत किया है और विहित निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। उक्त उत्पादक के लिए उसके उत्तर के आधार पर अलग मार्जिन निर्धारित किया गया है।
- xii. निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु का पाटन मार्जिन सकारात्मक है, न्यूनतम सीमा से अधिक है और संबद्ध देश से गैर-भागीदार उत्पादकों के लिए काफी अधिक है।
- xiii. पीओआई के दौरान भारत में संबद्ध वस्तु के लिए मांग में आधार वर्ष की तुलना में और तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में भी वृद्धि हुई है।
- xiv. खपत के सापेक्ष रूप में पाटित आयातों में आधार वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में भी पीओआई में वृद्धि हुई है। तथापि, भारत में उत्पादन के संबंध में पाटित आयातों में पीओआई और आधार वर्ष के बीच गिरावट आई है परंतु पीओआई और तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के बीच वृद्धि हुई है।

xv. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से कम कीमत पर प्रवेश कर रहे हैं, परिणामस्वरूप कीमत कटौती सकारात्मक है। पीओआई के दौरान, कीमत कटौती का स्तर काफी अधिक रहा है।

xvi. कोई कीमत ह्रास या न्यूनीकरण नहीं हुआ है। तथापि, आयातों की पहुंच कीमत पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से काफी कम रही है।

xvii. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर ऐसे पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे हैं:

क) घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंड में आधार वर्ष और पीओआई के बीच क्षमता उपयोग, उत्पादन और बिक्री की दृष्टि से वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग के मालसूची के स्तर में भी इसी अवधि में वृद्धि हुई है।

ख) घरेलू उद्योग की क्षमता क्षति अवधि के दौरान स्थिर रही है। परंतु पीओआई के दौरान उत्पाद की मांग में वृद्धि होने के बावजूद घरेलू उद्योग के पास काफी अप्रयुक्त क्षमता थी।

ग) संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के बाजार हिस्से और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में भी आधार वर्ष और पीओआई के बीच वृद्धि हुई है। तथापि, संबद्ध आयातों का पीओआई तक घरेलू उद्योग द्वारा रखे गए बाजार हिस्से की तुलना में समग्र रूप से काफी अधिक बाजार हिस्सा रहा है।

घ) पीबीटी, पीबीआईटी और आरओसीई की दृष्टि से लाभप्रदता पीओआई के दौरान ऋणात्मक रही है। यद्यपि, आधार वर्ष और पीओआई के बीच इन मापदंडों में वृद्धि हुई है। नकद लाभ भी पीओआई के दौरान केवल थोड़े सकारात्मक रहे हैं। पीओआई के दौरान मुख्य लाभप्रदता मापदंडों में ऐसे घाटे घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर काफी प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाते हैं।

ड) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

च) प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति रहित कीमत और संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत पर विचार करते हुए, यह देखा गया है कि क्षति मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।

छ) गैर-आरोपण विश्लेषण दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को किसी अन्य कारक की वजह से क्षति नहीं हुई है और घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

ज) प्राधिकारी ने उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की जांच की है। यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तु प्रीमियम बिल्डिंग मैटेरियल है, जिसका प्राथमिक रूप से कमर्शियल रीयल एस्टेट के विकास में प्रयोग किया जाता है और पाटनरोधी शुल्क लगाने से ऐसे अंतिम उपभोक्ताओं पर कोई खास प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

123. पाटनरोधी नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, पाटन, क्षति, और कारणात्मक संबंध के बारे में जांच शुरू करने और संचालित करने के बाद प्राधिकारी का विचार है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना

पाटन और परिणामी क्षति की भरपाई के लिए अपेक्षित है। प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।

124. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क को संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं:

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष/उप शीर्ष	वस्तुओ का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूओएम	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	39205111, 39205119, 39205199, 39206390, 39219039, 39269069, 35069999.	एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसेस *	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई	शांगडोंग केलेसे न्यू मैटिरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड और शंघाई सैलेसी इंडस्ट्री डवलेपमेंट कं. लिमिटेड, शांगडोंग ब्रांच	शून्य	कि.ग्रा.	अम.डा.
2	-वही.-	-वही.-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	ऊपर क्र.सं. 1 में दर्शाए गए उत्पादक को छोड़कर कोई अन्य उत्पाद	0.18	कि.ग्रा.	अम.डा.
3	-वही.-	-वही.-	चीन जन.गण. के अलावा कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	0.18	कि.ग्रा.	अम.डा.

* वैकल्पिक विवरण जैसे 100% एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसेस, प्योर एक्रिलिक सॉलिड सर्फेसेस, कोरियन शीट्स, हाई मैक्स एक्रिलिक शीट्स, पीएमएमए से बनी मोटेली शीट्स, पीएमएमए में शीट्स, स्टैरोन सॉलिड सर्फेस,

क्रियोन मिथाइल मेथाक्रिलिक रेजिन सॉलिड सर्फेस शीट, मिथाइल मेथाक्रिलिक रेजिन शीट्स शामिल हैं। नीचे दिए गए उत्पाद वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ पीयूसी के दायरे में शामिल नहीं हैं:

क) प्योर एक्रिलिक शीट्स।

ख) फर्नीचर की सजावट और वाहनों की रैपिंग के लिए एक्रिलिक लेमिनेट्स तथा पीईटी/पीवीसी फिल्म।

ग) पोलिएस्टर सॉलिड सर्फेस शीट्स।

घ) संशोधित एक्रिलिक सॉलिड सर्फेस।

ड. आगे की प्रक्रिया

125. इन अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

(Directorate General of Trade Remedies)

New Delhi the 26 December 2024

FINAL FINDINGS

Case No. AD (OI)-6/2023

A. **BACKGROUND OF THE CASE**

F. No. 06/06/2023-DGTR

1. **M/s Stylam Industries Limited** (hereinafter also referred to as “Applicant” or “Petitioner”) filed an application/petition seeking initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “**Acrylic Solid Surfaces**” (hereinafter also referred to as “Subject goods” or “Product Under Consideration” or “PUC”) originating in or exported from China PR and Japan before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred to as the “Rules”).
2. The Authority, on the basis of sufficient *prima facie* evidences submitted by the applicant, issued a public notice vide notification file **no. 6/6/2023-DGTR dated 29th December, 2023**, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from **China PR** (herein after referred to as the subject country) and to recommend the amount of anti-dumping duty (ADD),

which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry. Though the applicant has filed the petition proposing China PR and Japan as the subject countries as noted above, the Authority has considered only “China PR” as the “subject country” since the dumping margin in case of Japan has been noted as negative at the time of initiation.

B. PROCEDURE

3. The procedure described herein below has been followed with regard to the subject investigation:
 - a. The Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.
 - b. The Authority issued a public notice dated 29th December, 2023 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject country.
 - c. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 29th December, 2023, to the embassy of the subject country in India, the known producers and exporters from the subject country, known importers, importer/user associations, the domestic industry, other known Indian producers and any other interested parties, as per the addresses/email made available by the applicant. The interested parties were advised to provide relevant information in the form and manner prescribed and make their submissions known in writing within the prescribed time-limit, in accordance with Rules 6(2) and 6(4) of the Rules.
 - d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Government of the subject country, through its embassy in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.
 - e. The embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.
 - f. The Authority issued economic interest questionnaire (EIQ) to all interested parties and the concerned ministry. Response to EIQ was submitted by the domestic industry and responding exporters. None of the users or importers filed any EIQ.
 - g. The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules;
 - i. Jumei Acrylic Manufacturing Co Ltd
 - ii. Anhui Xintao Photoelectric Technology Co.
 - iii. Foshan Opaly Composite Materia
 - iv. Solidtop Co Ltd
 - h. In response, the following exporters/producers from the subject country filed exporter's questionnaire response and also Economic Interest Questionnaire;
 - i. Shandong Kelesi New Material Technology Co., Ltd (Producer/exporter)
Shanghai Sailisi Industry Development Co., Ltd. Shandong Branch (trader)
 - i. Apart from the above exporters, it has been intimated by Guangdong Hantai Decoration Material Co., Ltd that the Company is not engaged in the production or exportation of Acrylic Solid

Surfaces vide their email dated 22.01.2024. Another party namely Xintao International Group sought clarifications on the scope of product under consideration.

- j. The Authority sent importer's questionnaire to the following known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rule.
- i. Jain Timpoly LLP
 - ii. Prima Marketing Corporation
 - iii. Merino Industries Limited
 - iv. Jakan Impex Private Limited
 - v. Performance Specialty Products India Private Limited
 - vi. Goche Interior Solutions
 - vii. Bansal Sales Corporation Private Limited
 - viii. Silver International Private Limited
 - ix. Santosh Timber Trading Co Limited
 - x. Globentis Internationals Private. Limited
 - xi. Patel Wood Syndicate
 - xii. Rehau Polymers Private Limited
 - xiii. National Plywood Industries Limited
 - xiv. Ambica Corporation Limited
 - xv. Performance Specialty Products India Pvt Ltd
 - xvi. Dupont Specialty Products India Private Limited
- k. In response, none of the importers/users have responded within the stipulated time and filed any user/importer's questionnaire response. However, the following party filed comments on the scope of PUC;
- i. Dupont Specialty Product India Pvt. Ltd.
- l. Another party namely Rehau Polymers Private Limited expressed its interest in the investigation. However, no submissions were filed eventually by this party.
- m. Apart from the above noted foreign producers/exporters and importers/users, interest in the subject investigation were expressed by Marbonex and Durlax Top Surface Ltd who have claimed themselves to be producers of subject goods in India. No questionnaire responses have been filed by these parties.
- n. The Authority vide para 8 of the initiation notification dated 29th December, 2023 sought comments on the scope of the product under consideration (or PUC) within 30 days of initiation. However, no proposals/comments on PCN have been filed by any of the interested parties including the applicant. Nevertheless, certain clarifications on the scope of the PUC have been sought by some of the interested parties. After a careful consideration of the comments as received from all the interested parties including the applicant on the scope of PUC, a clarification on the scope of PUC was communicated vide a notice published on the DGTR website on 13th February, 2024. It has also been clarified in the said notice that since none of the interested parties have made any proposals for any PCN, a decision has been taken not to adopt any PCN methodology in this investigation. Thereafter, two weeks' time was granted to all the interested parties to file the responses from the date of issuance of the above-stated notice i.e. 13th February, 2024.
- o. The Authority made available a non-confidential version of the evidence presented/made by the various interested parties to the other parties by directing the parties to exchange such submissions via e-mail based on the list of interested parties relevant for the subject investigation made available to all relevant parties on the website of the DGTR.

- p. The Authority has, relied upon the DGCIS transaction-wise details of imports data for computation of the volume of imports and its analysis after due examination of the transactions.
- q. The Non-Injurious Price (NIP) has been determined based on the cost of production and the cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure–III to the Anti-Dumping Rules so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

The period of investigation (POI) adopted by the Authority for the present investigation is 1st April 2022 to 30th June 2023. The injury investigation period covers the periods 1st April 2019 – 31st March 2020, 1st April 2020 – 31st March 2021, 1st April 2021 – 31st March 2022 and the POI. POI in the present investigation covers fifteen months and such a period is considered appropriate in the facts of the present investigation.

- r. Desk verification of the information provided by the applicant, responding producer and exporter from the subject country and other interested parties to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary modification/rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of present notification.
- s. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in the first oral hearing held on hybrid mode on 14th June, 2024. All the parties who had attended the oral hearing were provided an opportunity to file written submissions by 21st June, 2024 followed by rejoinders, if any by 28th June, 2024. The Authority convened another oral hearing due to the appointment of the new Designated Authority and another opportunity of oral hearing has been provided to all the interested parties to present their views orally followed by submissions in writing pursuant to the judgement of the Hon'ble Supreme Court in the matter of 'Automotive Tyre Manufacturers' Association (ATMA) vs. Designated Authority, delivered in Civil Appeal No. 949 of 2006 on 07-01-2011. Accordingly, the Authority held the second oral hearing on 21st October, 2024. The interested parties who presented their views in the 2nd oral hearing, were directed to file their written submissions of the views expressed orally by 24th October, 2024, followed by rejoinder submissions due by 29th October, 2024, if any. The interested parties were further directed to share the non-confidential version of the written submission submitted by them with the other interested parties.
- t. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government to all interested parties on 18 December 2024. The Authority has examined all the post-disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.
- u. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation so far, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered and addressed by the Authority, in the final findings.
- v. Information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing

information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on a confidential basis.

- w. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.
- x. ‘***’ in the final findings represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- y. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US\$1 = Rs.81.47.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

- 4. At the stage of initiation, the product under consideration and like article were defined as:

A. **PRODUCT UNDER CONSIDERATION (PUC)**

3. The product under consideration is “**Acrylic Solid Surfaces**” originating in or exported from China PR. Acrylic Solid Surfaces are non-porous, low-maintenance, manmade materials produced from Methyl Methacrylate resin (MMA), Aluminium Hydroxide and Pigments as the key raw materials and are used for surfaces such as countertops and can be inferred as a trendy building material with peerless hygiene and aesthetic properties. It can mimic the appearance of granite, marble, stone, and other naturally occurring materials, and can be joined nearly invisibly by a trained craftsman. The product under consideration is used in seamless countertop installations and also for a wide range of applications, for residential and commercial purposes such as in kitchen countertops, sinks, bathrooms, furniture fittings, wall cladding etc. Acrylic Solid Surfaces are also used in commercial spaces such as offices, retail outlets, malls, hotels and bars, hospitals and clinics etc.

4. Acrylic Solid Surfaces are typically manufactured in sheet form in sizes such as 760mmX2440mm, 760mmX3660mm etc. for fabrication into finished countertops, commonly in thicknesses such as 6mm, 12mm etc., they can also be cast into a variety of shapes, including sinks, shower pans and bathtubs. Subject goods in sheet form can also be heated and bent into three-dimensional shapes using a process called thermoforming, which adds to the versatility of the product. There are more colour and design options available in the subject goods in comparison to natural stones which has over the period contributed to the demand for subject goods.

5. The product descriptions as per the import information shows that the importers have used descriptions such as 100% Acrylic solid surfaces, Pure Acrylic solid surfaces, Corian Sheets, Hi Macs Acrylic Sheets, Montelli Sheets made of PMMA, PMMA Sheets, Staron Solid Surface, Krypton Methyl Methacrylic Resin Solid Surface Sheet, Methyl Methacrylic Resin Sheets etc while importing the subject goods from subject country.

6. The product under consideration as considered in the application covers Acrylic Solid Surfaces irrespective of their thicknesses wherein the unit of measurement considered is weight of the product reported in Kilograms (Kg).

7. *The product under consideration is classified under Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975 and the code 3920. The product has been imported under the subheadings- 39205111, 39205119, 39205199, 39206390, 39219039, 39269069 and 35069999. However, it is possible that the subject goods may also be imported under other headings and therefore, the customs tariff heading is indicative only and is not binding on the scope of the product.*

1. *B. LIKE ARTICLE*

2. *9. The applicant has claimed that the subject goods, which have been alleged to be dumped in India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no known differences in the technical specifications, quality, functions and end use of the two products. The Authority notes that the two are prima facie technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.*

5. Following the initiation, certain clarifications on scope of the PUC were sought by some of the interested parties. After a careful consideration of the comments as received from the interested parties, it was clarified vide notice dated 13th February, 2024 that the below products are not covered in the scope of the PUC for the purpose of present investigation;

- a) *Pure acrylic sheets.*
- b) *Acrylic laminates and PET/PVC films for furniture decoration and vehicle wrapping.*
- c) *Polyester solid surface sheets.*
- d) *Modified Acrylic Solid Surfaces.*

6. It was also mentioned in the notice dated 13th February, 2024 published on the DGTR website that the specifics of any exclusion(s) are subject to determination throughout the investigation process and will be communicated in the final findings as deemed appropriate by the Authority. Hence, the final findings cover all relevant facts gathered during the investigation concerning the scope of PUC and Like Article which shall form the basis of final determinations in this regard by the Authority.

3. **C.1. Submissions by the other interested parties**

7. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the product under consideration and like article:

- i. Clarifications on the scope of PUC have been sought by some of the interested parties. The parties sought a clarification on whether the following products are covered in the scope of PUC or not;
 - a) Pure acrylic sheet, claimed to be distinct from the described Acrylic Solid Surface (PUC) which is a composite material made from different substances.
 - b) Acrylic laminates and PET/PVC films for furniture decoration and vehicle wrapping claimed to be distinct due to physical properties and application scenarios.
 - c) Polyester solid surface sheets, claimed to be distinct due to their resin composition and market applications.
 - d) Modified Acrylic Solid Surfaces claimed to be distinct due to differences in raw material composition, physical properties, and performance characteristics etc.

- ii. Marbonex, claiming to be Indian producer of Unsaturated Polyester and Acrylic Solid Surface Sheets, requested that imposition of anti-dumping duties on the import of Unsaturated Polyester and Acrylic Solid Surface Sheets from China must be considered.
- iii. Marbonex also submitted "polyester solid surface sheets" and "modified acrylic solid surfaces" share the same characteristics as the product currently under consideration, namely "acrylic solid surface." Both products serve identical end-user applications related to interiors and architectural purposes. The substantial import of Polyester solid surface sheets and Modified Acrylic Solid Surfaces from China poses a significant challenge to domestic producers, making it increasingly difficult for us to cover our production costs. Hence, "polyester solid surface sheets" and "modified acrylic solid surfaces" also should be made part of the investigation.

C.2. Submissions of the domestic industry

8. The domestic industry has submitted as follows with regard to the product under consideration and like article:

- i. The product under consideration is "Acrylic Solid Surfaces" originating in or exported from China PR.
- ii. Acrylic Solid Surfaces are non-porous, low-maintenance, manmade materials produced from Methyl Methacrylate resin (MMA), Aluminium Hydroxide and Pigments as the key raw materials and are used for surfaces such as countertops and can be inferred as a trendy building material with peerless hygiene and aesthetic properties. It can mimic the appearance of granite, marble, stone, and other naturally occurring materials, and can be joined nearly invisibly by a trained craftsman.
- iii. The product under consideration is used in seamless countertop installations and also for a wide range of applications, for residential and commercial purposes such as in kitchen countertops, sinks, bathrooms, furniture fittings, wall cladding etc. Acrylic Solid Surfaces are also used in commercial spaces such as offices, retail outlets, malls, hotels and bars, hospitals and clinics etc.
- iv. Acrylic Solid Surfaces are typically manufactured in sheet form in sizes such as 760 mm X 2440 mm, 760 mm X 3660 mm etc. for fabrication into finished countertops, commonly in thicknesses such as 6 mm, 12 mm etc., they can also be cast into a variety of shapes, including sinks, shower pans and bathtubs.
- v. Subject goods in sheet form can also be heated and bent into three-dimensional shapes using a process called thermoforming, which adds to the versatility of the product. There are more colour and design options available in the subject goods in comparison to natural stones which has over the period contributed to the demand for subject goods.
- vi. The product descriptions as per the import information shows that the importers have used descriptions such as 100% Acrylic solid surfaces, Pure Acrylic solid surfaces, Corian Sheets, Hi Macs Acrylic Sheets, Montelli Sheets made of PMMA, PMMA Sheets, Staron Solid Surface, Krion Methyl Methacrylic Resin Solid Surface Sheet, Methyl Methacrylic Resin Sheets etc while importing the subject goods from subject country. Authority may consider all such descriptions/names as part of the product under consideration.

- vii. The product under consideration as considered in the application covers Acrylic Solid Surfaces irrespective of their thicknesses wherein the unit of measurement considered is weight of the product reported in Kilograms (Kg).
- viii. The product under consideration is classified under Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975 and the code 3920. The product has been imported under the subheadings- 39205111, 39205119, 39205199, 39206390, 39219039, 39269069 and 35069999. However, it is possible that the subject goods may also be imported under other headings and therefore, the customs tariff heading is indicative only and is not binding on the scope of the product.
- ix. With regard to the clarification on the scope of PUC sought by certain parties pertaining to a) Pure acrylic sheets, b) Acrylic laminates and PET/PVC films for furniture decoration and vehicle wrapping, c) Polyester solid surface sheets, d) Modified Acrylic Solid Surfaces, applicant submits that such product is not covered in scope of PUC provided in the application. Hence, it can be noted that such products are not part of PUC. The PUC covers Acrylic Solid Surfaces which has MMA/PMMA resin as its key input and the product for which clarification is sought apparently has other resins as the key input.
- x. With regard to the request of certain other domestic producers for the inclusion of polyester solid surface sheets/ unsaturated Polyester sheets and modified acrylic solid surfaces within the scope of PUC, it is our submission that such products are not 'like article' to the subject goods as per the contours of the Rules governing 'like article' and the products have differences in terms of basic raw materials, inherent product properties, and cost and price though the end uses may overlap to some extent along with comparable physical appearance of the product in some cases. Modified Acrylic Solid Surfaces is estimated to be much cheaper than subject goods (40-50% cheaper) and they are clearly different articles in terms of technical and commercial terms. Subject goods have MMA/PMMA resin as its key raw material whereas Modified Acrylic Solid Surfaces uses other cheaper resins which impacts the overall product composition and properties. Even if MMA/PMMA is claimed to be used in Modified Acrylic Solid Surfaces, the concentration of the same may not be more than 1-10% whereas MMA/PMMA concentration in Acrylic Solid Surface is normally in the range of 40-45%. Inclusion of Modified Acrylic Solid Surfaces in the PUC will distort the product comparisons and also the dumping and injury margin determination since Modified Acrylic Solid Surfaces is a much cheaper product by its very nature in comparison to the subject goods.
- xi. With regard to the claim of certain Indian producers for the inclusion of modified solid surfaces also in the scope of PUC, any of the parties claiming Modified Acrylic Solid Surfaces as like article to the subject goods must demonstrate beyond doubt that Modified Acrylic Solid Surfaces are like article to the subject goods. In the absence of such demonstration, the claim has no meaning though the applicant has no reservations in its inclusion or exclusion as such. Likewise, there are no comparability between subject goods and polyester or unsaturated polyester which also cannot be included in the scope of PUC.
- xii. It is also submitted that even though Modified Acrylic Solid Surfaces is not a like article to the PUC in the present matter as per the understanding of the applicant, instances of any importer mis-declaring subject goods as Modified Acrylic Solid Surfaces to evade any duties on Acrylic Solid Surfaces cannot be ruled out, and in that case, the applicant reserves its right to approach the authorities to seek appropriate actions against any such attempts to circumvent the duties, if any.

C.3. Examination by the Authority

9. The product under consideration in the present investigation is “Acrylic Solid Surfaces” originating in or exported from China PR. Acrylic Solid Surfaces are non-porous, low-maintenance, manmade materials produced from Methyl Methacrylate resin (MMA), Aluminium Hydroxide and Pigments as the key raw materials and are used for surfaces such as countertops and can be inferred as a trendy building material with peerless hygiene and aesthetic properties. It can mimic the appearance of granite, marble, stone, and other naturally occurring materials, and can be joined nearly invisibly by a trained craftsman. The product under consideration is used in seamless countertop installations and also for a wide range of applications, for residential and commercial purposes such as in kitchen countertops, sinks, bathrooms, furniture fittings, wall cladding etc. Acrylic Solid Surfaces are also used in commercial spaces such as offices, retail outlets, malls, hotels and bars, hospitals and clinics etc.
10. It is clarified that the below products are not covered in the scope of PUC for the purpose of the present investigation;
 - a) *Pure acrylic sheets.*
 - b) *Acrylic laminates and PET/PVC films for furniture decoration and vehicle wrapping.*
 - c) *Polyester solid surface sheets.*
 - d) *Modified Acrylic Solid Surfaces.*
11. Acrylic Solid Surfaces are typically manufactured in sheet form in sizes such as 760mmX2440mm, 760mmX3660mm etc. for fabrication into finished countertops, commonly in thicknesses such as 6mm, 12mm etc., they can also be cast into a variety of shapes, including sinks, shower pans and bathtubs. Subject goods in sheet form can also be heated and bent into three-dimensional shapes using a process called thermoforming, which adds to the versatility of the product. There are more colour and design options available in the subject goods in comparison to natural stones which has over the period contributed to the demand for subject goods.
12. The product descriptions as per the import information shows that the importers have used descriptions such as 100% Acrylic solid surfaces, Pure Acrylic solid surfaces, Corian Sheets, Hi Macs Acrylic Sheets, Montelli Sheets made of PMMA, PMMA Sheets, Staron Solid Surface, Krion Methyl Methacrylic Resin Solid Surface Sheet, Methyl Methacrylic Resin Sheets etc while importing the subject goods from subject country. Such alternative names used are part of the description of the subject goods.
13. The product under consideration as considered in the application covers Acrylic Solid Surfaces irrespective of their thicknesses, length, width, color and design and the unit of measurement considered is weight of the product reported in Kilograms/Tons (Kg/MT).
14. The product under consideration is classified under Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975 pertaining to Plastics and articles thereof and further under subheading 392051 which pertains to poly (methyl methacrylate) sheet which is not a dedicated classification for the subject goods. Imports of the subject goods have been reported under subheadings 39205111, 39205119, 39205199, 39206390, 39219039, 39269069 and 35069999 as claimed in the application. The customs tariff heading is indicative only and is not binding on the scope of the product.
15. The Authority has also considered the arguments of the interested parties regarding the scope of the PUC and has examined the same based on the relevant information available on record and by calling further from the interested parties as found necessary.

16. With regard to the clarifications on the scope of PUC as has been sought by some of the interested parties concerning Pure acrylic sheets, Acrylic laminates and PET/PVC films for furniture decoration and vehicle wrapping, Polyester solid surface sheets and Modified Acrylic Solid Surfaces, it is confirmed that such products are not part of the PUC. As clarified by the applicant, while subject goods have Methyl Methacrylate (MMA)/ poly-Methyl Methacrylate (PMMA) resin also called acrylic resin as the key raw material, the facts available do not show that Pure acrylic sheets, Acrylic laminates and PET/PVC films for furniture decoration and vehicle wrapping and Polyester solid surface sheets also have MMA/PMMA as its key raw material. Thus, such products do not fall within the scope of subject goods.
17. Also, the facts available suggest that Modified Acrylic Solid Surfaces have differences in terms of basic raw materials, inherent product properties, and cost and price though the end uses may overlap with the subject goods to some extent. Modified Acrylic Solid Surfaces are estimated to be much cheaper than subject goods (40-50% cheaper). This is for the primary reasons that subject goods have MMA/PMMA resin as their key raw material whereas Modified Acrylic Solid Surfaces uses other cheaper resins which impacts the overall product composition and properties and also the cost and price of the product. As ascertained by the applicant, even if MMA/PMMA is claimed to be used in Modified Acrylic Solid Surfaces, the concentration of the same may not be more than 1-10% whereas MMA/PMMA concentration in Acrylic Solid Surface is normally in the range of 40-45%. Subject goods are unique in their bendability and can be cast into many shapes, Modified Acrylic Sheets have nil to very low bendability. Thus, modified acrylic solid surfaces are not within the scope of PUC.
18. With regard to the request to include Modified Acrylic Solid Surfaces also in the scope of PUC by some parties, the Authority notes that such claim is not substantiated. Per contra, facts available suggest fundamental differences between subject goods and Modified Acrylic Solid Surfaces as noted herein above. Hence, the request to include Modified Acrylic Solid Surfaces also in scope of PUC is not accepted.
19. With regard to the request for inclusion of unsaturated Polyester and polyester solid surface sheets also in the scope of PUC, the Authority notes that the claimant Indian producer has not substantiated such claims and the request lacks merit. It is noted that unsaturated Polyester and polyester solid surface sheets are apparently polyester based product whereas the subject goods are MMA/PMMA resin-based product.
20. With regard to like article, Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules provides as under:

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;
21. After considering the information on record, the Authority holds that the product under consideration produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The goods produced by the domestic industry and that imported from the subject country are like articles in terms of the Rules. The two are technically and commercially substitutable. Thus, the Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from the subject country within the scope and meaning of Rule 2(d) of Anti-Dumping Rules.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**D.1. Submission of the other interested parties**

22. The submissions on the aspect of the domestic industry and the standing as filed by other interested parties are as follows;
- i. Initiation notification says that the petitioner continues 80% of the Indian production of the subject goods. This statement is not correct.
 - ii. Petitioner's production is nowhere close to 75-80% of the total production of Acrylic Solid Surface in India. Instead, Durlax Top Surface Ltd. (Mumbai) is the biggest player in solid surface business. Durlax has the capacity of 200000 sheets which is almost the double of the petitioner's capacity.
 - iii. The petitioner has provided misleading information to the Authority to consider the petitioner as eligible Domestic Industry. The Authority is required to call the necessary information from Durlax Top Surface Ltd. and examine the standing of the Domestic Industry accordingly.
 - iv. The Authority must ask the Domestic Industry to provide the total production of the subject goods in India to the other parties.

D.2. Submissions made by the domestic industry

23. The submissions made by the domestic industry with regard to scope of the domestic industry & standing are as follows:
- i. The applicant namely Stylam Industries Ltd is the largest producer of subject goods in India and holds major proportion in total Indian production of subject goods. The applicant did not import the subject product from subject country during the period of investigation nor it is related to any of the exporters/importers of the subject product. Hence, the Authority may treat applicant as the eligible domestic industry under Rule 2 (b) of the anti-dumping rules for the purpose of present investigation.
 - ii. There are five other producers of the subject goods in India namely 1) Durlax Top Surface Limited, 2) Marbonex, 3) Baroda Monosol Surface India LLP, 4) Recorian Shagun Polymers India Private Limited and 5) Denolex Polymers Pvt Ltd. Marbonex declared itself as the producer of subject goods in India in a letter to the Authority post initiation though this producer was not in the knowledge of the applicant at the time of application.
 - iii. Out of the 5 other Indian producers, Durlax Top Surface Limited and Marbonex have supported the application and levy of anti-dumping duties on subject goods.
 - iv. Applicant has estimated total Indian production as per its market information since information on production of subject goods by other known Indian producers is not available from any other official or published sources. The share of the applicant in total Indian production so assessed is in the range of 70-80% and fulfills the requirements of Rule 2(b) read with Rule 5 (3).
 - v. There is no alternative information on total Indian production furnished by any of the other parties. In the absence of any such information, the total Indian production as claimed by the applicant stands reliable evidence.

- vi. The responding exporter have disputed the standing claimed by the applicant but have not provided any information on total Indian production of “Acrylic Solid Surfaces” in terms of tonnage/kg. The exporter initially claimed that another producer namely Durlax Top Surface Limited has 2 Lakh capacity and later it has been stated that the same producer has capacity of 120000 pieces to produce “Solid Surfaces”. It must be noted that Durlax Top Surface Private Limited has supported the present investigation. Also, standing under Rule 2(b) of the Anti-dumping rules is not a function of capacity and standing needs to be determined based on production by Indian producers during the POI. Even with regard to capacity of Durlax Top Surface Private Limited, it can be noted from their website that the capacity reported on their website is for Acrylic Solid Surfaces and also for Modified Acrylic Solid Surfaces which is a non-PUC item but the exporter tried to insinuate that such entire capacity is of Acrylic Solid Surfaces.
- vii. Following the second hearing and based on the discussion points in this regard with the Authority, the applicant has rechecked whether Indian production of subject goods is available from some governmental or other sources. Applicant also revisited its estimations to ensure correctness of the estimates. It is submitted after all such efforts that there are no such published or compiled information available and the applicant is constrained to rely on its estimates to gauge the total Indian production.
- viii. It must be appreciated that it has been almost 10 months since initiation of the present investigation and claims by the applicant have been widely circulated to all other parties but to date, no other party could provide any credible information to rebut the claims of the applicant on total Indian production. Even the contentions in this regard came up from a foreign producer is inconsistent and the exporter could not provide production details of subject goods.
- ix. Also, the supporting producers or other Indian producers have not disputed the estimates of Indian production made by the applicant which shows the estimates made by the applicant are reliable.
- x. Thus, the petitioner fulfils the criteria under Rule 2 (b) to be considered as the domestic industry concerning the subject goods.

D.3. Examination by the Authority

24. Rule 2 (b) of the AD rules defines the “domestic industry” as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”

25. It is noted that the application has been filed by M/s Stylam Industries Limited. It is further noted that the applicant did not import the subject goods from the subject country during the period of investigation/injury period and is also not related to any of the exporters/importers of the subject product.
26. Applicant has claimed that the production of subject goods by them constitute a major proportion in the total domestic production of subject goods in India as envisaged in Rule 2(b) read with Rule

5(3) of the Anti-dumping rules. Applicant also claimed that they are the largest producer of subject goods in India.

27. It has also been submitted by the applicant that there are 5 more other producers of subject goods in India other than the applicant making the number of total Indian producers for the subject goods in India at total 6.
28. The applicant submitted as follows with regard to the details of other known Indian producers, their production on an estimated basis, production by the applicant on actual basis, share of each known producer in total domestic production of subject goods and status of support or opposition to the application/investigation as follows;

Domestic Production of subject goods- Volume in KG						
S. No.	Name of Company	2019-20	2020-21	2021-22	POI (April 2022 to June 2023)	Status of the Producer
1	Stylam Industries Ltd.	***	***	***	***	Applicant
2	Durlax Top Surface Limited	***	***	***	***	Supporter
3	Marbonex	***	***	***	***	Supporter
4	Baroda Monosol Surface India LLP	***	***	***	***	Neutral
5	Recorian Shagun Polymers India Private Limited	***	***	***	***	Neutral
6	Denolex Polymers Pvt Ltd	***	***	***	***	Neutral
7	Total	***	***	***	***	
8	Share of Applicant in Total Indian Production-%	***	***	***	***	Above the thresholds required
9	Range	60-70%	65-75%	70-80%	75-85%	Above the thresholds required
10	Share of Applicant along with supporters in Total Indian Production-%	***	***	***	***	Above the thresholds required
11	Range	75-85%	80-90%	85-95%	85-95%	Above the thresholds required

29. Out of the 5 other producers as noted above, Durlax Top Surface Limited and Marbonex have intimated their support for the application/present investigation to the Authority and requested for levy of anti-dumping duties on imports of subject goods from China PR and cited that such imports have impacted their performance. However, it is noted that the expression of support is not in the form and manner prescribed by the Authority nor there is any information submitted to gauge the injury caused to them. The other 3 producers namely Baroda Monosol Surface India LLP, Recorian Shagun Polymers India Private Limited and Denolex Polymers Pvt Ltd neither supported nor opposed the present investigation.
30. The Authority has written to all the known other Indian producers of the subject goods to submit all the information relevant for the present investigation in the form and manner prescribed. But no information is received from such producers. While the responding exporters have disputed the claims of standing made by the applicant, no information on total domestic production is supplied by such parties. Exporters have contended that the Indian producer namely Durlax Top Surface Limited has the capacity to produce 2 lakh pieces of subject goods. However, no information on production of subject goods by the said party during the POI is provided by the exporters. The submission made by the exporters based on information available on the website of Durlax Top Surface Limited reads as follows;

“Durlax Top Surface Ltd has been involved in Solid Surface Business for more than 10 Years. Having Established two Popular Brands LUXOR (ACRYLIC UV SOLID SURFACE) & SPIRON (MODIFIED SOLID SURFACE) with Excellent Satisfaction Rating with our end customer & Channel Partners. We have annual capacity to produce 200000 Sheets”.

31. The above information shows that Durlax Top Surface Limited is a multi-product company and it is not shown by the claimant exporters that the capacity referred on the website of the Company pertains to subject goods only. As noted, Durlax Top Surface Limited has supported the investigation though not in the form and manner prescribed as noted. In the absence of any other information on total domestic production of subject goods, the Authority relies on the information submitted by the applicant to gauge the domestic production of subject good and also for determination of standing in this investigation. The available information shows that the applicant hold major proportion in the domestic production of subject goods and the share is ***% which is above the thresholds required under Rule 2 (b) read with Rule 5(3) of the Rules. It is further noted that the Applicant is not related to any exporter or producer of the subject goods in the subject country or to any importer of the product under consideration in India.
32. Therefore, considering the information on record, the Authority holds the applicant/petitioner as eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules, and that the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. ISSUES ON CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions made by other interested parties

33. The following submissions have been made by other interested parties with regard to confidentiality issues:
- The non-confidential version of the petition does not give a reasonable understanding of the allegations contained in the petition.

- ii. The non-confidential version of the petition fails to meet the standards laid down in Rule-7 of the Rules and Trade Notice No 1/2013 dated December 09, 2013, issued by the Director General.
- iii. The petitioner has claimed excessive confidentiality by not disclosing even the name of the source of import information used as a basis for the initiation of the present investigation. The petitioner has neither mentioned the source of imported data nor cited any reason for claiming the same as confidential.
- iv. Despite relying on the project report heavily, the domestic industry has claimed the entire project report confidential. It has also not provided any meaningful non-confidential summary of the project report to allow the interested parties to provide any effective rebuttal or comments to the same.
- v. The petitioner has claimed excessive confidentiality by not disclosing the total production in India which is required to be disclosed as per Trade Notice 10/2018 dated 7th September 2018.
- vi. The petitioner abusively withheld and manipulated information related to the allegations of injury.
- vii. The domestic industry has claimed excessive confidentiality and filed an incomplete petition.

E.2. Submissions made by the domestic industry

34. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality issues:
- i. The opposing parties have resorted to excessive confidentiality in this matter which has limited the ability of the applicant to offer adequate rebuttals on their claims. The claims of confidentiality are in violation to Rule 7 of the anti-dumping rules. The parties failed to provide tenable reasons or meaningful summary of the information claimed as confidential which violates the confidentiality principle in letter and spirit. The Authority may direct the opposing parties to comply with the requirements of Rule 7.
 - ii. Shandong Kelesi New Material Technology Co., Ltd. has kept even the names of affiliated companies confidential and this has affected our ability to comment on the response filed by the Company on its completeness.
 - iii. Shanghai Sailisi Industry Development Co Ltd has not given any details of its shareholders and also the details of the affiliation of the company are also held confidential. This has also impacted our comments on the completeness of the response. It is not clear whether all parties concerned with the subject goods have come before the Authority or not.
 - iv. Contentions on confidentiality claims concerning project report has no merit. Complete confidentiality on the document has been claimed as preparation of any non-confidential summary of the same without disclosing the essential details was found unviable and the information is confidential and business sensitive in nature.
 - v. The contention that the applicant resorted to excessive confidentiality and filed an incomplete petition is bereft of any merit. The application clearly demonstrates dumping and consequential injury to the domestic industry and the information have been submitted as per the requirement of the rules and also prescribed proformas by the Authority. Also, certain

information including the project report has been claimed confidential by adducing ample reasons as permissible in the Rule and summaries to the extent possible have also been provided.

E.3. Examination by the Authority

35. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

36. As required under Rule 6 (7), the Authority made available the evidence presented to it by one interested party to the other interested parties, participating in the investigation. Such information was circulated among the participating interested parties with directions to exchange such evidence among the interested parties participating in the investigation.
37. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined regarding sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential versions of the information filed on a confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.
38. With regard to the source of import data used by the applicant for the purpose of application, the Authority notes that the applicant has specified the source of data as market information. The Authority has considered DG System transaction-wise data for the purpose of the present investigation.
39. With regard to the contention that despite relying on the project report heavily, the domestic industry has claimed the entire project report confidential, the Authority notes that the applicant claimed confidentiality on the project report on the grounds of business sensitivity.

40. With regard to the submission that actual information on total domestic production must be disclosed in the context of determination of standing, it is noted that a range of shares in Indian total production held by the applicant is provided which is noted as a meaningful summary of the information relevant for determination of standing.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. Submissions made by the other interested parties

41. The following submissions have been made by the exporter/ producer/ other interested parties with regard to various miscellaneous issues:
- i. No updated petition has been furnished by the applicant post initiation.
 - ii. Import data considered by the petitioner is from unreliable sources.
 - iii. DGTR should not have initiated the present investigation on the basis of the information contained in the petition.
 - iv. Levy of anti-dumping duty will establish a monopoly of domestic producer and will not be in the public interest.

F.2. Submission made by the domestic industry

42. The following miscellaneous submissions/rebuttals have been made by the domestic industry:
- i. The contention of the exporters that no updated petition has been furnished by the applicant post initiation have no merit as a submission on relevant updates in the petition following the change in the subject country at the time of initiation has been furnished by the domestic industry on 27th February, 2024. And the same have also been circulated among the interested parties on 12th March, 2024. Such information has been once again provided along with written submission post first oral hearing.
 - ii. The contention that the import data considered by the petitioner is from unreliable sources has no basis. It is a known fact that the transaction wise import information as per DGCI&S is not accessible by general public or a Company and the applicant could not procure such data in view of the regulations put in place by the concerned authorities, and such difficulties have been documented in the application itself. Hence, the applicant had to rely on other source.
 - iii. With regard to the contention that DGTR should not have initiated the present investigation on the basis of the information contained in the petition, it may be noted that the application clearly demonstrates dumping and consequential injury to the domestic industry and the information has been submitted as per the requirement of the rules and also prescribed proformas by the Authority.
 - iv. With regard to the contention that levy of anti-dumping duty will establish a monopoly of domestic producer and will not be in the public interest, the Authority may note that there are about 6 known producers of the subject goods in total in India. It is a settled principle that ADD will not lead to monopoly. Rather, it will only arrest dumped imports enabling the domestic industry to operate under level playing and fair market conditions. India now has the capacity to meet the Indian demand on its own and the country can be self-reliant on this product.

F.3. Examination by the Authority

43. The Authority has considered the views of the interested parties, as follows;

- i. With regard to the contention that no updated petition has been furnished by the applicant post initiation, it is noted that such information has been circulated by the applicant among all interested parties.
 - ii. With regard to the contention that the import data considered by the applicant is from unreliable sources, it is noted that the applicant relied upon secondary source for import data as it could not procure the said data from DGCI&S. However, the Authority has relied upon DGS data at the time of initiation itself and such data is used for this statement also.
 - iii. With regard to the contention that DGTR should not have initiated the present investigation on the basis of the information contained in the petition, the Authority notes that the case was initiated based on prima facie satisfaction of all parameters relevant for such initiation. Claims in the application have been subjected to verification and detailed scrutiny, and only such verified data is considered for the final findings.
- 4.**
- iv. With regard to the contention that anti-dumping duty will lead to monopoly of the petitioner and any such measures shall be against the public interest, it is recognized that the imposition of anti-dumping duty might affect the price levels of the downstream users. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly since the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to address the injury to the domestic industry. Imposition of anti-dumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices and will not restrict fair imports in any manner. Anti-dumping duties will also prevent injury being caused to the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

G. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1. Submission of other interested parties

44. The following submissions have been made by the other interested parties concerning determination of normal value, export price and dumping margin: -

- i. Market economy status should be given to peoples' republic of China PR.
- ii. As per Section 15 (a) (ii) of the Protocol on the Accession of the People's Republic of China to the World Trade Organization expired on December 11, 2016. After that date, India no longer has a legal basis under the agreements of the World Trade Organization to calculate normal value in anti-dumping investigation of Chinese products using the non-market economy methodology. Any such action by India would be inconsistent with the requirements of the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (the "Anti-Dumping Agreement") and other covered agreements.
- iii. Authority may conduct any normal value calculation in accordance with Article 2 of the Anti-Dumping Agreement.
- iv. At the very least, apply the data on costs and prices provided by the exporting Companies in the response for the determination of the normal value rather than applying analogue country data in this instigation.

G.2. Submissions made by the domestic industry

45. The following submissions have been made by the domestic industry:

- i. The Petition contain all relevant information pertaining to normal value, export price and working of dumping margin as per the claims of the applicant. Such data shows significant dumping margin in case of imports of subject goods from China PR. The dumping margin is not only above the de-minimis threshold but is also very significantly positive for PUC.
- ii. Determination of normal value for China PR as per Para 7 of Annexure I of the AD Rules is still relevant as it is still incumbent on the producers from China PR to establish that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product
- iii. China PR must be treated as a non-market economy country for the purpose of normal value determination and the basis of normal value thereafter is elaborated in the application. Also, the Authority may note that the responding exporters has not claimed MET by filing applicable questionnaire replies and in this context, determination of normal based on paras 7 and 8 of Annexure-I to the AD Rules is very essential in this matter.
- iv. The facts of the present case clearly show that the exporters of subject goods from China PR are using dumping of subject goods in India as a strategy to gain more market share in India by decimating the Indian producers and such design of the exporters is evident in the way they sell the subject good in their own market, to India and to other countries. The information available in the response of Shandong Kelesi New Material Technology Co., Ltd shows the below trend;

Particulars	Unit	3rd Previous Year -2020	2nd Previous Year (2021)	1st Previous Year (2022)	POI
Installed Capacity (PUC)	Indexed	100	200	200	250
Capacity Utilization Percentage	Indexed	100	164	182	211
Sales Quantity (PUC):					
Domestic Sales	Indexed	100	151	222	293
Exports to India	Indexed	100	588	1590	2349
Other Countries	Indexed	100	277	373	458
Sales Realisations per unit (PUC):					
Domestic Sales	Indexed	100	85	84	83
Exports to India	Indexed	100	78	89	88
Other Countries	Indexed	100	89	103	105

- v. The following is very evident from the above table;

- a. The exporter has increased their capacity very aggressively and the capacity utilization also doubled by the POI. It is clear that manifold growth in exports to India has augmented such aggressive growth in capacity and capacity utilization.
- b. Highest volume growth is evident in exports to India wherein the increase is from though the exporter sold the goods in domestic and other markets also. Such increase in volume from 100 indexed points to 2349 points has been achieved by reduction in price by about 12% by the POI over the base year and 1% over the immediate previous year. Thus, price reduction was used as a strategy to increase the volume of exports to India.
- c. The import data relied upon in the application shows massive growth in imports from China PR by the POI and the above data underscores the fact that the exporters from China PR have been aggressively exporting the subject goods to India and to increase the volume, dumped prices have been offered and prices to India were reduced whereas the exports to other countries registered increases.
- d. It is clear that the exporter has adopted discriminatory pricing and as result, while the price to India declined significantly by the POI by about 12%, the price to other countries increased by 5%. It is clear that the exporter has a low-price strategy for India resulting in dumping.
- e. The above facts collectively shows that the exporter has adopted dumping as a strategy to gain more market share for the subject goods in India and the situation can only be corrected by levying appropriate levy of ADD.
- vi. The Authority may determine net export price based on the claims in the application.
- vii. Dumping of subject goods is evident and it is significant enough to cause material injury to the domestic industry.

5. G.3. Examination by the Authority

6. Normal value

46. Under Section 9A (1)(c), normal value in relation to an article means:

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-
(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under subsection (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

Market Economy Status for Producers from China PR

47. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

- (a) *"In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following Rules:*
 - (i) *If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*
 - (ii) *The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*
- (b) *In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*
- (c) *The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*
- (d) *Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."*

48. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status.
49. At the stage of initiation, the Authority proceeded by constructing the normal value as per the information furnished by the applicant based on the cost of production of subject goods in India with due addition of SGA and profits. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of their market economy status. The Authority sent copies of the supplementary questionnaire to all the known producers/ exporters for rebutting presumption of non-market economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the Rules and furnish relevant detailed information. The Authority also requested Government of China PR to advise the producers/ exporters in China PR to provide the relevant information.
50. None of the exporters/producers from China PR contested the NME presumption of China PR. Thus, in view of the above position and in the absence of rebuttal of the non-market economy presumption by any exporting company from China PR, the Authority considers it appropriate to treat China PR as a non-market economy country in the present investigation and proceed with para 7 of Annexure-I to the Rules for determination of normal value in case of China PR.
51. Accordingly, the normal value for all the producers/exporters from China PR have been determined as given below.

Normal Value for all Producers in China PR

52. Annexure I of the Rules which reads as under:

In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Account shall also be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

53. Para 7 lays down a hierarchy for determination of normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other country, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. Since there is no claim on record with regard to the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India made by any of the interested parties including the applicant, normal value could not be determined on any of such basis. Therefore, the Authority has constructed normal value for the subject goods from China PR

as price actually payable in India as stipulated in para 7 of Annexure – I to the Anti-dumping Rules. It has been computed based on the cost of production of the domestic industry, with reasonable addition for selling, general and administrative expenses, and profits. The constructed normal value so determined is given below in the dumping margin table.

Determination of Export Price for cooperating producers and exporters

i. Export Price

a) Shandong Kelesi New Material Technology Co., Ltd (Producer)

54. From the exporters' questionnaire response of Shandong Kelesi New Material Technology Co., Ltd who is the producer cum exporter of the subject goods, it is noted that during the POI the Company has exported *** MT of subject goods to India. The producer / exporter has claimed adjustments on account of inland transportation, ocean freight, insurance, bank charges, and port and other related expenses, and the same have been allowed. Accordingly, the export price is provided in the dumping margin table.
55. **Shanghai Sailisi Industry Development Co., Ltd (Trader)-** From the exporters' questionnaire response of Shanghai Sailisi Industry Development Co., Ltd who is the exporter/trader of the subject goods, it is noted that during the POI the Company has exported *** MT of subject goods produced by Shandong Kelesi New Material Technology Co., Ltd, to India. The producer/exporter has claimed adjustments on account of inland transportation, ocean freight, insurance, bank charges, and port and other related expenses, and the same have been allowed. Accordingly, the export price is provided in the dumping margin table.

Determination of Normal Value and Export Price for all non-cooperating Producers and Exporters in China PR

56. The normal value and export price for other non-cooperating exporters from China PR is as per facts available taking into account the data examined for the co-operating exporters and the same is mentioned in the dumping margin table.

Dumping Margin

57. Considering the normal value and export price for the subject goods, the dumping margins for the subject goods from the subject country is as follows. It is seen that the dumping margin for the participating producer is *de minimus*.

Dumping Margin Table

S. No	Country	Producer	Normal Value US\$/Kg	Net Export Price US\$/Kg	Dumping Margin US\$/Kg	Dumping Margin %	Dumping Margin (Range %)
1	China PR	Shandong Kelesi New Material Technology Co., Ltd and Shanghai Sailisi Industry Development Co., Ltd. Shandong Branch	***	***	***	***	0-10
2	China PR	Any other producer	***	***	***	***	5-15

H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK**H.1. Submissions made by other interested parties**

58. The submissions made by the other interested parties have been as follows:

- i. The production and profits projected by the petitioner cannot be taken into account due to the unforeseen and unprecedented crisis occurred in India as well as the whole world in the form of COVID-19 flu pandemic that derailed the socio-economic life of people globally as well as trade and commerce for months and years to come.
- ii. The project report which was based on grossly different market situation should not be relied upon in the extant investigation for analysis of material retardation claim without making due adjustments to account for the impact of the pandemic.
- iii. Imports from subject country is coming only to fill the demand and supply gap in India as the petitioner cannot fulfil the Indian demand. Accordingly, imports from the subject country have been increasing with the increase in demand.
- iv. With the present capacity available with the petitioner and other domestic producers, it cannot fulfil the Indian demand. Therefore, imports are imperative only to fill the demand and supply gap in India and not to cause any injury to the domestic industry.
- v. The per unit cost of sales has declined during the POI to 49 as compared to 100 during the base year 2019-20. Whereas, the net sales realization has increased by 49%, from 100 during the base year 2019-20 to 149 during the POI. This must have resulted into profitability to the domestic industry as their selling price is much more than their cost of sales. Thus, there is no price effect during the POI.

- vi. The capacity of the petitioner remained unchanged throughout the injury period and period of investigation. Production and capacity utilization of the petitioner have increased sharply respectively showing that there is no injury to the domestic industry.
- vii. With the increase in the production of the petitioner, their domestic sales have also increased during the period of investigation by more than 6 times. The export sales of the petitioner have increased exponentially.
- viii. Average Inventory as no. of days of production and sales are showing decline. This depicts that the petitioner was able to sell whatever they produced.
- ix. The petitioner was facing losses during the entire injury period and POI. However, such losses have come down significantly during the POI which shows that the performance of the Domestic Industry has improved significantly showing that there is no injury to the Domestic Industry
- x. Annual Report of the petitioner for the FY 2022-23 depicts profitability of the applicant. It is to be noted that PBT of the petitioner was the highest during the POI showing that no injury is being caused to the Domestic Industry.
- xi. No. of employees and wages are showing an upward trend which clearly depicts that there is no injury to the Domestic Industry.
- xii. Productivity of the petitioner has improved during the period of investigation as compared to the base year 2019-20, showing that there is no injury to the domestic industry.
- xiii. Overall performance of the Domestic Industry has improved. All the economic parameters of the petitioner depict that there is no injury to the domestic industry and if any, that cannot be attributed to the imports of subject goods from China PR. The observations made by the Authority in the initiation lacks factual and legal basis.
- xiv. Any injury allegedly suffered by the domestic industry is due to factors other than imports from the country concerned. The petition deliberately fails to address a number of crucial issues which had an impact on the domestic industry independently from the imports originating in the country concerned.
- xv. Chinese products are better in terms of quality. the quality of imported products is better than the Indian Acrylic Solid Surfaces. Chinese & Korean producers provide high quality products which enhance durability and widen the area of application.
- xvi. Fluctuations in raw material prices have a significant impact on the global acrylic solid surface market. The prices of raw materials, such as alumina trihydrate and acrylic resin, fluctuate due to various factors, such as supply and demand, geopolitical tensions, and natural disasters.
- xvii. The COVID-19 pandemic has had a profound impact on businesses worldwide. From disruptions in supply chains and shifts in consumer behavior to remote work arrangements and financial challenges, the pandemic has forced businesses to adapt quickly to unprecedented circumstances. Many industries have faced significant setbacks including the petitioner.

- xviii. Other reasons may include internal problems, depressed market conditions globally, Russia Ukraine War etc. that might have played a role in the deterioration of the performance of the domestic industry, which is attributed to alleged dumping of subject goods.
- xix. The petitioner has done calculations considering 22% return on gross fixed assets, which is highly inflated and not in accordance with the Law. It is submitted that the Hon'ble Director General Trade Remedies should not adopt reasonable profit as 22% return on capital employed for computing the non-injurious price.
- xx. Hon'ble Director General Trade Remedies should adopt the actual profit earned by the Domestic Industry during the period when there was no allegation of dumping as a basis for calculating reasonable return.
- xxi. Project report cannot be a parameter for making assessment of actual performance. The petitioner projected a rosy picture of the production volume and profits in the project report that cannot be treated as a parameter for making assessment of the applicant's actual performance.

H.2. Submissions made by the domestic industry

59. The following submissions have been made by the domestic industry:

- i. The positive evidences on dumping, injury and causal link submitted by the applicant in the application shows that the domestic industry suffered material injury from dumped imports as envisaged in the AD Rules. The information contains details of the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like article and also, the consequent impact of such dumped imports on domestic industry as envisaged in Annexure II to the AD Rules read with Rule 11.
- ii. The information in the application also shows the performance has been much lower than what the industry projected to achieve and in that sense, the establishment of the industry was also materially retarded. Thus, coexistence of material injury and also material retardation to the establishment of the industry is very evident in the present matter. Without prejudice, material injury is very evident in this matter even if the Authority decides not to conduct examination of claims of material retardation.
- iii. Rule 11 of the AD Rules read with the Annexure II shows injury can be material injury or threat of material injury to the domestic industry or material retardation of the establishment of such an industry. The facts of injury of the present matter would show presence of injury in the form of material injury and also material retardation and the same may be examined by the Authority. As far as the applicant is concerned, it has suffered injury on account of dumped imports and its nature is a matter of determination by the Authority as envisaged in the Rule.
- iv. To support the projected levels of performance, project report of the applicant has been provided which is relevant in case of many parameters. The applicant commenced commercial production in FY2018-19 (Oct-2018) which shows that the applicant started production in the recent period. However, had there been no dumped imports, the applicant could have established itself fully by this time and achieved the projected levels of capacity utilization, production, profits etc. by the POI.

- v. It is apparently a settled jurisprudence by this time in India that material injury and material retardation can co-exist in an investigation and explicit views taken by the Authority in the past in several investigations may be made applicable in this matter also. Views taken in a) Final Finding- Anti-dumping investigation concerning imports of Veneered Engineered Wooden Flooring originating in or exported from China PR, Malaysia, Indonesia and the European Union dated 13.2.2018, Antidumping investigation concerning imports of O-Acid originating in or exported from China PR dated 19th December, 2017 etc. may be made applicable in this matter also. It has been clearly noted in Veneered Engineered Wooden Flooring case that *“as regards the contention that material retardation and materials injury cannot co-exist, the Authority notes that there is no bar under the law for examination of more than one form of injury”*
- vi. Imports of the subject goods from subject country have increased in absolute terms as well as in relation to consumption in India by the POI. In fact, dumped import was at the highest level during the POI.
- vii. Market share of dumped imports increased by the POI and have been holding very significant share in the Indian demand during the POI. Though market share of the domestic industry also increased by the POI, the market share in absolute terms remained very abysmal and the capacity of the domestic industry remained largely underutilized during the POI as a result of such abysmal market share.
- viii. The real injury lies in the fact that while the dumped imports could increase their market share from 5-10% in the base year to 25-35% in the POI, the share of domestic industry moved from 0-2% in the base year to 3-6% in the POI only. Resultantly, the domestic industry could only increase its capacity utilization from 2-10% in the base year to 25-35% in the POI. In fact, the domestic industry expected to reach a capacity utilization level of 70-80% by the 4th or 5th year of operation but the same was prevented by dumped imports.
- ix. This is a case where dumped imports from China PR grabbed the market share and pushed the domestic industry to operate at lower-than-expected levels of capacity utilization which then impacted overall performance and triggered injury.
- x. Information shows that capacity utilization, production and sale of the domestic industry was so low even by the POI and such actual performance on these parameters were far lower than the projected or expected numbers on these parameters. Increases in these parameters by the POI over the injury period would have been far higher had there been no dumping and the growth achieved on these parameters were all abysmal and namesake.
- xi. Below par capacity utilization, much lower than the projected levels, even when the country has been showing a robust demand is a direct fall out of presence of dumped imports in India and the injury and material retardation evident on this parameter underscores dumped imports as the actual trigger point of injury to the domestic industry.
- xii. The domestic industry was left with significant unutilized capacities as the major market share was held by dumped imports. This is when there have been increases in demand for the product in the country.

- xiii. The landed price of dumped imports created positive price undercutting, underselling and price suppression effects as the domestic industry was prevented from price increases which otherwise would have occurred, to a significant degree, so as to recover full cost and earn reasonable profits.
- xiv. The domestic industry suffered financial losses as reflected in negative PBT, negative PBIT, negative PBDIT and negative ROI and such core parameters were negative during the POI and in the entire injury period. Apart from these negative figures, actual performance in terms of cash profits and PBDIT were very low though has been slightly positive during the POI.
- xv. Though the profitability parameters have shown some increases by the POI in comparison to the previous years, the actual performance on these parameters were far lower than the projected or anticipated numbers and no way show healthy situation of the domestic industry. Increases in these parameters by the POI over the injury period would have been far higher had there been no dumping.
- xvi. Inventory with the domestic industry increased and such increase is attributable to huge presence of dumped material in the market. Increase in inventory shows volume injury since the increase in inventory shows there was less offtake of product of the domestic industry though production increased at very low rates.
- xvii. Growth was negative in terms of inventory level. Actual growth in terms of all core parameters by the POI have been abysmal and have been lower than the projections concerning such parameters. Thus, dumped imports have prevented the domestic industry from achieving robust growth showing signs of injury and such dumped imports further prevented the domestic industry from establishing itself as evident in the lower-than-expected growth registered by the domestic industry on all key injury parameters.
- xviii. The ability of the domestic industry to raise capital investment has been significantly impacted and the projected increases in capacity could not be completed.
- xix. Imports have been taking place at dumped levels and dumping margin is significantly positive in case of subject country. Trend of imports do not show that there will have any change in the situation with the current rate of dumping and dumping will only get aggravated if no ADD is levied.
- xx. The pace at which the domestic industry operated in the injury period and during the POI shows that dumping will continue to prevent the domestic industry from performing well and establishing itself as expected.
- xxi. Thus, the domestic industry has suffered material injury and there are evidences that the establishment of the industry as expected could not be achieved.
- xxii. While the parameters of injury in the petition read with the post initiation addendum demonstrate that the Domestic Industry suffered injury as envisaged in the Rule, the petition further shows that the injury to the Domestic Industry has been caused on account of dumped imports.

- xxiii. The price at which the product under consideration has been imported into India from subject country has been below its normal value resulting in significant dumping.
- xxiv. Imports from subject country increased substantially by the POI in absolute terms and also in relative terms to consumption in India. As a result, market share of such dumped imports increased and remained significantly high by POI and have been on an increasing trajectory in the injury period and POI. Consequently, market share of the domestic industry remained at below par and insignificant levels.
- xxv. Increase in market share of dumped imports and abysmal market share of the domestic industry had a cascading effect on volume parameters of the domestic industry and as a result, production, capacity utilization and sales of the domestic industry remained very low and have been much lower than the projected levels even after some increases over the injury period. It is evident that injury from dumped imports has created material retardation effects on the establishment of the industry.
- xxvi. The adverse effects of dumped imports on the price of the domestic industry prevented the domestic industry from even passing on full cost and the domestic industry had to sell below its cost. As a result, the domestic industry suffered financial losses and negative ROI situation. Domestic industry would have increased the prices to profitable levels in the absence of dumped imports.
- xxvii. The importers/users apparently preferred the imported material for the reason that prices offered by the exporters were at dumped level. The dumped prices alone caused market share gain by dumped imports. Resultantly, the domestic industry was left to suffer injury on all fronts.
- xxviii. Had there been no dumping, the situation of the domestic industry would have been that of better performance and profitability with significant market share and moderate capacity utilization.
- xxix. It is also evident that performance of the domestic industry has been much lower than the projected levels. This shows the dumped imports have prevented the domestic industry from establishing itself and such facts show material retardation in the establishment of domestic industry.
- xxx. Productivity of the domestic industry has been continuously increasing and the industry could bring down its cost substantially and the cost in terms of interest, depreciation has been at the lowest level during the POI showing the efficient operation by the applicant. Still the domestic industry could not sell at profitable levels as the dumped imports has been lower than its cost and price.
- xxxi. Imports from other countries have been at higher or at un-dumped or non-injurious level and such imports from other countries has not been the cause of injury. Also, it has been shows in the application that factors such as exports, any decline on demand, change in technology also has not been any cause of injury to the domestic industry. It is notable that import price from

China PR have been much lower than other major exporting countries like Korea RP, Japan etc. and the cause of such lower price is not explained.

- xxxii. Exporters from China PR are trying to undercut and get into the share of other imports also along with domestic industry and to give effect to such motivated designs, dumped price is being offered and as a result, market share of China PR have been sky rocketing.
- xxxiii. A comparison of imports from China PR and other countries shows China PR has kept its price so low and as a result, imports from China PR increased while the others decreased or remained stagnant;

	Volume MT				Rate Rs/ KG			
Row Labels	2019-20	2020-21	2021-22	POI (A)	2019-20	2020-21	2021-22	POI (A)
China	691	281	1214	2650	174.18	168.25	190.67	187.10
Japan	242	189	142	439	205.93	237.71	220.05	220.07
South Korea	7414	4656	6327	5984	211.91	209.65	223.12	255.07
USA	513	255	540	339	240.59	237.84	197.99	316.95

- xxxiv. Actual performance and the expected performance during by the POI- Domestic industry clearly emphasize that the actual performance during the POI has been much lower than the expected level and this factor also must be considered as a parameter while examining the injury.
- xxxv. The applicant expected to operate in the level of 70-80% capacity utilization by the POI which would have been easily possible with the given growth in demand, had there been no dumping. However, the DI was forced to operate at a capacity utilization level of 25-35% even by the POI. DI expected a market share in the range of 25-35% by the POI, but was sidelined to less than 3-5% market share by the POI. DI expected to register profits by the POI along with ROCE in the region of 15-25%. However, the DI incurred losses and the ROCE was negative.
- xxxvi. DI had plans to expand its capacity even prior to the POI but the adverse market situation delayed the capacity additions beyond the POI period. The DI could have employed more people but the stagnancy in volume growth prevented such any such addition in employment and in fact, there was an increase in inventory level which forced the DI to keep its production and employee level to the minimum. Thus, the overall performance during the POI have been much lower than the projected levels and this aspect may be considered while examining the injury.
- xxxvii. Legal standards and the contention of improvement in injury parameters- It has been contended by some of the opposing parties that the performance of the domestic industry has improved on all key parameters of injury by the POI in comparison to the base year and, hence, there is no injury. This contention has no basis in law and the contention must be rejected while examining the injury as required under the rule.

- xxxviii. Annexure II to the Rules under Rule 11 says that (i) A determination of injury shall involve an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. Thus, the requirement under the Rule is objective examination of evidence of injury presented and not an end point to end point (base year to POI) comparison as suggested by the opposing parties. An increase over the base year does not rule out injury and what is required is objective examination.
- xxxix. Similar is the position of law as set out in Article 3.1 of the WTO-AD Agreement. It has been clarified by the WTO Panel in the European Communities – Anti-Dumping Duties On Malleable Cast Iron Tube Or Pipe Fittings From Brazil- WT/DS219/R dated 7 March 2003 that an examination to capture the current state of the industry is essential rather than just a comparison of end-points as claimed by the exporters here. The WTO Panel observed “7.316 *We first recall the importance in the process of this evaluation of placing data relating to developments with respect to each injury factor in context, both in terms of their own individual development and vis-à-vis developments in other factors examined. Thus, a meaningful investigation must also take into account the actual intervening trends in each of the injury factors and indices -- rather than just a comparison of "end-points". There must a streamlined, genuine and undistorted picture drawn from the facts before the investigating authority. Only on the basis of such a thorough and dynamic evaluation of data capturing the current state of the industry in the determination would a reviewing panel be able to assess whether the conclusions drawn from the examination are those of an unbiased and objective authority*”.
- xl. It has also been clarified by WTO in Thailand – Anti-Dumping Duties On Angles, Shapes And Sections Of Iron Or Non-Alloy Steel And H-Beams From Poland- WT/DS122/R dated 28 September 2000 that positive trends in a number of factors do not preempt the investigating authority from determining any injury and it is just that such positive trends would require explanations. Rather, injury can be found even after positive trends in a number of factors and its again a matter of objective examination and explanation. Thus, the need is objective examination of evidences and determination of injury is not a function of mere trend analysis between past years and POI as suggested by the exporters. The WTO report says “7.248. *Moreover, Exhibit Thailand-37 contains or refers to non-confidential data in indexed form pertaining to SYS, including: capacity; production capacity; capacity utilization; sale quantity (including domestic and export sales); market share; inventory, net profit/loss, return on investment and employment. This factual evidence before the Thai investigating authorities indicated that from 1995 to the IP, SYS' capacity remained constant while numerous factors indicative of the state of the industry moved positively, including production, capacity utilization, sales (both domestic and export sales), market share, inventories and employment. 7.249. While we do not consider that such positive trends in a number of factors during the IP would necessarily preclude the investigating authorities from making an affirmative determination of injury, we are of the view that that such positive movements in a number of factors would require a compelling explanation of why and how, in light of such apparent positive trends, the domestic industry was, or remained, injured within the meaning of the Agreement. In particular, we consider that such a situation would require a thorough and persuasive explanation as to whether and how such positive movements were outweighed by any other factors and indices which might be moving in a negative direction during the IP.*

- xli. The principles as above set out by WTO is also well reflected in many Anti-dumping findings by India and in none of such cases, improvement in key parameters by the POI lead to a conclusion that there is no injury. Rather, the Authority found injury even when most of the key parameters improved by the POI.
- xlii. In Anti-dumping investigation concerning imports of “New/unused pneumatic radial tyres with or without tubes and/or flap of rubber (including tubeless tyres) having nominal rim dia code above 16” used in buses and lorries/trucks”, originating in or exported from China PR- No. 14/14/2015-DGAD- 1st August, 2017, both key volume and price parameters have shown increases between base year and POI but injury was found by the Authority.
- xliii. In Anti-dumping investigation concerning imports of “Printed Circuit Boards (PCB)” originating in or exported from China PR and Hong Kong- F No. 06/16/2022-DGTR dated 29th December 2023, the case had core parameters improved by the POI viz. the base year but injury was found. It was noted *that the profitability parameters of the domestic industry have increased from the base year to the POI*. It was also noted *that though there is a positive growth in volume as well as price parameters, but the growth is lower along with lower capacity utilization in comparison to the expansion in demand*.
- xliv. In Anti-dumping duty investigation concerning imports of Elastomeric Filament Yarn from China PR, South Korea, Taiwan and Vietnam- F. No.14/29/2015-DGAD dated 24 March, 2017, the facts of the case show the core injury parameters improved during the POI in comparison to the base year though the price parameters still remained negative during the POI. It was observed *“there was positive growth of the domestic industry in terms of sales and production in the POI as compared to the base year. However, profits, cash profit as well as ROI remained negative in the POI as compared to the preceding years despite significant increase in demand. The domestic industry has contended that with increase in demand, the domestic industry had expected growth in profits, comfortable cash flow and increase in return on investments. However, the domestic industry was not able to achieve the same due to the presence of the dumped imports from subject countries. With regard to consequent impact of the dumped imports on the domestic industry, it is concluded that the performance remained negative in respect of profit, return on investment and the inventory level”*.
- xlv. A collective reading of the relevant past findings by the Authority and WTO decisions shows that mere increase in several parameters do not lead to an automatic conclusion that there is no injury as contended by the opposing parties. Injury needs to be examined objectively and positive evidences on injury suffered by the domestic industry is presented in the application shows existence of material injury to the domestic industry in the present matter.
- xlvi. It is also submitted that in the absence of immediate measures to arrest the dumping of subject goods into India from the subject country, the domestic industry will face further irreparable losses. Thus, recommendation of anti-dumping duties at the earliest is very essential in the facts of the present case.

- xlvi. The Authority has raised questions on the trend of depreciation concerning domestic sales claimed in the proforma IV which has been explained in detail in the post oral hearing written submission. It has been confirmed and clarified that the claims of depreciation in the proforma IA are as per the records of the applicant and does not require any modification.
- xlvi. It has also been clarified that that the slight overrun in capital cost, however, did not have any effect on the cost element in terms of depreciation since the actual depreciation charged since commencement of production has been significantly lower than the projected figures of depreciation cost due to a change in method in the charging of depreciation occurred due to change in policy of the Government.
- xlix. The price at which the product has come to India from significant other sources like Korea RP (Rs255/Kg), USA (Rs316/Kg) etc. shows cost of the applicant during the POI is not any abnormal number but reflects the true picture of price prevailing in the international market.
1. The exporters have contended that the project report is not reliable and the use of the same is not proper in the context of injury. The contention has no merit. The project report, which was prepared at the time of setting up the plant, and has been part of the financing and other management decisions of the applicant, cannot be called as any fabricated document by any reasonable person and the document is by nature confidential and authentic by all means.
 - li. The application has placed reliance on the project report to the extent necessary to show material retardation in the establishment of the industry in its performance. A project report enables an assessment of performance projected at the time of establishment of the plant viz. the actual performance during the POI and there is nothing improper in the use of a project report as held by any court of law or by any provisions of the anti-dumping rule or by the Authority. In fact, the Authority noted the use of project report in material retardation matters like Vinyl Tiles (F. No. 6/17/2021-DGTR dated 23.1.2023).
 - lii. The Authority may take cognizance of both performance during the POI and the projected performance based on the project report while evaluating injury in the present matter. Also, the impact of Covid was not there in the POI and the projected performance for the POI was not met only on account of dumped and injurious import of subject goods from China PR. The applicant projected a very reasonable and achievable numbers for the period now considered as POI and the same was vitiated by the dumped imports. The product had a robust demand and price in the market but dumped imports at very low prices spoiled the opportunities of the applicant. Thus, considering the projected numbers also has relevance.
 - liii. It is also asserted by the exporters that the overall performance of the Domestic Industry has improved. This is not a correct reading of the situation of the domestic industry and legal standards need to be looked into and also the past cases by the Authority in this regard.
 - liv. The actual performance even after increase has been very abysmal and have been nowhere close to the projected numbers by the domestic industry. Also, the increase over the years as highlighted by the exporters is the effect of very miniscule base year numbers and the actual performance during the POI would show that the domestic industry was prevented from

establishing itself in any meaningful manner coupled with below par performance on all parameters.

- iv. It may also be noted that the exporters have stated that the applicant has claimed threat of material injury which is not a correct statement. Applicant has claimed injury and not threat of injury in the application.
- lvi. The exporters have tried to tabulate their comments on injury in the first two columns of the following table, to which the following rebuttal is offered;

Parameter	Comments on Actual Performance by exporter	Rebuttal by the domestic industry
Natural and potential decline in:		
Sales	Improving	Improvement is only namesake. Even after increase, market share of the DI is less than 5% whereas that of the dumped imports is 25-35%. Thus, dumped imports took away higher share of market demand which shows injury to the DI.
Profits	Improving	DI was still in losses whereas it was projected to be in good profits by the period covered as POI. The losses during the POI are attributable to low realization on account of price and cost undercutting from dumped imports. Losses during the POI shows injury suffered by the DI.
Output	Improving	Inventory also improved and even after some increase in production, more than 70% of the capacity remained unutilized on account of dumped imports which shows injury to the DI.
Productivity	Improving	This shows reduction in productivity has not been the cause of injury.
Return on Investments or Utilization of Capacity	Improving	DI was still in losses whereas it was projected to be in good ROCE levels of 15-25% by the period covered as POI. Dumped prices directly impacted the ROCE. The DI did not get the benefit of reduction in cost on account of presence of dumped imports.
Actual and potential negative effects on		
Cash Flow	Improving	DI was still in losses during the POI which shows current injury. Improvement from very low numbers in the base year does not mean absence of injury. DI expected significantly positive cash flows by the POI which was impacted due to dumping.
Inventories	Improving	Inventories increased which shows even the lower level of production achieved could not be sold out fully and the material ended up in the inventories. This parameter shows volume injury.

Employment/wages	Improving	Below par performance. DI could have provided more employment in the absence of dumped imports and better capacity utilization.
Growth	Improving	Below par performance is visible on all parameters. The injury parameters also shows that the establishment of the DI was materially retarded as the overall performance was lower than the expectation and the levels projected in the project report. Thus, injury is visible on growth parameter also.
Ability to raise capital investments	Improving	Significant delay has happened in the expansion plans and this is a direct fall out of adverse market conditions created by dumped imports, which shows injury on this count.

- lvii. The reasons cited by the exporters in the context of other cause of injury such as Chinese products are better in terms of quality, fluctuations in the price of raw material, Impact of COVID etc. have not even been the cause of injury to the domestic industry at all. The mammoth increase in imports at dumped and at undercutting and underselling levels have been the cause of injury suffered by the domestic industry.
- lviii. The products by the applicant are best in quality and compete with any international player and the only concern is the dumped prices being offered by the exporters from subject country. The landed price of imports is lower than the cost and price of the domestic industry and such prices have vitiated the level playing field in the market and such imports alone has been the cause of injury claimed by the applicant. There are no evidences shown with regard to the quality issues of the applicant nor there are any submissions made by the users in this regard.
- lix. The contention of Inflated Return On Capital Employed has no merit. The rate of ROCE for the purpose of NIP is determined by the Authority based on Annexure-III to the rules and as per its consistent practices.
- lx. The contention of monopoly by the petitioner has no merit. There are about 6 known producers of the subject goods in total in India. It is a settled principle that ADD will not lead to monopoly. Rather, it will only arrest dumped imports enabling the domestic industry to operate under level playing and fair market conditions. India now has the capacity to meet the Indian demand on its own and the country can be self-reliant on this product. While the demand supply gap during the POI has been about 5-10%, the gap post POI is nil. India has some excess capacity now.

H.3. Examination by the Authority

60. The Authority has taken note of various submissions of the domestic industry and also opposing parties and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority hereunder *ipso facto* addresses the various submissions made by the interested parties.

61. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....*”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.
62. With regard to various contentions on injury and causal link, the substantial submission of the opposing parties is that the performance of the applicant improved on all parameters in the POI and any injury claimed by the applicant are on account of other reasons only. On the other hand, and in rebuttal to the claims of the opposing parties, the applicant has claimed that though the injury parameters improved by the POI in comparison to the previous years the actual growth in real terms have been very abysmal and the performance on all volume and price parameters have been much lower than the levels projected by the applicant at the time of investing in the project to produce the subject goods. The applicant also emphasized that the domestic industry incurred financial losses and negative return in the POI even after some improvements over the injury period. Applicant also claimed that the establishment of the industry was materially retarded which also shows injury having been suffered by the domestic industry. The Authority has taken into consideration all such contentions and rebuttals and the facts in this regard collected during the investigation is disclosed in this statement which ipso facto addresses the contentions as envisaged in Rule 11 of the anti-dumping rules read with Annexure II to the said rules.
63. With regard to the claim that the production by the petitioner cannot be taken into account due to the unforeseen and unprecedented crisis occurred in India as well as the whole world in the form of COVID-19 flu pandemic, the Authority notes that the POI determined for the present investigation has not been impacted by pandemic and the claims for POI does not require any adjustment for COVID-19 pandemic.
64. With regard to the contention that the imports from the subject country is coming only to fill the demand and supply gap in India as the petitioner cannot fulfil the Indian demand, the Authority notes that there are about 6 producers of subject goods in India and it is noted that the capacity available with such producers for the subject goods in India during the POI was sufficient to meet substantial part of Indian demand.
65. With regard to the contention that Annual Report of the petitioner for the FY 2022-23 depicts profitability of the applicant, the Authority notes that the applicant is a multi-product company and injury concerning subject goods alone is considered for injury examination.
66. With regard to the contention that any injury allegedly suffered by the domestic industry is due to factors other than imports such as Chinese products are better in terms of quality, fluctuations in raw material prices, the COVID-19 pandemic, internal problems of the applicant, depressed market conditions globally, Russia Ukraine War etc., the Authority notes that none of such contentions are supported by any evidences. There are no evidences adduced to show that the applicant could not sell at profitable levels due to quality issues. Issue such as pandemic was not prevalent during the POI. There is no evidence to show that the cause of injury is global

fluctuation in raw material price. Similarly, there are no evidences adduced to show that the injury was on account of Russia-Ukraine war, internal problems of the applicant etc.

67. With regard to the contention that a project report cannot be a parameter for making assessment of actual performance, the Authority notes that assessment of injury in this case is done based on the actual injury data submitted by the domestic industry concerning the injury period and such examination is carried out as per the mandates of the rules governing injury assessment.
68. With regard to the submission that the Authority must not allow 22% ROCE while determining Non-injurious price for the domestic industry, it is noted that 22% ROCE is allowed for the purpose of NIP determination as per the consistent practices and such practice is considered as appropriate in the present matter also.
69. With regard to the claims of the domestic industry that the coexistence of material injury and also material retardation to the establishment of the industry is very evident in the present matter, the authority has done the injury analysis based on the actual performance of the DI in the injury period. It is also noted in this regard that the injury information for POI and the previous three years is available in the present case which allows objective examination of injury as envisaged in the rule.
70. With regard to the claims of the domestic industry concerning legal standards and the contention of improvement in all injury parameters by the POI, the Authority notes that the requirement under the Rule is to conduct objective examination of injury and relevant facts for such an examination as gathered during the investigation is presented in this statement. Annexure II to the Rules under Rule 11 says that (i) A determination of injury shall involve an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products.

i. Volume Effect of Dumped Imports on the domestic industry

71. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or in relation to production or consumption in India. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied upon the transaction-wise data procured from DGS. The import volumes of the subject goods and share of the same during the injury investigation period are as follows:

a. Assessment of Demand/Apparent Consumption

72. For the purpose of the demand/apparent consumption, the Authority has considered total import of the subject goods into India and the total domestic sales made by domestic industry and sales made by all other Indian producers;

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	Annualized- POI	POI
Subject Imports	MT	798	193	1971	3677	4596
Trend	Indexed	100	24	247	461	576
Other Countries	MT	5613	3176	6549	6444	8056
Total Imports	MT	6411	3368	8520	10,121	12651
Domestic Sales	MT	***	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	78	346	607	759
Sales of Other Producers	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	60	234	316	395
Demand	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	53	136	164	206

73. It is seen that the demand for the product increased significantly over the injury period. Demand for the subject goods in India during the POI has increased over the base year and also over the immediate previous year. It is also noted that demand has been at the highest level during the POI with an increase of 64% between POI and the base year and 28% increase between POI and the immediate previous year.

b. Subject Country Imports in absolute and relative terms

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	AnnualizedPOI	POI
Subject Imports	MT	798	193	1971	3677	4596
Demand	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	53	136	164	206
Production	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	222	648	1085	1357
Subject import in relation to:						
Consumption	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	46	181	280	280
Production	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	11	38	42	42

74. It is noted that the share of dumped imports in relative terms to consumption has increased by the POI in comparison to the base year and also the immediate previous year. However, dumped imports in relation to production in India has declined between the POI and the base year but increased between the POI and the immediate previous year.

ii. Price Effect of the imports on the domestic industry

75. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject country has been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject country.

a) Price Undercutting

76. For the purpose of price undercutting analysis, the net selling price of the domestic industry has been compared with the landed value of imports from the subject country. While computing the net selling price of the domestic industry all taxes, rebates, discounts and commissions have been deducted and sales realization at ex-works level has been determined for comparison with the

landed value of the dumped imports. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject country work out as follows:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Net Sales Realization	Rs. /Kg	***	***	***	***
Net Sales Realization	Trend	100	129	120	149
Landed Price	Rs. /Kg	181	179	197	197
Price Undercutting	Rs. /Kg	(***)	***	***	***
Price Undercutting	%	(***)	***	***	***
Price Undercutting	Range %	0 – (10)	15-25	0-10	15-25

77. It is noted from the aforesaid table that imports of the subject goods from the subject country have been entering Indian market at a price below the net sales realization of the domestic industry, resulting in positive price undercutting. It is further noted that though the landed price of imports had increased over the years, the gap between landed price of dumped imports and NSR of the domestic industry remained very significant resulting in a price undercutting in the range of 15-25% during the POI.

b) Price Suppression/Depression

78. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in the normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, were compared in light of the landed price of dumped imports as below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI	Annualized-POI
Cost of Sales	Rs. /Kg	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	120	54	49	49
Selling Price	Rs. /Kg	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	128	120	149	149
Landed Price	Rs. /Kg	181	179	197	197	197
Trend	Indexed	100	99	109	109	109

79. The information as per the above table shows that the selling price of the domestic industry and also landed price of imports of subject goods from the subject country increased between the base year and the POI while the cost of production of the domestic industry declined in the POI.
80. The landed price of imports has been significantly lower than the cost of sales and selling price of the domestic industry during the POI.

iii. Economic Parameters of the domestic industry

81. Annexure-II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Anti-dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the

industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

82. While disclosing the essential facts on injury and causal link, the Authority has also examined the injury parameters objectively taking into account various submissions made by all the interested parties so far in this investigation so as to address all such submissions as well on their merits.

a) Production, Capacity, Sales and Capacity Utilization

83. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity and capacity utilization was as follows:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI	Annualized - POI
Installed Capacity	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	125	100
Production	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	222	648	1357	1085
Capacity Utilization	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	222	648	1085	1085
Domestic Sales	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	78	346	759	607

84. It is noted that while the capacity remained constant over the injury period, production, capacity utilization and sales of the domestic industry increased between the base year and the POI.

c. Market Share in Demand

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI	Annualized- POI
Subject Imports	MT	798	193	1971	4596	3677
Trend	Indexed	100	24	247	576	461
Other Countries	MT	5613	3176	6549	8056	6444
Total Imports	MT	6411	3368	852	12651	10,121
Domestic Sales	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	78	346	759	607
Sales of Other Producers	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	60	234	395	316
Demand	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	53	136	206	164
Share in Indian Demand that of;						
Subject Imports	%	12	6	22	34	34
Trend	Indexed	100	46	181	280	280

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI	Annualized- POI
Other Countries	%	86	92	74	60	60
Trend	Indexed	100	107	86	70	70
Total Imports	%	98	97	96	94	94
Trend	Indexed	100	99	98	96	96
Domestic Sales	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	147	254	369	369
Sales of Other Producers	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	113	172	192	192
Sales of Indian producers	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	136	228	313	313

85. The Authority notes that the market share of the imports of subject goods from subject country has increased between the base year and the POI..

b) Profitability, return on investment and cash profits

86. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period is given in the table below: -

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI	Annualized POI
Profit/Loss (PBT)	Rs. /Kg	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
Trend	Indexed	(100)	(117)	(25)	(5)	(5)
PBIT	Rs. /Kg	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
Trend	Indexed	(100)	(118)	(25)	(5)	(5)
Cash Profit	Rs. /Kg	(***)	(***)	(***)	***	***
Trend	Indexed	(100)	(185)	(31)	1	1
Average Capital Employed	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	42	65	88	88
Return on Capital Employed	%	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
Trend	Indexed	(100)	(217)	(133)	(31)	(31)

87. It is noted from the above table that the key profitability parameters of the domestic industry showed improvements during the POI over the previous years. However, the profitability in terms of all key parameters such as Profit Before Tax per unit, Profit Before Interest and Tax and Return on Capital Employed have been still negative during the POI.

Employment, productivity and wages

88. Employment, productivity and wages of domestic industry over the injury period are given in the table below;

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI	Annualized POI
Employment	Nos	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	144	264	264
Wages	Rs. Lakhs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	221	248	383	306
Productivity per employee	MT/Person	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	205	450	411	411
Wages	Rs/Kg	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	38	28	28

89. It is noted that there has been an increase in the level of employment with the domestic industry and productivity per employee also improved by the POI. However, wages per unit of production have shown decline by the POI.

c) Magnitude of Dumping Margin

90. Magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped in India. The investigation has shown that dumping margin is positive in the period of investigation.

d) Inventories

91. Inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI	Annualized POI
Inventory	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	227	356	644	644

92. It is noted that inventory with the domestic industry increased by the POI.

e) Growth

93. The Authority notes that growth of the domestic industry with regard to key volume and profitability parameters have been positive during the POI as can be seen from the table below;

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	Annualized-POI
Production	%	122	192	67
Sales Volume Domestic	%	(22)	346	75
Capacity Utilization	%	122	192	67
Inventory	%	127	57	81
Employment	%	8	33	83
Selling Price Per Kg	%	28	(7)	24
Cost of Sales Per Kg	%	21	(55)	(10)

Return on Capital Employed	%	(117)	39	76
Profit per Unit	%	(17)	79	81
PBIT Per Unit	%	(18)	79	82

94. It is the claim of the domestic industry that the positive growth has been very abysmal. A higher market share would have enabled the domestic industry to utilize its capacity better leading to even higher growth in volume parameters. Un-dumped price would have enabled the domestic industry to realize better price leading to even higher growth in price and profitability parameters. Growth as a parameter is noted in such a context here.

f) Ability to raise capital investments

95. The domestic industry claimed that the capacities set up is yet to reach any meaningful utilization level and the negative return even after more than five years into production shows the adverse situation created by the dumped imports. It is noted that the domestic industry is a multi-product company and therefore the ability to raise capital investment may not be governed based on the performance of the product under consideration (PUC) alone though the ROCE from the investment made to produce the subject goods is noted as negative in the POI which may negatively influence the ability to raise further capital investment.

g) Factors affecting domestic prices

96. The examination of the import prices from the subject country, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market, etc. shows that the landed value of imported material from the subject country is below the selling price and cost of sales of the domestic industry, causing significant price undercutting. It is also noted that the demand for the subject goods was showing significant increase during the injury period and therefore it could not have been a factor affecting domestic prices. Thus, it can be noted that the principal factor affecting the domestic prices is the dumped imports of the subject goods from the subject country.

h) Magnitude of Injury Margin/Price Underselling

97. The Authority has determined Non-Injurious Price (NIP) for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practicing cost accountant for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilization of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.

98. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject country, the Authority has determined the landed price based on facts available.
99. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority.

Injury Margin

S. No	Country	Producer	NIP US\$/KG	Landed Value US\$/KG	Injury Margin US\$/KG	Injury Margin %	Injury Margin (Range %)
1	China PR	Shandong Kelesi New Material Technology Co., Ltd and Shanghai Sailisi Industry Development Co., Ltd. Shandong Branch	***	***	***	***	10-20
2	China PR	Any other producer	***	***	***	***	20-30

I. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

100. As per the AD Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry.

a) Volume and price of imports from third countries

101. Import information shows that there have been substantial imports of subject goods from Korea RP, USA and Japan during the POI other than subject country. In fact, the application has been filed against Japan also as a subject country. But it was noted at the time of initiation that dumping margin is negative in case of Japan. It is further noted that imports from Korea RP and USA have also been at prices higher than the subject country and the applicant claimed such prices have not caused any injury to the domestic industry. Thus, such other imports cannot be considered to have caused injury to the domestic industry.

b) Export Performance

102. The Authority has considered the data for domestic operations only for its injury analysis. In any case, there have been an increase in exports made by the domestic industry during the POI which is provided in the table below.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI	Annualized POI
Export Sales	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	3388	7526	25978	20782

c) Contraction in demand Changes in pattern of consumption

103. It is noted that the demand of the subject goods has increased over the injury period. Thus, it can be noted that the injury to the domestic industry was not due to contraction in demand to any significant level.

d) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

104. The import of the subject goods is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. No evidence has been submitted by any interested parties to suggest that the conditions of competition between the foreign and the domestic producers have undergone any change.

e) Developments in technology

105. None of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in the technology that could have caused injury to the domestic industry. It is noted that the domestic industry setup its plant recently and commenced commercial production from October 2018.

f) Changes in pattern of consumption

106. The subject goods produced by the domestic industry and that imported into India are comparable and the end users find these goods interchangeable. Possible changes in pattern of consumption are not a factor that could have caused claimed injury to the domestic industry.

g) Performance of the domestic industry with respect to other products

107. The Authority has only considered data relating only to the performance of the subject goods. Therefore, the performance of other products produced and sold is not a possible cause of injury to the domestic industry.

h) Productivity of the domestic industry

108. Productivity per employee as assessed has shown increases by the POI. Thus, the Authority notes that deterioration in productivity as such has not been any cause of injury to the domestic industry.

J. INDIAN INDUSTRY'S INTERESTS AND OTHER ISSUES**J.1. Submissions by other Interested Parties**

109. The following submissions have been made by the other interested parties during the course of the investigation;
- i. Levy of anti-dumping duty will establish a monopoly of domestic producer and will not be in the public interest.
 - ii. With the imposition of anti-dumping duty, Indian local production may result in unstable supply and customers diverting to other products. Limited and unstable Indian local production will create monopolistic situation and ruin USD 100 million product market, business and the associated jobs.
 - iii. The demand for acrylic solid surface in India has been steadily increasing, driven by various factors such as growth in the construction and interior design industries, rising disposable incomes, and evolving consumer preferences whereas the Indian producers cannot meet the Indian demand for the subject goods. There are only 4 producers of the subject goods in India having 1-2 production line each which is not sufficient to meet the Indian demand.
 - iv. China and Korea have around 10-15 production lines. Therefore, especially after covid, Indian importers realized that they cannot depend on the Indian producers entirely to meet the demand and started importing from other countries. Today more than 20 brands are active in India with OEM based imports from China and Korea. OEM mode gives lot of confidence to Indian importers and more choice for Indian consumers.
 - v. The determination of public interest leans in favour of the non-imposition of anti-dumping duty in this matter.

J.2. Submissions by the domestic industry

110. The following submissions have been made by the domestic industry during the course of the investigation;
- i. The subject goods are premium discretionary building material most commonly used for seamless countertop installations, bathroom vanity etc in commercial spaces and in some households depending on the choice of the end user. As a result, the product does not form a major cost item in such construction/end use applications. Nor this is a mass building material used for general housing purposes like traditional tiles etc.
 - ii. ADD as requested by the applicant will not create any huge impact on the users as shown in the Economic Interest Questionnaire filed by the domestic industry and the impact shall be less than 0.50% which cannot be considered as any significant effect of ADD.
 - iii. The applicant does not have access to financial information of the users to present an impact analysis as such with supporting cost/price data. However, an estimate as follows has been made considering the nature and use of the product based on the understanding of the applicant;

Particulars	Value. Rs
Estimated cost of a small sized commercial building project	10000000
Estimated requirement of subject goods (About 500 Kg)	106445

at landed price of imports @Rs212.89/Kg)	
Share of subject goods in total cost as of now	1.06%
Weighted average Injury margin of Subject country (lower of the margin as claimed) as probable ADD @Rs 67.48 per Kg As per injury margin statement in the petition.	33740
New Cost after probable ADD as estimated	140185
Share of subject goods in total cost after any ADD	1.40%
Increase in cost of end user on account of probable ADD	0.34%
Range	0.25%-0.50%

- iv. The estimate shows that ADD as requested by the applicant will not create any huge impact on the users and the impact shall be less than about 0.50% which cannot be considered as any significant effect of ADD. The users will be benefited in the long run if the applicant is allowed to establish itself in India with the help of level playing field ensured by way of ADD as requested.
- v. The users will be benefited in the long run if the applicant is allowed to exist in India with the help of level playing field ensured by way of ADD as requested. In any case, users are importing at much higher price than China PR from other countries and any ADD on China will not trigger any price increase per se.
- vi. It is a well settled principles that measures like ADD may have some impact on the end users but the same will not be burdensome in any manner and balance of convenience shall lie in arresting the injurious dumped imports which is impacting the establishment of a strong manufacturing base for this product in India. A manufacturing base in India shall ultimately be in the interest of Indian users. As of now, the users are preferring imported material on account of the dumped prices offered by them. Even after any measures, the users will only be paying fair and reasonable prices and not anything beyond that as the duties in any case cannot exceed lower of the margin of dumping and injury.
- vii. It is also pertinent to note that the ADD measures are sought only against dumped and injurious imports from China PR and substantial imports are taking place from Korea RP, Japan, USA and the users can continue to import from such sources without any ADD.
- viii. The applicant has, as a post POI development, installed additional capacities to produce the subject goods. This additional capacity was supposed to go live much earlier since the machine were purchased in 2022 itself but the process was delayed due to adverse market situation created by dumped imports. The new capacity has technically gone live in the month of March 2024, though the plant is largely idle now like the existing capacity as the pressure from dumped imports still continues. As of now India has the capacity to meet the entire demand for the subject goods and there is no demand supply gap in the post POI period and gap even during the POI was barely 5%.
- ix. It has been contended by the exporters that levy of anti-dumping duty will establish a monopoly of domestic producer and will not be in the public interest. The contention is totally baseless. There are about 6 known producers of the subject goods in total in India. It is a settled principle that ADD will not lead to monopoly. Rather, it will only arrest dumped imports enabling the domestic industry to operate under level playing and fair market conditions. India now has the capacity to meet the Indian demand on its own and the country

can be self-reliant on this product. While the demand supply gap during the POI has been about 5-10%, the gap post POI is nil. India has some excess capacity now.

J.3. Examination by the Authority

111. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.
112. The Authority considered whether imposition of anti-dumping shall have any adverse impact on the interest of the public. In order to determine such impact, the Authority weighed the impact of the imposition of duties on the availability of the goods in the Indian market, the impact on the users of the product as well as the domestic industry and the impact on the general public at large. This determination is based on the submissions and evidence submitted over the course of the present investigation.
113. The Authority issued Gazette Notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the consumers to provide relevant information with regard to the present investigation, including possible effect of anti-dumping duty on their operations. The Authority sought information on, inter-alia, interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the consumers to switch sources, effect of anti-dumping duty on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by imposition of antidumping duty.
114. It is noted that anti-dumping duty does not restrict imports, but only ensures that the imports enter the market at fair prices. Thus, the users will continue to have the broader choice and liberty to import the subject goods at fair prices, which will ensure better competition in the market.
115. The Authority had prescribed an Economic Interest Questionnaire which was sent to all interested parties to this investigation. The domestic industry and 2 responding exporters/producers submitted the Economic Interest Questionnaire, in the form and manner as prescribed by the Authority. It is noted that one of the users/importers have responded to the Economic Interest Questionnaire. In fact, none of the users/importers of the subject goods have responded in this matter. The domestic industry has provided a quantification of the potential impact of the duty but no such quantification is made by the exporters or any other parties. It is seen that the imposition of duties will not have a significant impact on the users who are primarily developers of commercial properties etc. As per information on record, the impact would be insignificant. Moreover, none of the interested parties, have demonstrated with verifiable quantified information that the imposition of anti-dumping duty shall have significant adverse impact on the subject goods. The Authority further notes that the measures may have an impact on certain users but that should be balanced against the risk of continuing unfair trade practices.
116. With regard to the contention that there is demand-supply gap for the product and any anti-dumping duty shall lead to monopoly of the domestic producer, it is noted that the imposition of anti-dumping duty does not act as a ban on imports. There are about 6 producers of subject goods in India. The purpose of imposition of antidumping duty, in general, is to address the issue of trade distortion caused by the unfair trade practices in order to re-establish the situation of open and fair competition. In any case, the Authority notes that if there is a demand supply gap in the country, the foreign producers can certainly fill the gap in the

country by exporting the product at a fair and un-dumped price. However, existence of demand supply gap does not justify dumping of the product. With regard to impact on user industry, the domestic industry has quantified the impact of anti-dumping duty on the end users as less than 1%. The other interested parties have not quantified the impact of the anti-dumping duty on the end users nor there is any response filed by any of the actual users. Further, the Authority notes the submission of the domestic industry that the subject goods are premium and discretionary building material primarily used in commercial properties and the share of the subject goods in overall construction is very minuscule in view of the nature of the product in question. The subject goods have very niche uses.

117. With regard to the contention that with the imposition of anti-dumping duty, Indian local production may result in unstable supply and customers diverting to other products, the Authority notes that there is adequate supply capacity among domestic and foreign producers from non-subject countries .
118. With regard to the claim that China and Korea have around 10-15 production lines and today more than 20 brands are active in India with OEM based imports from China and Korea, the Authority notes that ADD will not restrict the choices available to the users in any manner but at the same time will remove the injury being caused to the Indian producers from an unfair trade practice of dumping being followed by foreign producers. Also, large scale production undertaken in foreign countries is not any justification for exports to India at dumped levels. It is also notable that imports from Korea RP have been at higher price and the applicant has not claimed any injury from such imports.

K. POST DISCLOSURE COMMENTS

K.1. Submissions of the other interested parties

119. The following submissions have been made by the other interested parties;
 - i. The Authority is requested to impose the duty based on the figures determined in the Disclosure Statement.
 - ii. The name of the producer/exporter be mentioned as “Shandong Kelesi New Material Technology Co., Ltd.” and “Shanghai Sailisi Industry Development Co., Ltd. Shandong Branch” in the final findings.

K.2. Submissions by the domestic industry

120. The following submissions have been made by the domestic industry;
 - i. The Authority may specify in the duty table in case of a positive finding that alternative descriptions such as “100% Acrylic solid surfaces, Pure Acrylic solid surfaces, Corian Sheets, Hi Macs Acrylic Sheets, Montelli Sheets made of PMMA, PMMA Sheets, Staron Solid Surface, Krypton Methyl Methacrylic Resin Solid Surface Sheet, Methyl Methacrylic Resin Sheets etc. while importing the subject goods from subject country are part of the description of the subject goods. This request has been part of the petition also.
 - ii. Facts as disclosed show dumping in the present matter. However, the dumping margin determined for the producers from China PR appears very low at 0-15%. Such lower margin is only on account of very low normal value determined for China PR and insufficient adjustment from export price carried out.

- iii. The total cost of the domestic industry as claimed may be considered for determining normal value since the adjustment done for NIP is for a different purpose and under a different Annexure to the rules.
- iv. There has been significant import from Korea RP compared to Japan and in view of the same, import price from Korea RP may be considered as the basis for determination of normal value in this case. Annexure I to the rule provides for determination of normal value in case of NME country and price from a market economy third country to other countries, including India can be the basis for normal value. Even as per the hierarchy under Para 7 of Annexure I to the rules, this option comes first.
- v. The export price is required to be adjusted by 4% to account for the difference in VAT rate refund and VAT paid. This has a direct bearing on the comparability of the product at ex-factory level.
- vi. Apart from adjustment for VAT difference, adjustments from export price needs to be done for the purpose of net export price considering secondary packing cost since the secondary packing cost of the domestic industry is not allowed as a permissible expense.
- vii. Even after improvements, the situation of the domestic industry has been in negative in terms of profitability parameters and the performance in terms of volume parameters have been much lower than the expectations and projections of the domestic industry. Material injury as per the rule is, thus, very evident.
- viii. The dumped imports entering India are undercutting the price of domestic industry and price suppression effects are also very evident. Such prices have also been below the cost of sales and NIP of the domestic industry leading to a positive injury margin showing the graveness of the impacts on dumping on the domestic industry.
- ix. Facts as disclosed show that the injury caused to the domestic industry has been on account of dumped imports alone.
- x. Indian producers can meet the demand for the product in India and the impact of the ADD as sought shall be very meager on the users. However, the current market share of the domestic industry is very miniscule and the situation will aggravate if the ADD is not levied.
- xi. India has capacity to meet entire Indian demand in the post POI period and the product has the potential to attract more investment and India may see more producers coming up in this robust product should there be a conducive market situation available in India. Even currently, with 5 producers and capacity to meet the entire Indian demand, the domestic manufacturing base is very promising and robust and the ADD will help the Indian producers to overcome the injury created by dumped imports. As of now dumped imports command a major share of a very prudent market for the product in India and the Indian producers deserve their fair share having made significant investments to produce the product in India.

K.3. Examination by the Authority

121. The Authority has examined the post disclosure comments made by the domestic industry and other interested parties. It is noted that comments which are reiterations and have already been suitably examined and adequately addressed in the relevant paras of the final findings, are not being repeated in the post-disclosure examination by the Authority for the sake of brevity. The

issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the domestic industry and considered relevant by the Authority have been examined as under:

- i. With regard to the claim the dumping margin determined is low, the Authority notes that the dumping margin has been determined by following the mandates of Annexure I to the rules and also the consistent practices of the Authority. All the facts considered in this regard have been disclosed. However, no factual error in the determination is pointed out.
- ii. With regard to the claim that normal value in the case of China PR must be determined based on import price from Korea RP, the Authority notes that no such submission has been made during the course of the investigation and such a request cannot be accepted at this stage.
- iii. With regard to adjustments in terms of unpaid VAT and also secondary packing, the Authority notes that due adjustments as per the facts available have already been made and the details of the same have already been disclosed. Even the claims made post-disclosure are not supported with any evidence and cannot be considered.

L. CONCLUSION AND RECOMMENDATION

122. Having regard to the contentions raised, information provided, submissions made by the interested parties and facts available before the Authority, as recorded above, and on the basis of the above analysis of dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority concludes as follows:

- i. The product under consideration is “Acrylic Solid Surfaces” originating in or exported from China PR. The below products are not covered in the scope of PUC for the purpose of the present investigation;
 - a) Pure acrylic sheets.
 - b) Acrylic laminates and PET/PVC films for furniture decoration and vehicle wrapping.
 - c) Polyester solid surface sheets.
 - d) Modified Acrylic Solid Surfaces.
- ii. Imports of the subject product shows that the importers have used descriptions such as 100% Acrylic solid surfaces, Pure Acrylic solid surfaces, Corian Sheets, Hi Macs Acrylic Sheets, Montelli Sheets made of PMMA, PMMA Sheets, Staron Solid Surface, Krion Methyl Methacrylic Resin Solid Surface Sheet, Methyl Methacrylic Resin Sheets etc while importing the subject goods from subject country. Such alternative names used are part of the description of the subject goods.
- iii. The product under consideration covers Acrylic Solid Surfaces irrespective of their thicknesses, length, width, color and design and the unit of measurement considered is weight of the product reported in Kilograms/Tons (Kg/MT).
- iv. The product under consideration is classified under Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975 pertaining to Plastics and articles thereof and further under subheading 392051 which pertains to poly (methyl methacrylate) sheet which is not a dedicated classification for the subject goods. Imports of the subject goods have been reported under subheadings 39205111, 39205119, 39205199, 39206390, 39219039, 39269069 and 35069999 as claimed in the application. The customs tariff heading is indicative only and is not binding on the scope of the product.
- v. The Authority provided opportunity to the interested parties to provide proposals, if any, on PCN methodology. However, no proposals were received. The comments on scope of PUC

received from various interested parties have been addressed based on the facts made available and thereafter the scope of the PUC have been notified to the interested parties.

- vi. The goods produced by the domestic industry is like articles to the subject goods being imported from the subject country in terms of Rule 2 (d) of the AD Rules.
- vii. The application for initiation of the anti-dumping investigation against the imports of the subject goods from China PR was filed by M/s Stylam Industries Limited. The applicant did not import the subject goods from the subject country during the period of investigation/injury period and is also not related to any of the exporters/importers of the subject product. Apart from the applicant, there are 5 more other producers of subject goods in India.
- viii. While the applicant estimated the total Indian production by quantifying the production of other producers on an estimated basis, none of the interested parties provided any evidence of gross Indian production. There is no published information with regard to the production and sales of the subject goods in India. Hence, in addition to notifying initiation of the investigation in the official Gazette and on the DGTR website, the Authority wrote to the various entities identified by the interested parties, seeking information on their production, imports and any other information they may deem relevant. But no such information has been made available by any of the interested parties.
- ix. Based on information on record, the Authority has determined that the production by the applicant constituted 75-85% of Indian production. The Authority has therefore determined that the applicant constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and meets the criteria for standing as per Rule 5(3).
- x. The Authority is satisfied with the confidentiality claim made by the interested parties and has accepted information provided by the interested parties on a confidential basis.
- xi. A producer of the subject goods namely Shandong Kelesi New Material Technology Co., Ltd along with Shanghai Sailisi Industry Development Co., Ltd (Trader) registered themselves in the present investigation and filed a response to the prescribed exporter's questionnaire. Individual margin is determined for the said producer based on its response.
- xii. Considering the normal value and export price determined, the dumping margin for the subject goods from China PR is positive, more than de minimis and significant for non-participating producers from the subject country.
- xiii. Demand for the subject goods in India during the POI has increased over the base year and also over the immediate previous year.
- xiv. Dumped imports in relative terms to consumption has increased by the POI in comparison to the base year and also the immediate previous year. However, dumped imports in relation to production in India has declined between the POI and the base year but increased between the POI and the immediate previous year.
- xv. Imports of subject goods from the subject country have been entering Indian market at a price below the net sales realization of the domestic industry, resulting in positive price undercutting. Price undercutting have been at significant levels during the POI.
- xvi. There is no price depression or suppression. However, the landed price of imports has been significantly lower than the cost of sales and selling price of the domestic industry during the POI.

- xvii. As regards the effect of such dumped imports on the economic parameters of the domestic industry, the Authority has reached the following conclusion:
- The volume parameters of the domestic industry in terms of capacity utilization, production and sales increased between base year and the POI. However, inventory level of the domestic industry also increased in the same period.
 - Capacity of the domestic industry remained constant during the injury period. But the domestic industry had significant unutilized capacity during the POI even when the demand for the product increased.
 - Market share of the imports of subject goods from subject country and also market share of the domestic industry has increased between the base year and the POI. However, subject imports accounted for a very high market share in absolute terms in comparison to the market share held by the domestic industry by the POI.
 - Profitability in terms of PBT, PBIT and ROCE remained negative during the POI even though there has been increases in these parameters between the base year and the POI. Even cash profit has been only slightly positive during the POI. Such losses on core profitability parameters during the POI show significant adverse impact on profitability of the domestic industry.
 - The domestic industry has suffered material injury.
 - Considering the non-injurious price determined by the Authority and the landed price of subject imports, it is seen that the injury margin is positive and significant.
 - Non-attribution analysis shows that no other factor has caused injury to the domestic industry, and the domestic industry has suffered material injury as a result of the dumped imports of the subject goods.
 - The Authority examined the impact of anti-dumping duty on the consumers. It is seen that the subject goods are premium building material primarily used in commercial real estate development and the imposition of anti-dumping duties would not have any significant adverse impact on such end consumers.
123. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury, and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of the anti-dumping duty is required to offset the dumping and consequent injury. The Authority considers it necessary to recommend the imposition of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.
124. Having regard to the lesser duty rule followed, the Authority recommends imposition of an anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury on imports of subject goods originating in or exported from the subject country, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of the anti-dumping duty on the imports of subject goods originating in or exported from the subject country, for a period of 5 years, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Column 7 of the duty table appended below.

Duty Table

S N	Heading/ Subheading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	UoM	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

1	39205111, 39205119, 39205199, 39206390, 39219039, 39269069, 35069999.	Acrylic Solid Surfaces*	China PR	Any including China PR	Shandong Kelesi New Material Technology Co., Ltd and Shanghai Sailisi Industry Development Co., Ltd. Shandong Branch	NIL	Kg	USD
2	-do-	-do-	China PR	Any Country including China PR	Any other producer excluding producer mentioned at Sr. No. 1 above.	0.18	Kg	USD
3	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	0.18	Kg	USD

**Covers alternative descriptions such as 100% Acrylic solid surfaces, Pure Acrylic solid surfaces, Corian Sheets, Hi Macs Acrylic Sheets, Montelli Sheets made of PMMA, PMMA Sheets, Staron Solid Surface, Krion Methyl Methacrylic Resin Solid Surface Sheet, Methyl Methacrylic Resin Sheets. The below products are not covered in the scope of PUC for the purpose of the present investigation;*

- a) Pure acrylic sheets*
- b) Acrylic laminates and PET/PVC films for furniture decoration and vehicle wrapping*
- c) Polyester solid surface sheets*
- d) Modified Acrylic Solid Surfaces*

M. FURTHER PROCEDURE

125. An appeal against the determination of the Authority in these final findings shall lie before the Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Customs Tariff Act.

DARPAN JAIN, Designated Authority